राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 8 अंक 137

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, गुरुवार, 24 अक्टूबर, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

साक्षी के आरोप पर बोलीं बबीता, किताब के चक्कर में ईमान बेच गईं

>> 12

जागरण विशेष

स्वावलंबी बनने के साथ रोजगार भी दे रहीं महिलाएं

उत्तरकाशी: उत्तरकाशी में तुल्याड़ा मल्ली गांव की महिलाएं एलईडी व झालर सहित अनेक प्रकार के उत्पाद बना लाभ अर्जित कर रहीं हैं। दूसरे गांव की महिलाओं को भी रोजगार दे रहीं हैं।

● पेज-7

संपादकीय

राजनीतिक लड़ाई का मोहरा बनते कारोबारी: जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नवाचार और उद्यमशीलता सम्मान करने वाली संस्कृति को बढ़ावा देना अनिवार्य है। **गौरव वल्लभ** का आलेख।

अलग माहौल वाले विधानसभा चुनाव: महाराष्ट्र और झारखंड में सीटों के बंटवारे पर जो खींचतान हुई, उससे आइएनडीआइए की एका की पोल ही खुली। **अवधेश कुमार** का दृष्टिकोण।

● पेज-8

विमर्श

समझौते का स्वागत हो सजगता भी रहे कायम: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) पर पेट्रोलिंग व्यवस्था संबंधी समझौता हो गया है। फिर भी चीन के प्रति सजगता बरतने की आवश्यकता दर्शा रही हैं, **डा. अनिता राठौर**।

राजनीति में भाजपा का नवाचार: भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान रहा है, जिसे विश्लेषित कर रही है, **धनंजय प्रताप सिंह** की डायरी।

● पेज-9

सप्तरंग

तकनीक की दुनिया का

एआइ से बदल रही फैशन की दुनिया

कैसे पहचानें सही और वैध एप

● पेज-13

अब क्रिकेट की बारी

आज का मैच (दूसरा टेस्ट)

भारत vs न्यूजीलैंड	स्थान
सुबह 9:30 बजे से	पुणे

प्रसारण: स्पोर्ट्स 18, जियो सिनेमा

श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्वामित्व विवाद: सभी 15 वादों की एक साथ सुनवाई का रास्ता साफ

प्रयागराज: मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि के स्वामित्व संबंधी सभी 15 सिविल वादों की इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने बुधवार को उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का वह रिकाल एप्लीकेशन खारिज कर दिया, जिसमें एक साथ सुनवाई का 11 जनवरी, 2024 का आदेश वापस लेने की मांग की गई थी। कोर्ट ने 16 अक्टूबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिविल वाद बिंदु तय करने सहित अन्य अर्जियों की सुनवाई छह नवंबर को होगी। (पेज-6)

पांच वर्ष बाद हुई मोदी और चिनफिंग की मुलाकात, पिघली रिश्तों पर जमी बर्फ

रूस में हुई द्विपक्षीय बैठक, एलएसी पर समझौते का दोनों नेताओं ने किया स्वागत

जयप्रकाश रंजन ● जागरण

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की बहुप्रतीक्षित बैठक बुधवार देर शाम रूस के शहर कजान में संपन्न हुई। यह दोनों नेताओं की नवंबर, 2019 के बाद पहली द्विपक्षीय प्रतिनिधि स्तर की बैठक थी जिसमें भारत-चीन के बीच स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई, पूर्वी लद्दाख स्थित एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए 21 अक्टूबर को हुए समझौते का स्वागत किया गया और अप्रैल, 2020 में चीनी सैनिकों की पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ से रिश्तों में आए तनाव को खत्म करते हुए द्विपक्षीय रिश्तों को शांतिपूर्ण व स्थिर बनाने की नई शुरुआत करने पर सहमति बनी।

मोदी और चिनफिंग ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की पांच वर्षों से स्थगित वार्ता पुनः शुरू करने का निर्देश दिया। यह फैसला भी हुआ कि सीमा पर शांति स्थापित करने और द्विपक्षीय संबंधों के दूसरे आयामों को सामान्य बनाने के लिए विदेश मंत्रियों तथा अफसरों के बीच वार्ता शुरू की जाए। इसमें कैलास मानसरोवर को भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए पुनः खोले जाने पर भी बात होगी।

- सीमा विवाद सुलझाने के लिए डोभाल और वांग यी की फिर शुरू होगी वार्ता
- कैलास मानसरोवर को भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए फिर खोलने पर भी होगी बात
- अप्रैल, 2020 में चीनी सैनिकों की गलवन में घुसपैठ से आ गया था रिश्तों में तनाव
- एलएसी के मुद्दों पर मतभिन्नता से सीमा पर शांति को नहीं होने देना चाहिए खतरा : मोदी

रूस के कजान में बुधवार को द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग। एएनआइ

> भारत-चीन के संबंधों का महत्व सिर्फ हमारे लोगों के लिए ही नहीं है। वैश्विक शांति व स्थिरता के लिए भी हमारे संबंध अहम हैं। सीमा पर गत चार वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का स्वागत है। शांति व स्थिरता बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। परस्पर भरोसा, आदर और संवेदनाओं का ख्याल रखना हमारे संबंधों का आयाम होना चाहिए।
>
> **- नरेन्द्र मोदी, पीएम** (चिनफिंग से मुलाकात के दौरान)

> दोनों देशों के लोग और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस बैठक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। दोनों पक्षों के लिए अधिक संवाद और सहयोग करना, मतभेदों तथा असहमतियों से निपटना व एक-दूसरे की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करना अहम है।
>
> **-शी चिनफिंग, चीन के राष्ट्रपति**

मोदी-चिनफिंग बैठक की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा, 'दोनों नेताओं ने सीमा पर जारी स्थिति के समाधान के लिए कूटनीतिक व सैन्य स्तर पर हुई वार्ता के बाद किए गए समझौते का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि एलएसी से जुड़े मुद्दों पर मतभिन्नता से सीमा पर अमन व शांति को खतरा नहीं होने देना चाहिए। इस संदर्भ में दोनों देश मानते हैं कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता को अहम भूमिका निभानी है। इसके बाद मोदी व चिनफिंग ने दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों को शीघ्र वार्ता शुरू करने का निर्देश दिया।' इस वार्ता में भारत की अगुआई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन का प्रतिनिधित्व उनके विदेश मंत्री वांग यी करते हैं। यह वार्ता वर्ष 2003 में शुरू हुई थी, ताकि दोनों देश सीमा विवाद का स्थायी और स्थिर हल निकाल सकें। इसकी अंतिम बैठक दिसंबर, 2019 में हुई थी। मिसरी ने उम्मीद जताई कि नए निर्देश के बाद जल्द ही इनकी बैठक होगी।

पहले 23 स्तरों पर हो रही थीं वार्ताएं पेज>>3

आतंकवाद पर दोहरे मापदंड का कोई स्थान नहीं : मोदी

नई दिल्ली: पीएम नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर वैश्विक आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों को दूसरे देशों से मिल रहे आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर दुनिया का ध्यान आकर्षित कराया है। रूस के शहर कजान में ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी ने चीन, रूस, यूएई जैसे देशों से आह्वान किया कि आतंकवाद और टेरर फंडिंग की समस्या से निपटने के लिए सभी देशों को एकमत होकर दृढ़ता से सहयोग करना होगा। मोदी ने साफ कहा कि ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। (पेज-3)

पराली पर सिर्फ आंखों में धूल झोंक रही सरकारें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वायु प्रदूषण को काबू करने में ढिलाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा व पंजाब सरकारों को कड़ी फटकार लगाई। कहा- 'पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर दोनों सरकारें सिर्फ आंखों में धूल झोंक रही हैं, गंभीर नहीं हैं। वे पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं करतीं। कुछ मामलों में केवल नाममात्र का जुर्माना वसूलती हैं। आखिर सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही?'

जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पर्यावरण कानूनों को दंतहीन बनाए जाने पर केंद्र सरकार की भी खिंचाई की। कोर्ट ने कहा, पर्यावरण कानून की धारा 15 में संशोधन करके अभियोजन की जगह पेनाल्टी कर दी गई है और उसे भी तय करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति और तंत्र नहीं स्थापित हुआ है। इस तरह तो ये दंतहीन हो गया है। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हो सकती तो वो खुले घूमेंगे ही। इसके अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों को लागू न करने वाले राज्य के अफसरों के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई न किए जाने पर भी कोर्ट ने आयोग को आड़े हाथों लिया। हालांकि केंद्र की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि पर्यावरण कानून के मुताबिक 10 दिन के भीतर पूरा तंत्र सृजित हो जाएगा। अफसरों पर कार्रवाई पर भाटी ने कहा, उन्हें कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

- सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को लगाई कड़ी फटकार
- कहा- दोनों राज्य सरकारें गंभीर नहीं, क्यों नहीं बरती जा रही सख्ती
- पर्यावरण कानूनों को दंतहीन बनाने के लिए केंद्र की भी खिंचाई की

कोर्ट के आदेश पर पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव बुधवार को कोर्ट में पेश हुए और पराली जलाने से रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। हालांकि कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय होना चाहिए। दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण और पूर्व आदेशों को लागू करने के मुद्दे पर चार नवंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने दिल्ली सहित एनसीआर के राज्यों से पूर्व आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है।

प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार पेज>>6

बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन घेरा

- राष्ट्रपति को पद छोड़ने के लिए सात दिनों का अल्टीमेटम दिया
- बैरिकेड तोड़ने से रोकने के लिए चलाई गई गोलियों में दो घायल
- अंतरिम सरकार ने कहा, राष्ट्रपति को हटाने पर अभी कोई निर्णय नहीं

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के त्यागपत्र की मांग के साथ ढाका में राष्ट्रपति भवन के सामने लगे बैरिकेड पर चढ़कर नारे लगाते प्रदर्शनकारी। रायटर

ढाका, एएनआइ: बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को पांच अगस्त को उखाड़ फेंकने के बाद अब छात्रों ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। उन्होंने बंगभवन को घेर लिया और पद छोड़ने के लिए सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है। टीवी फुटेज में प्रदर्शनकारियों को पुलिस के साथ हाथापाई करते दिखाया गया है। बीते सप्ताह एक साक्षात्कार में शहाबुद्दीन ने कहा था कि उनके पास देश छोड़ने से पहले हसीना के पीएम पद से इस्तीफे का कोई दस्तावेजी सुबूत नहीं है। इसके बाद छात्र भड़क उठे। वहीं, अंतरिम सरकार ने कहा, उसने अभी राष्ट्रपति को हटाने पर निर्णय नहीं लिया है।

सूत्रों के अनुसार, जब सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन के बैरिकेड तोड़ने से रोकने के लिए गोलियां चलाईं तो दो लोग घायल हो गए। हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए प्रयोग किए गए ग्रेनेड से तीसरा व्यक्ति घायल हो गया। प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रपति आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्य द्वार पर बैरिकेड्स के साथ कंटीले तारों की बाड़ लगाई गई है। बख्तरबंद वाहन, वाटर कैनन व दंगा नियंत्रण वाहनों को तैयार रखा गया है।

छात्रों की मांग नया संविधान बनाया जाए

विरोध कर रहे छात्रों ने मांग की है कि 1972 में लिखे गए संविधान को खत्म किया जाए और 2024 के संदर्भ में नया संविधान बनाया जाए। छात्रों ने अवामी लीग के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना के नेतृत्व में 2014, 2018 और 2024 में हुए चुनावों को अवैध घोषित किया जाना चाहिए और इन चुनावों में जीत हासिल करने वाले संसद सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। छात्र आंदोलन के समन्वयकों में से एक हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि यदि सरकार इस सप्ताह तक मांगों को पूरा करने में विफल रही, तो हम पूरी ताकत के साथ सड़कों पर फिर से उतरेंगे।

विमानों को धमकी मामले में एक्स पर बरसा केंद्र

नई दिल्ली, आइएएनएस : पिछले कुछ समय से भारतीय कंपनियों के विमानों को लगातार बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। इनमें से कई धमकियां एलन मस्क के स्वामित्व वाले इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स के जरिये दी गई हैं। अब सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स को फटकार लगाई है और पूछा है कि इस तरह की अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ज्ञात हो, एक्स (पूर्व में ट्विटर) के साथ भारत सरकार के संबंधों में पहले भी तल्खी रही है। विवादित पोस्ट को हटाने के मुद्दे पर सरकार एक्स के खिलाफ अदालत तक का दरवाजा खटखटा चुकी है। सरकार एक्स के अधिकारियों को आगाह कर चुकी है कि उनको स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा।

विमानों को बम की धमकियों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव संकेत एस भोंडवे की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक बुलाई। इस बैठक में विमानन कंपनियों और एक्स तथा मेटा जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान आइटी मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि एक्स का कृत्य अपराध को बढ़ावा देने जैसा है। उन्होंने एक्स के प्रतिनिधियों से सवाल किया कि इस तरह की खतरनाक अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पिछले कुछ दिनों से दी जा रही आनलाइन धमकियों ने यात्रियों में दहशत पैदा कर दी है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। फर्जी काल के बाद कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को डायवर्ट किया गया और आपात लैंडिंग करानी पड़ी। इससे विमानन कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित लगभग डेढ़ सौ उड़ानों को बम की धमकियां मिली हैं। मंगलवार को इंडिगो, विस्तारा और एअर इंडिया द्वारा संचालित 30 उड़ानों को ऐसी धमकियां मिलीं।

बताते चलें, विमानों में बम होने की फर्जी धमकी देने वाले आरोपित सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बन गए हैं। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने कुछ इंटरनेट मीडिया हैंडल और ईमेल पतों की जानकारी हासिल करने के लिए एक्स और हाटमेल से संपर्क किया है। इन धमकियों के लिए जिम्मेदार अपराधी अत्यधिक सुरक्षित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग कर रहे हैं, जिससे अकाउंट की उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल होता है। विशेषज्ञों का दावा है कि आरोपित को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म, सुरक्षा एजेंसियों व वीपीएन प्रदाताओं जैसे भागीदारों के सहयोग से ही गिरफ्तार किया जा सकता है।

आइटी मंत्रालय ने कहा, एक्स अधिकारियों का कृत्य अपराध को बढ़ावा देने जैसा

- सरकार ने विमानन कंपनियों और इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के अधिकारियों की बुलाई बैठक

महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव और पवार 85-85 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

मुंबई: महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो गया है। शिवसेना (उद्धव), राकांपा (शरद) व कांग्रेस 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 18 सीटें छोटे दलों को मिलेंगी। 15 पर बाद में निर्णय होगा। (पेज-4)

पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय जांच पर सार्थक जवाब देही चाहता है अमेरिका

वाशिंगटन: अमेरिका ने कहा है कि वह अपनी सरजमीं पर सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश की भारत द्वारा की जा रही जांच के नतीजों पर सार्थक जवाबदेही चाहता है। (पेज-11)

आज ओडिशा पहुंचेगा 'दाना' तूफान

भुवनेश्वर: ओडिशा और बंगाल में `दाना` तूफान से बचाव की व्यापक तैयारियां की गई हैं। ओडिशा में एनडीआरएफ की 288 टीमें तैनात की गई हैं। 14 जिलों से 10 लाख लोगों को सुरक्षित शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। इस तूफान का असर ओडिशा से लेकर बंगाल, बिहार और झारखंड तक दिख सकता है। पुरी में तूफान के राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच सतह से टकराने की संभावना है। (पेज-7)

तुर्किये की एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी तुसास पर आतंकी हमला

अंकारा: तुर्किये की राजधानी अंकारा में बुधवार को एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी तुसास के परिसर में आतंकी हमला हुआ। सुरक्षाकर्मियों के बदलने के दौरान हमलावर टैक्सी से परिसर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। एक ने बम विस्फोट कर दिया, जबकि अन्य परिसर में दाखिल हो गए। हमले में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में दो हमलावर मारे गए। हमले की किसी ने अब तक जिम्मेदारी नहीं ली है। (पेज-11)

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

Scan QR CODE to get UPSC Preparation Insights from VisionIAS Topper's Talk

8468022022 WWW.VISIONIAS.IN

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में from various programs of VISIONIAS

हिन्दी माध्यम टॉपर

1 AIR — ADITYA SRIVASTAVA — ABHYAAS PRELIMS 2023, 2022 & 2021, ABHYAAS MAINS 2023 & 2022

2 AIR — ANIMESH PRADHAN — ABHYAAS, ALL INDIA GS TEST, SOCIOLOGY TEST, LAKSHYA, INTERVIEW

5 AIR — RUHANI — ABHYAAS, INTERVIEW GUIDANCE

53 AIR — मोहन लाल — अभ्यास, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ इंटरव्यू गाइडेंस, मेन्स 365

लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन 2026

- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

हिन्दी माध्यम: 20 नवंबर, 8 AM

English Medium: 12 NOV, 6 PM

अधिक जानकारी, रजिस्टर या फ्री काउंसलिंग के लिए हमारे एक्सपर्ट से बात करें

विशेषज्ञों द्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन

GS मेन्स एडवांस कोर्स 2025
क्विक रिवीजन, कंटेन्ट एनरिचमेंट व सतत मूल्यांकन के लिए क्लासरूम प्रोग्राम
22 अक्टूबर | 2:30 PM

फास्ट ट्रैक कोर्स
सामान्य अध्ययन प्रीलिम्स
(UPSC प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए स्मार्ट सीलेबस कवरेज, फास्ट रिवीजन व मेंटरशिप के साथ नवाचारी क्लासरूम प्रोग्राम)
21 नवंबर | 6 PM

DELHI: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, Delhi | CONTACT: 8468022022, 9019066066
GTB Nagar Enquiry and Classroom Centre, Above GTB Nagar Metro Station Gate No. 2, Delhi - 110009

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

नई सुविधा

केंद्र सरकार आज से देगी पंचायत स्तर पर हर घंटे का मौसम अपडेट, देशभर की ग्राम पंचायतों के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवा शुरू करेगा केंद्र, मौसम की पूर्व सूचना से अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकेंगे किसान

ताकि किसानों की मेहनत का एक-एक दाना हो सके सुरक्षित

नई दिल्ली, प्रेट्र : कल्पना कीजिए कि कोई किसान अपने फसलों की सिंचाई करने जा रहा हो और उसे यह जानकारी मिल जाए कि अगले कुछ घंटों में वर्षा होने वाली है, तो उसे कितनी राहत मिलेगी? उसका सिंचाई का सारा खर्च बच जाएगा। इसी तरह फसल तैयार हो जाने के बाद यदि उसे कुछ घंटों में आंधी-तूफान आने या वर्षा होने का पता चल जाए, तो वह समय रहते अपने एक-एक दाने की सुरक्षा कर सकेगा। इस समय किसानों को इस तरह से अलर्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं है, पर केंद्र सरकार गुरुवार से ग्राम पंचायत स्तर पर हर घंटे मौसम का अपडेट देगी। पंचायतीराज मंत्रालय ग्राम पंचायतों के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को पांच दिनों का दैनिक मौसम पूर्वानुमान मिलेगा। खेती-किसानी के अलावा आपदा प्रबंधन में भी इससे मदद मिलेगी।

मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से शुरू की जाने वाली मौसम पूर्वानुमान सेवा से ग्राम पंचायतें प्रति घंटे मौसम पूर्वानुमान की जांच कर सकेंगी। इससे देशभर के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पंचायतीराज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में गुरुवार को यह सेवा शुरू कर दी जाएगी।

पंचायतीराज मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार के 100 दिनों के एजेंडे के हिस्से के रूप में यह पहल जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत बनाने, दीर्घकालिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, ग्रामीण आबादी को अधिक जलवायु अनुकूल बनाने और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर साबित होगी। यह पहली बार है कि स्थानीय मौसम पूर्वानुमान ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध होगा। इसके लिए मौसम विभाग के विस्तारित सेंसर कवरेज का सहयोग मिलेगा।

कहां मिलेगा मौसम का पूर्वानुमान पेज>>6

इन डिजिटल मंचों को जानें

- ई-ग्रामस्वराज पोर्टल को पंचायतों में डिजिटलीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसका लक्ष्य विकेंद्रित प्लानिंग, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य-आधारित अकाउंटिंग में पारदर्शिता लाना है।
- मेरी पंचायत एप पंचायतीराज मंत्रालय का आधिकारिक एप है। यह नागरिकों को स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने और अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाने की अनुमति देकर सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है।

प्रतीकात्मक

- ग्राम मानचित्र भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य उन्नत भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) के माध्यम से ग्रामीण शासन के डिजिटल परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना है।

****

64 प्रतिशत हिस्सा प्रदूषण में दिल्ली शहर के बाहरी स्रोतों से आता है पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) 2.5 में। सीईईडब्ल्यू के अनुसार, इन स्रोतों में फसल अवशेष जलाना और गर्मी (हीटिंग) व खाना पकाने के लिए बायोमास जलाना शामिल है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 24 अक्टूबर, 2024

आज का मौसम

आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
24 अक्टूबर	33.0	19.0
25 अक्टूबर	34.0	19.0
नोएडा		
24 अक्टूबर	34.0	21.0
25 अक्टूबर	34.0	20.0
गुरुग्राम		
24 अक्टूबर	35.0	19.0
25 अक्टूबर	35.0	19.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

एयरपोर्ट से दो किमी के दायरे में हाट एयर बैलून पर प्रतिबंध

नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट के नजदीक दो किलोमीटर के दायरे में हाट एयर बैलून, लालटेन काइट्स की उड़ान पर प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध 21 अक्टूबर से 19 दिसंबर तक के लिए लगाया गया है। दरअसल, त्योहारों के इस मौसम में विशेषकर दीवाली के दौरान हाट एयर बैलून या लालटेन काइट्स के उड़ाए जाने की संभावना काफी रहती है। एयरपोर्ट के आसपास उड़ानों की ऊंचाई कम होने के कारण हादसे की आशंका न हो, इसके लिए ही यह प्रतिबंध पुलिस की ओर से लगाया गया है। (जासं)

अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली: आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई बुधवार को टल गई। मामले से जुड़े मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित होने की जानकारी होने पर न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने सुनवाई 22 जनवरी के लिए स्थगित कर दी। केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी नौवें समन के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। (जासं)

विभव को अप्रमाणित दस्तावेज की सूची उपलब्ध कराए पुलिस

नई दिल्ली: अदालत ने राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस को पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार को अप्रमाणित दस्तावेज की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कहा कि अभियोजन पक्ष को आरोपित को अप्रमाणित दस्तावेज के साथ-साथ ऐसे दस्तावेज जिनका मुकदमे में इस्तेमाल नहीं किया गया, उनकी सूची देनी होगी। (जासं)

दिल्ली के प्रदूषण पर एलजी ने आतिशी को लिखा पत्र

वीके सक्सेना ने कहा, प्रदूषण के 26% कारणों पर हमारा नियंत्रण नहीं, लेकिन 74 % की रोकथाम हमारे हाथ में है

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर एलजी वीके सक्सेना ने बुधवार को मुख्यमंत्री आतिशी को चार पेज का एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कुल 16 बिंदुओं में अपनी बात रखी। पत्र में उन्होंने एक बार फिर दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में चिह्नित किए जाने पर सवाल उठाया। बताया कि इस घातक प्रदूषण का लोगों के जीवन पर बहुत खतरनाक असर पड़ रहा है और इससे उनका जीवन भी कम हो रहा है। एलजी ने सीएम को कहा कि वे समय-समय पर इस मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाते रहे हैं, लेकिन कुछ हल नहीं निकला।

एलजी ने पत्र में लिखा, 'प्रिय आतिशी जी, जैसे-जैसे हम त्योहारों के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं और एक दशक पहले तक इसे ''गुलाबी सर्दी'' कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम एक बार फिर काले वायु प्रदूषण, ग्रे आसमान और उस भयानक घुटन भरे एहसास को देख रहे हैं। जब मैं आपको लिख रहा हूं, तब शहर के कई इलाकों का एक्यूआइ 400 के करीब पहुंच चुका है।' उन्होंने लिखा कि भले ही प्रदूषण के 26 प्रतिशत कारणों पर हमारा ज्यादा नियंत्रण ना हो, लेकिन शेष 74 प्रतिशत हमारे नियंत्रण में हैं। यदि सरकार चाहती, तो सरल कदम उठाकर बेहद कम लागत पर प्रभावी ढंग से इनका समाधान किया जा सकता था। इतना कहने के बाद भी मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि पड़ोसी राज्यों, खासकर हमारे उत्तर में स्थित राज्यों से आने वाला धुआं दिल्ली में स्थिति को खराब कर रहा है और यदि जरूरत पड़ी, तो मैं उनसे फिर से अनुरोध करूंगा कि वे हमारी मदद करें।'

एलजी वीके सक्सेना व आतिशी। फाइल

उन्होंने लिखा, 'मैं यह पहले भी कह चुका हूं और आपके हस्तक्षेप के लिए मैं इसे फिर से दोहराता हूं कि स्थिति को ठीक करने के लिए बस सरल उपाय करने होंगे। सड़कों की नियमित मरम्मत, फुटपाथों पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पेवरमेंट ब्लाक बिछाना, सड़कों के खुले क्षेत्रों और बीच के किनारों पर छोटी-छोटी झाड़ियां, चारा और घास लगाना, फुटपाथों पर छिद्रपूर्ण टाइलों को बिछाना, मशीनों से सड़कों की सफाई के साथ पानी से धुलाई और सड़क की धूल के लिए प्रमुख सड़कों की वैक्यूम सफाई से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।'

कृत्रिम वर्षा कराने के लिए गोपाल राय ने केंद्र को तीसरी बार लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली : दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने तीसरी बार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने दीपावली के बाद आर्टिफिशियल रेन (कृत्रिम वर्षा) के जरिये प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न विभागों की आपातकाल बैठक बुलाकर अनुमति दिलाने की मांग की है। बकौल राय, यदि एक सप्ताह के भीतर मंजूरी नहीं दिलाई गई, तो इस बार भी कृत्रिम वर्षा के जरिये प्रदूषण को कम करने का प्रयोग नहीं हो पाएगा। दिल्ली सरकार दीपावली के बाद कृत्रिम के जरिये प्रदूषण को कम करना चाह रही है।

केजरीवाल सरकार द्वारा उठाए गए उपायों से प्रदूषण में आई कमी : आप : आप ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण में 31% से अधिक की गिरावट आई है। यह उपलब्धि केजरीवाल सरकार द्वारा उठाए गए दीर्घकालिक व अल्पकालिक उपायों के कारण है। आप ने आरोप लगाया कि यूपी और हरियाणा जैसे गंभीर रूप से प्रदूषित राज्यों सहित 22 राज्यों पर शासन करने के बावजूद भाजपा प्रदूषण के खिलाफ कोई सार्थक कार्रवाई करने में पूरी तरह से विफल रही है।

पता नहीं था कि पेड़ों की कटाई के लिए लेनी होगी अनुमति : एलजी

- सुप्रीम कोर्ट को दिए शपथपत्र में एलजी ने इस बात को स्वीकारा
- राजधानी दिल्ली रिज क्षेत्र में 1,100 पेड़ों की अवैध कटाई का है मामला

नई दिल्ली, प्रेट्र: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं दी गई थी कि रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए पहले से अनुमति की जरूरत है। इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण के दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को दिए गए शपथपत्र में एलजी ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी 16 से 26 फरवरी के बीच हुई पेड़ों की कटाई के बाद हुई। उन्हें इस संबंध में जानकारी 10 जून को डीडीए उपाध्यक्ष द्वारा जारी किए गए पत्र के बाद मिली।

शपथपत्र में उन्होंने कहा कि हालांकि यह एक गलती थी, लेकिन उनके (डीडीए अधिकारियों) द्वारा किया गया कार्य प्रामाणिक और जनता की भलाई के हित में थे। 5 जुलाई 2024 को डीडीए के दोषी अधिकारियों के खिलाफ बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रावधानों के साथ दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम (डीपीटीए) के प्रावधानों के तहत एक शिकायत दर्ज की गई थी और उनके खिलाफ डीडीए द्वारा विभागीय तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि बीते 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को एक व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसमें फरवरी में दिल्ली रिज क्षेत्र में 1,100 पेड़ों की अवैध कटाई के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का विवरण दिया गया था। एलजी, डीडीए के अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि फरवरी 2024 में उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान तक आसान आवाजाही के लिए एक सड़क चौड़ीकरण परियोजना स्थल का दौरा किया था। उन्हें बताया गया था कि पेड़ों की कटाई के लिए ''सक्षम प्राधिकारी'' से अनुमति का इंतजार किया जा रहा था।

क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू होगा, सीएम ने एलजी को भेजी फाइल

विनीत त्रिपाठी, जागरण, नई दिल्ली: क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को विनियमित करने के लिए नया स्वास्थ्य कानून बनाने से संबंधित जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता उदित मलिक ने अदालत को सूचित किया कि एक्ट को लागू करने से संबंधित फाइल को सीएम ने उचित कार्यवाही के लिए उपराज्यपाल को भेज दिया है।

दिल्ली सरकार के बयान को रिकार्ड पर लेते हुए मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने बयान के लिए बाध्य है। मामले में आगे की सुनवाई 21 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ता बैजोन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता शशांक देव सुधि के माध्यम से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत प्रयोगशालाएं और डायग्नोस्टिक केंद्र अयोग्य तकनीशियनों के साथ काम कर रहे थे और मरीजों को गलत रिपोर्ट दे रहे थे। मुख्य पीठ ने न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करने पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज व स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार को आड़े हाथों लिया था। अदालत ने दोनों को जेल भेजने की चेतावनी देते हुए कहा था कि वे सरकार के सेवक हैं और बड़े अहंकार नहीं रख सकते।

अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिनके भी पानी के बिल ज्यादा आए, वो न भरें

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को महरौली विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि जिनके भी पानी के बिल ज्यादा आएं हैं वो लोग पानी के बिल मत भरें। मैं सारे बिल माफ करा दूंगा। कहा कि 10 साल में हमने कई चीजें सुधारी हैं। दिल्ली की जनता के साथ मिलकर अभी बहुत काम करने हैं। उन्होंने आप नेताओं के साथ लोगों से सीधा संवाद किया। कार्यकर्ता 'ईमानदारी की क्या पहचान, केजरीवाल और झाड़ू का निशान' के नारे लगा रहे थे। इस दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने मुझे जेल भेजकर दिल्लीवालों को खूब परेशान किया। सीवर, पानी, सड़कों के सारे काम रोक दिए। वापस आकर मैंने टाप स्पीड पर काम शुरू कर दिया है।

केजरीवाल ने लोगों से कहा कि अब मैं आ गया हूं, आप चिंता मत करना।

दिल्ली के महरौली विधानसभा में पदयात्रा के दौरान बुधवार को बच्चों से हाथ मिलाते आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सौजन्य : आप

सड़कों की मरम्मत हो रही है, सफाई, अस्पतालों में दवाइयां, टेस्ट सब शुरू करवा दिए हैं। हमारी सरकार आने से पहले दिल्ली में 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, आज बिजली 24 घंटे और मुफ्त मिल रही है। केजरीवाल महरौली विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा के लिए पहुंचे तो लोग उनसे मिलने सड़कों पर लोग आ गए। केजरीवाल ने लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं।

यमुना में बढ़ा अमोनिया, तीन जल शोधन संयंत्र से जल आपूर्ति बाधित

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने से दिल्ली में वजीराबाद, भागीरथी और सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) से जल आपूर्ति प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने वजीराबाद बैराज व डब्ल्यूटीपी का निरीक्षण करने के बाद बताया कि तीनों संयंत्रों से लगभग 40 प्रतिशत कम जल आपूर्ति हो रही है। उन्होंने दिल्ली में यमुना में प्रदूषण और खराब हो रही हवा के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। कहा, दिल्लीवालों को साफ हवा व पानी न मिले इसके लिए वह हरियाणा व उत्तर प्रदेश सरकार को हथियार के रूप में उपयोग कर रही है।

वजीराबाद डब्ल्यूटीपी से उत्तरी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में सोनिया विहार व भागीरथी डब्ल्यूटीपी से पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली में जल आपूर्ति की जाती है। आतिशी ने आरोप लगाया, दीवाली व छठ पूजा के समय जानबूझकर हरियाणा व उप्र से औद्योगिक इकाइयों का अनुपचारित गंदा पानी नदी में गिराया जा रहा है।

आरएसएस के नरेला जिला प्रचारक का अपहरण करने वाले चार गिरफ्तार

- पुलिस की भनक लगते ही बदमाशों ने पीड़ित को सोनीपत के पास छोड़ा
- अपहरण के बाद आरोपितों ने क्यूआर कोड के जरिये मांगी थी फिरौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आरएसएस के नरेला जिला प्रचारक को बदमाशों ने अपहरण कर फिरौती की मांग की। इसकी शिकायत नरेला थाना पुलिस को मिली। शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस की भनक लगते ही कार में सवार बदमाश पीड़ित को हरियाणा के सोनीपत में सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए। बाहरी-उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त निधिन वलसन ने बताया कि इस मामले में पुलिस अब तक चार आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार यह मामला संज्ञान में आते ही बाहरी-उत्तरी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और बदमाशों के भागने के दिशा और मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पीछा किया। इस मामले में नरेला थाना पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार 19 अक्टूबर की रात कुलदीप के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की शिकायत नरेला थाने में मिली। तुरंत पुलिस ने कई टीमें गठित कर कुलदीप की तलाश में जुट गई थी। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल की। 20 अक्टूबर रविवार तड़के तीन बजे कुलदीप को सोनीपत से बरामद कर लिया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 19 अक्टूबर शनिवार को अपराह्न तीन बजे जब वे कार्यालय से निकले तो सफेद स्कार्पियो में आए कई लड़कों ने उनका अपहरण कर लिया।

आरोपितों ने फिरौती के लिए पैसे को क्यूआर कोड पर भेजने के लिए कहा। पीड़ित ने कोड अपने भाई को भेजते हुए इस पर मांगी गई रकम भेजने के लिए कहा। क्यूआर कोड पर अभिषेक नाम आ रहा था। आरोपितों की पहचान प्रिंस, अभिषेक, साहिल व अन्य के रूप में हुई है। इस मामले में अन्य आरोपितों की भूमिका की जांच की जा रही है।

डीयू और जेएनयू में जल्द शुरू होंगे पीएचडी के दाखिले

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के परिणाम जारी होने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश की तैयारी शुरू हो गई है। डीयू में पीएचडी की करीब 850 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। जेएनयू में 600 से अधिक सीटें हैं। डीयू में अगले सप्ताह तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का अनुमान है।

डीयू और जेएनयू में पीएचडी के प्रवेश यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पर होने हैं। जून के मध्य में हुई नेट परीक्षा को गड़बड़ी की आंशका के बाद रद कर दिया गया था। बाद में यह परीक्षा सितंबर में हुई। जबकि जून में ही पीएचडी के दाखिले शुरू होने थे, लेकिन नेट परीक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर दाखिला प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जा सका। डीयू की प्रवेश शाखा से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, हमारी तैयारी पूरी है और एक सप्ताह में प्रवेश प्रक्रिया को शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।

आइआइटी दिल्ली में एमएससी के छात्र ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- आइआइटी अस्पताल से चल रही थी काउंसिलिंग, अंतिम मोबाइल मैसेज में कहा 'पापा कैसे हैं आप'

आइआइटी, दिल्ली के एक छात्र यश कुमार झा ने मंगलवार रात हास्टल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था और उसकी काउंसलिंग भी की जा रही थी। छात्र के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आगामी 26 अक्टूबर को उसकी 22वीं जन्मतिथि है। आइआइटी दिल्ली में इस वर्ष यह आत्महत्या की दूसरी घटना है।

पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि मंगलवार रात 11 बजे सूचना मिली कि आइआइटी में एक छात्र ने फंदा लगा लिया है। 21 वर्षीय यश कुमार झा मानविकी व सामाजिक विज्ञान विभाग में एमएससी कान्गेटिव साइंस में द्वितीय वर्ष का छात्र था। झारखंड के देवघर का यश अरावली हास्टल के डी-57 नंबर कमरे में रहता था। पुलिस पहुंची तो दरवाजा बंद था। दरवाजा तोड़ा गया तो उसका शव पंखे पर तौलिये के फंदे पर लटका था। पुलिस को यश के कमरे से शराब की बोतल, सिगरेट और दवाइयां मिली हैं।

दो महीने से अवसाद में था यश : करीब दो महीने से यश अवसाद से ग्रस्त था, जिसका उपचार भी चल रहा था। वह मंगलवार सुबह आइआइटी के अस्पताल भी गया था, जहां उसकी काउंसिलिंग हुई। उसे 29 अक्टूबर को पुनः डाक्टर के पास जाना था। हालांकि स्वजन ने उसके अवसाद में जाने का कारण नहीं बताया। यश के पिता एक महीने पहले ही देवघर जिलाधिकारी कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं। पहले सेमेस्टर में यश तीन अन्य छात्रों के साथ रहता था, लेकिन कुछ दिन से कमरे में अकेला रह रहा था।

अंतिम मोबाइल मैसेज में यश ने कहा, पापा कैसे हैं आप : आत्महत्या से कुछ घंटे पहले यश ने पिता को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि पापा कैसे हैं आप। पिता ने हाल चाल पूछा तो कहा कि थोड़ी थकान हो रही है। पिता ने गर्म पानी पीने की सलाह दी और पूछा कि पैसे मिल गए, जिसका जवाब यश ने नहीं दिया।

लिव इन पार्टनर की हथौड़ी से हत्या कर महिला पहुंची थाने, गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : भलस्वा डेरी थाना क्षेत्र में एक महिला ने पहले पेचकस और हथौड़ी से हमला कर लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी, फिर थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपित महिला को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, मृतक साहिल प्लंबर था। सात साल पहले साहिल खान की मुलाकात मुन्नी से हुई थी। इसके बाद मुन्नी अपने पति को छोड़कर 2018 से साहिल के साथ रहने लगी। इस बीच उसके पति की भी मौत हो गई। मुन्नी अपने चारों बच्चों को ससुराल में छोड़ दिया था। एक साल पहले ही महिला बच्चों को लेकर दिल्ली आई थी। बताया गया कि मुन्नी एक माह पहले बिहार के खगड़िया जिले में अपने गांव गई थी। वह रविवार को लौटकर दिल्ली आई। आरोपित मुन्नी ने पुलिस को बताया कि साहिल उसे परेशान करता था, इसलिए उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहा। साहिल इस बात के लिए राजी नहीं हुआ।

छठ पूजा से पूर्वांचल समाज को भावनात्मक रूप से जोड़ेगी भाजपा

संतोष कुमार सिंह ● जागरण

नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचल के लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही इनका राजनीतिक महत्व भी बढ़ा है। कई विधानसभा क्षेत्रों में यह चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। यही कारण है कि सभी पार्टियां इन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती हैं। पिछले दो लोकसभा चुनावों की तरह इस बार भी भाजपा इन्हें साधने में सफल रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में इनका समर्थन लेना बड़ी चुनौती है। चुनाव से पहले उन्हें अपने साथ जोड़ने का छठ पूजा भी एक अच्छा मौका है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड के लोग अब दिल्ली के राजनीतिक समीकरण को बनाने व बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यहां के 70 में से 17 विधानसभा क्षेत्रों में इन राज्यों से संबंधित मतदाताओं की संख्या 30 से 55 प्रतिशत तक है। राजनीतिक समीकरण को देखते हुए पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। मोर्चों को मजबूत करने के लिए

अगस्त में प्रदेश अध्यक्ष व प्रभारी दोनों को बदलने के बाद अब नई टीम गठित की गई है। शनिवार को पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष ओझा की अध्यक्षता में हुई बैठक में छठ पर्व की तैयारी पर चर्चा हुई।

अध्यक्ष ने पदाधिकारियों को छठ घाटों की सफाई, व्रत करने वालों को होने वाली समस्याओं के समाधान में सहयोग करने का निर्देश दिया। प्रत्येक मंडल अध्यक्षों को अपने यहां व्रत करने वालों को उपहार स्वरूप पूजन सामग्री देने के लिए सूची तैयार करने को भी कहा गया है। प्रत्येक मंडल में कम से कम 11 लोगों की सूची तैयार की जाएगी। कई मंडलों में यह काम शुरू हो गया है।

जेएनयू में फ्रेशर पार्टी में छात्रों से मारपीट, शिकायत दर्ज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में समाजशास्त्र विभाग के छात्रों की ओर से कराई गई फ्रेशर पार्टी में मारपीट हो गई। जूनियर छात्रों को दूसरे विभागों से आए छात्रों ने पीटा, जिसमें कुछ छात्र घायल हो गए। पीड़ित छात्रों ने इसकी शिकायत विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारियों और पुलिस से की है। उधर, चीफ प्राक्टर जनार्दन राजू ने कहा कि उनके पास शिकायत नहीं आई है। शिकायत आने पर उचित कदम उठाए जाएंगे।

जेएनयू के स्कूल आफ सोशल साइंस के तहत आने वाले समाजशास्त्र विभाग में मंगलवार को परास्नातक और पीएचडी छात्रों की फ्रेशर पार्टी थी। छात्रों का आरोप है कि पार्टी के दौरान दूसरे विभागों के छात्र आडिटोरियम में घुस आए और वहां मौजूद छात्राओं पर फब्तियां कसने लगे। सुरक्षाकर्मियों के हस्तक्षेप के बाद वह लौट गए। करीब दो घंटे बाद दूसरे विभागों के छात्रों ने अपने साथियों के साथ पार्टी स्थल पर पहुंचकर पार्टी कर रहे छात्रों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा।

सख्त टिप्पणी

बेदखली नोटिस के खिलाफ नेताओं के विरोध-प्रदर्शन पर हाई कोर्ट ने जताई आपत्ति, जल प्रवाह को बाधित करने वाली जंगपुरा की जेजे मद्रासी कैंप झुग्गी को हटना होगा

'नेताओं को सिर्फ चुनाव जीत सत्ता में वापसी में रुचि'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पुराने बारापुला ब्रिज क्षेत्र में कुछ लोगों को बेदखली के नोटिस दिए जाने के खिलाफ नेताओं के आंदोलन और विरोध पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आपत्ति जताई है। मामला पहले से ही अदालत में लंबित होने का बावजूद विरोध करने पर हाई कोर्ट ने कहा कि यदि परियोजना विफल हो जाती है, तो दिल्ली में फिर से बाढ़ आ जाएगी। अदालत ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पानी को यमुना नदी में बहने से रोका जा रहा है। अदालत ने कहा कि सवाल यह है कि क्या कालोनी पानी के प्रवाह को बाधित कर रही है या नहीं। साथ ही स्पष्ट कर दिया कि यदि यह पानी के प्रवाह को बाधित कर रही है, तो उसे हटना होगा।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि नेताओं की मंशा केवल चुनाव जीतना है और उन्हें शहर के बुनियादी ढांचे और स्थिति में सुधार की कोई चिंता नहीं है। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट। फाइल

के जंगपुरा में झुग्गी बस्ती के निवासियों को बेदखली के नोटिस मिलने के कुछ दिनों बाद आप और भाजपा के नेताओं ने निवासियों से मुलाकात की और उन्हें समर्थन देने का वादा किया। दोनों पार्टियों ने बेदखली नोटिस के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यमुना में पानी के प्रवाह के वास्ते रास्ता बनाने के लिए अतिक्रमण हटाना होगा, नहीं तो शहर में फिर से बाढ़ आ जाएगी। अदालत ने कहा कि अगर प्रशासन इस मुद्दे को हल करना चाहता है तो यह पांच मिनट का काम है लेकिन इसे हल करने के बजाय वे वहां राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं। अगर इरादा नहीं है, तो आप इसे अगले 50 वर्षों में भी हल नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि काम करने की इच्छाशक्ति नहीं है। पीठ ने यह टिप्पणी जेजे मद्रासी कैंप के निवासियों की याचिका पर की। लोगों ने पुनर्वास की मांग की है।

अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डुसिब) सहित अन्य अधिकारियों से इन निवासियों को अन्यत्र पुनर्वास के मुद्दे पर विचार करने को कहा। पीठ ने कहा कि अगर दिल्ली डूब गई तो नेताओं को कोई चिंता नहीं है और वे केवल चुनाव जीतने और सत्ता में वापस आने में रुचि रखते हैं। पीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा जब मामला अदालत में है तो कोई वहां जाकर आंदोलन क्यों करेगा और भाषण क्यों देगा। अदालत ने कहा कि यह पुनर्वास का एक साधारण मामला है और इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है।

****

जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने के इच्छुक नहीं : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: ऐतिहासिक जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अदालत ऐसा करने की इच्छुक नहीं है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह व न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने कहा कि वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के रुख को देखते हुए जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने के इच्छुक नहीं है। अदालत ने इसके लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में अपने नोट दाखिल करने का आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब एएसआइ ने बताया कि जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने से 'पर्याप्त प्रभाव' पड़ेगा, अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। अदालत सुहैल अहमद खान व अजय गौतम द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

एम्स से प्रत्यारोपण कर कहीं और पेड़ लगाने से नहीं दूर होगा प्रदूषण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच एक नए ब्लाक के निर्माण के लिए एम्स परिसर से 70 से अधिक पेड़ों को किसी अन्य स्थान पर प्रत्यारोपित करने के प्रस्ताव पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राथमिक आपत्ति दर्ज कराई है। अदालत ने कहा कि एम्स से पेड़ों को प्रत्यारोपित करने से दिल्ली को मदद नहीं मिलेगी। निश्चित तौर पर प्रदूषण की स्थिति को कम करने में पेड़ मदद करते हैं और यदि इन्हें जौनापुर में प्रत्यारोपित किया जाता है तो इससे लोगों को मदद नहीं मिलेगी। इस प्रस्ताव मंजूरी नहीं दी जाएगी और इसे एम्स परिसर में प्रत्यारोपित किया जाए। अदालत ने कहा कि पेड़ों को अन्य स्थान पर प्रत्यारोपण की अनुमति नहीं देगी।

पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब एम्स की तरफ से पेश हुए एक अधिकारी व

एम्स। फाइल

वास्तुकार ने कहा कि दो मीटर से अधिक परिधि वाले पांच पेड़ों को परिसर के भीतर प्रत्यारोपित किया जाएगा, बाकी को जौनापुर भेजा जाएगा। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि हवा की गुणवत्ता को देखें। पीठ ने संबंधित उप वन संरक्षक (डीसीएफ) से पेड़ों की उम्र और मोटाई का निर्धारण करने के लिए निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए एम्स प्रशासन से पूछा कि सभी पेड़ों को परिसर में ही क्यों नहीं प्रत्यारोपित किया जा रहा।

आतंकवाद पर दोहरे मापदंड का स्थान नहीं : मोदी

ब्रिक्स सम्मेलन ▶ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा- हम युद्ध नहीं, वार्ता और कूटनीति का करते हैं समर्थन

युवाओं में अतिवाद रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने पर दिया जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर वैश्विक आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों को दूसरे देशों से मिल रहे आर्थिक सहयोग (टेरर फंडिंग) के मुद्दे पर दुनिया का ध्यान आकर्षित कराया है। रूस के शहर कजान में ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने चीन, रूस, यूएई जैसे देशों से आह्वान किया कि आतंकवाद और इन्हें वित्त उपलब्ध कराने की समस्या से निपटने के लिए सभी देशों को एकमत होकर दृढ़ता से सहयोग करना होगा। मोदी ने साफ कहा कि ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। साथ ही उन्होंने युवाओं में अतिवाद को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाने पर जोर दिया। मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह ब्रिक्स के तहत सहयोग बढ़ाने को प्रतिबद्ध हैं और भारत संगठन के विस्तार का स्वागत करता है, लेकिन इस बारे में फैसला सर्वसम्मति से होना चाहिए और संस्थापक देशों की भावनाओं का आदर होना चाहिए।

भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। कजान में ब्रिक्स की दो बैठकें हुईं। एक सदस्य देशों की और दूसरी सभी आमंत्रित देशों की। दोनों बैठकें रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की अगुआई में हुई। दोनों बैठकों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। सीमित पूर्ण सत्र में उन्होंने कहा, 'एक विविध व समावेशी प्लेटफार्म के तौर पर ब्रिक्स सभी विषयों पर सकारात्मक भूमिका अदा कर सकता है। इस संदर्भ में हमारी सोच आमजन केंद्रित होनी चाहिए। हमें विश्व को यह संदेश देना चाहिए कि ब्रिक्स विभाजनकारी नहीं, जनहितकारी समूह है।' इसी संदर्भ में उन्होंने मौजूदा यूक्रेन-रूस युद्ध और पश्चिम एशिया में चल रहे संकट की तरफ भी संकेत करते हुए कहा, 'हम युद्ध नहीं, वार्ता और कूटनीति का समर्थन करते हैं। और जिस तरह हमने मिलकर कोविड जैसी चुनौती को परास्त किया, उसी तरह हम भावी पीढ़ी के सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध भविष्य के लिए नए अवसर पैदा करने में पूरी तरह सक्षम हैं।' साथ ही उन्होंने साइबर सुरक्षा और सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए वैश्विक नियम बनाने पर भी काम करने का आह्वान किया।

भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के इस मंच से वैश्विक संस्थाओं में सुधार की फिर पैरवी की और कहा कि हमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए एकमत होकर आवाज उठानी चाहिए। मोदी ने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स (विश्व बैंक आदि) में सुधार के लिए समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस संगठन (ब्रिक्स) की छवि ऐसी न बने कि हम इन संस्थाओं में सुधार नहीं, बल्कि उनकी जगह दूसरे संस्थाएं लाना चाहते हैं। ग्लोबल साउथ देशों (विकासशील व कम विकसित) की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। मुझे खुशी है कि ब्रिक्स के अंतर्गत भी इन प्रयासों को बल मिल रहा है। पिछले वर्ष अफ्रीका के देशों को ब्रिक्स से जोड़ा गया। इस वर्ष भी रूस द्वारा अनेक ग्लोबल साउथ के देशों को आमंत्रित किया गया है।' प्रधानमंत्री ने कहा, ''विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारधाराओं के संगम से बना ब्रिक्स समूह दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो सकारात्मक सहयोग को बढ़ावा देता है। हमारी विविधता, एक-दूसरे के प्रति सम्मान और आम सहमति के आधार पर आगे बढ़ने की हमारी परंपरा हमारे सहयोग का आधार है।''

इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मलेन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। इसमें तकरीबन 40 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख भी थे। मोदी ने इस सत्र में मुख्य तौर पर भारत की तरफ से ब्रिक्स के तहत इन देशों को आर्थिक विकास या सामाजिक विकास से जुड़ी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने वाली पेशकश की। उन्होंने भारत व यूएई के बीच यूपीआइ के इस्तेमाल का जिक्र करते हुए सभी देशों को यूपीए अपनाने की पेशकश की। इसी तरह से वैक्सीन व डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भारत के सफल अनुभव को साझा करने की बात कही। 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे अभियान से भी जुड़ने का आह्वान इन सभी देशों से किया। ब्रिक्स देशों के बीच वित्तीय एकरूपता लाने के प्रयासों का स्वागत करते हुए मोदी ने कहा, 'स्थानीय मुद्रा में व्यापार और सीमा पार व्यापार के भुगतान को आसान करने से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा।'

ये भी कहा

- ब्रिक्स देशों से किया यूपीआइ को अपनाने का प्रस्ताव
- डिजिटल हेल्थ को भी साझा करने की पेशकश की
- 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जुड़ने का आग्रह
- स्थानीय मुद्रा में कारोबार शुरू करने की पहल का स्वागत

रूस के कजान में बुधवार को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा (बाएं), चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग (बाएं से दूसरे), रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (मध्य में) एवं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रेट्र

उज्बेक व यूएई के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी ने चिनफिंग के अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कीं। प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ बैठक में व्यापार व सांस्कृतिक संबंधों सहित दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति नाहयान से मुलाकात पर खुशी जताई। सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश रवाना हो गए।

पहले 23 स्तरों पर हो रही थीं वार्ताएं

प्रथम पृष्ठ से आगे

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और उन्हें नए सिरे से बनाने के लिए विदेश मंत्रियों व दूसरे अधिकारियों के स्तर पर भी वार्ता शुरू की जाएगी। ज्ञात हो, अप्रैल, 2020 में चीनी सैनिकों की पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ से रिश्तों में आए तनाव से पहले भारत और चीन के बीच मंत्रियों व अधिकारियों की अगुआई में 23 स्तरों पर भिन्न-भिन्न तरह की वार्ताएं चल रही थीं। इनमें आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, विज्ञान व प्रौद्योगिकी से लेकर दोनों देशों के आम जनों को प्रभावित करने वाले कई क्षेत्रों पर बातचीत होती थी। ये सारी बंद हैं। मंत्रालय ने कहा, दोनों नेता मानते हैं कि भारत-चीन जैसे पड़ोसी और दुनिया के दो सबसे बड़े देशों के बीच स्थिर, मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों से क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं, वैश्विक शांति व समृद्धि पर सकारात्मक असर होगा। यह बहु-ध्रुवीय एशिया व विश्व बनाने के लिए जरूरी है। रिश्तों को रणनीतिक व दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखने व विकास से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने की जरूरत है।

विदेश सचिव बोले, अब भरोसा भी बढ़ेगा : विदेश सचिव मिसरी से जब पूछा गया कि क्या इस बैठक से भारत-चीन के रिश्ते सामान्य हो गए हैं तो उनका जवाब था, 'मैं यह कह सकता हूं कि गत दिनों जो समझौता हुआ है, उससे सामान्य रिश्ते बनाने का रास्ता खुल गया है। आशा है कि हमारे बीच भरोसा बढ़ेगा।' यह पूछे जाने पर कि क्या कैलास मानसरोवर को भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा तो मिसरी ने कहा, 'आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए दोनों नेताओं ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, भरोसा है कि यह मामला भी एजेंडे में होगा।'

दो सम्मेलनों में हुई थी संक्षिप्त मुलाकात : गलवन में जून, 2020 में भारत-चीन के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक बलिदान हो गए थे। संघर्ष में चीन ने अपने चार सैनिकों के मारे जाने की बात मानी थी। इसके बाद दोनों देशों ने अग्रिम मोर्चे पर हजारों सैनिक तैनात कर दिए थे। मोदी-चिनफिंग के बीच उसके बाद से द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई थी। दोनों के बीच अंतिम द्विपक्षीय वार्ता अक्टूबर, 2019 में तमिलनाडु के मामल्लपुरम में हुई थी। हालांकि दोनों नेताओं ने नवंबर, 2022 में बाली जी-20 सम्मेलन से इतर बात की थी। उन्होंने अगस्त, 2023 में जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन से इतर भी बात की थी,पर दोनों देशों ने वार्ता के अलग-अलग वर्जन जारी किए थे।

ब्रिक्स नेताओं ने दहशतगर्दी को बताया साझा खतरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आतंकवाद को 'साझा खतरा' बताते हुए ब्रिक्स नेताओं ने आतंकी विचारधारा के प्रसार, एक से दूसरे देश में आतंकियों की आवाजाही व आतंकी फंडिंग रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाने का संकल्प लिया है।

रूस के कजान शहर में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त घोषणा-पत्र में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के नजरिये का समर्थन किया गया है। सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी स्वरूप की एक स्वर में निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि इसे किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। घोषणा-पत्र के अनुसार, 'आतंकवाद एक साझा खतरा है, जिसके लिए वैश्विक व क्षेत्रीय स्तर पर देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर व्यापक व संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।' ब्रिक्स नेताओं ने राष्ट्रों की संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति पूर्ण सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर व अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप आतंकी खतरों को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। कहा, 'आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक और अनुचित है, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो और हम दोहरे मापदंडों के बिना सामूहिक कार्रवाई पर बल देते हैं।' हम

ब्रिक्स घोषणा-पत्र

- भारत के नजरिये का समर्थन, निर्णायक कदम उठाने का लिया संकल्प
- गाजा में युद्धविराम की अपील, सामूहिक हत्याओं के लिए इजरायल की निंदा

आतंकी कृत्यों के लिए उकसावे, विदेशी आतंकी लड़ाकों की भर्ती को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकियों और आतंकी समूहों के विरुद्ध कार्रवाई का आह्वान करते हैं।'

घोषणा-पत्र में यूक्रेन विवाद को लेकर बहुत कुछ तो नहीं कहा गया है, पर फलस्तीन-इजरायल के संघर्ष का विस्तार से जिक्र किया गया है और वहां अंतरराष्ट्रीय कानून लागू करने की मांग की गई है। साथ ही अलग फलस्तीन राष्ट्र को पूरा समर्थन देने की बात है। इसमें गाजा में स्थायी युद्धविराम और दोनों पक्षों के बंधकों की रिहाई की अपील की गई है। साथ ही सामूहिक हत्याओं और सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हवाई हमले के लिए इजरायल की निंदा की गई। लेबनान पर इजरायल के हमले की भी कड़ी निंदा की गई है और लेबनान व सीरिया की संप्रभुता का आदर किए जाने की बात कही है। साफ है कि घोषणा-पत्र के जरिये रूस ने राजनीतिक संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रोकने का प्रयास करें ब्रिक्स सदस्य : ईयू

रूस के कजान में बुधवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रेट्र

ब्रसेल्स, रायटर : यूरोपीय संघ (ईयू) ने बुधवार को ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हो रहे देशों से अपील की कि वे रूस से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खत्म करने को कहें। ईयू के विदेश नीति के प्रवक्ता पीटर स्टानो ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के गलत इस्तेमाल की निंदा की और कहा, रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। उन्होंने कहा, ईयू सम्मेलन में हिस्सा ले रहे यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस का समर्थन करता है। हमें भरोसा है कि वह यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए पुतिन के सामने बात पुरजोर ढंग से रखेंगे। वहीं, यूक्रेन ने कहा, सम्मेलन की घोषणा से स्पष्ट है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस द्वारा छेड़े गए युद्ध पर संगठन का कोई संयुक्त रुख नहीं है।

अपनी मुद्रा में आपसी कारोबार करेंगे ब्रिक्स देश

घोषणा-पत्र में यह भी कहा गया है कि सदस्य देश अपनी-अपनी मुद्राओं में आपसी कारोबार करने को प्राथमिकता देंगे और इसके जरिये ही कारोबार बढ़ाएंगे। साथ ही ब्रिक्स देशों के वित्तीय ढांचे को आपस में जोड़ने, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन के सेटलमेंट के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था बनाने और एक पुर्नबीमा कंपनी की स्थापना करने का अध्ययन कराने का भी फैसला किया गया है।

मुख्य बातें

- ब्रिक्स देशों के मौजूदा न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) को एक नए विकास बैंक के तौर पर विकसित किया जाएगा। स्थानीय मुद्रा में ज्यादा कर्ज देगा एनडीबी।
- वैश्विक कर्ज के बढ़ते स्तर पर चिंता। इसे एक वैश्विक समस्या के तौर पर चिह्नित करते हुए इसका समग्र तौर पर समाधान निकालने के लिए जी-20 फ्रेमवर्क को लागू करने की मांग।
- अंतरराष्ट्रीय कारोबार में मौजूदा बाधाओं को दूर करने और उन्हें हर देश के लिए समान तौर पर लागू करने का समर्थन।
- सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों को स्थानीय मुद्रा में कारोबार, भुगतान की नई व्यवस्था पर अध्ययन कर अगली बैठक में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश।
- डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के प्रभावशाली वैश्विक गवर्नेंस को बढ़ावा देने और इसमें संयुक्त राष्ट्र की अहम भूमिका का समर्थन।
- पश्चिमी प्रतिबंधों को अवैध और एकतरफा बताया जिसके वैश्विक अर्थव्यवस्था व अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़े रहे असर पर चिंता जताई।
- वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए ब्रिक्स वैक्सीन सेंटर का किया समर्थन। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने की भारत की पहल पर लिया संज्ञान।
- विकासशील देशों के लिए आगामी जलवायु सम्मेलन में अधिक धन की अपेक्षा जताई।

भविष्य के एजेंडे पर काम करेंगे भारत-जर्मनी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

फ्रांस के बाद एक दूसरा यूरोपीय देश जर्मनी अब भारत का एक विश्वस्त वैश्विक साझेदार बनने की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच शुक्रवार को होने वाली द्विपक्षीय वार्ता इस क्रम में काफी अहम है। चांसलर शोल्ज तीन दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं जो उनकी पिछले डेढ़ वर्षों में तीसरी भारत यात्रा होगी। शोल्ज गुरुवार को नई दिल्ली पहुंच जाएंगे।

यही नहीं, भारत आने से पहले ही शोल्ज की कैबिनेट ने फोकस आन इंडिया प्रपत्र को मंजूरी दी है। यह विरले ही होता है कि जर्मनी किसी देश के साथ रिश्तों की अहमियत पर कोई सरकारी प्रपत्र जारी करे। फोकस आन इंडिया में भारत को न सिर्फ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है बल्कि जर्मनी ने भारत के साथ दीर्घकालिक संबंधों को मजूबत करने का पूरा एक रोडमैप दिया है।

जर्मनी के राजदूत डा. फिलिप आकरमान ने कहा है कि यह प्रपत्र जर्मन सरकार के सभी मंत्रालयों की

- आज नई दिल्ली पहुंचेंगे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज
- शुक्रवार को होगी पीएम मोदी से द्विपक्षीय बातचीत

ओलाफ शोल्ज। फाइल

तरफ से भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को अगले मुकाम पर ले जाने की तैयारी को बताता है।

जर्मनी के राजदूत आकरमान ने बताया कि दोनों देशों के नेताओं के बीच होने वाली बातचीत का एजेंडा बहुत ही व्यापक है। शोल्ज के साथ पांच प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों का एक दल भी भारत आ रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ओलाफ शोल्ज की अगुवाई में शुक्रवार को जर्मनी-भारत अंतर सरकारी बैठक (आइजीसी) होगी। आइजीसी की बैठक हर दो वर्षों पर होती है। एक बार भारत में तो दूसरी बार जर्मनी में। जर्मनी भारत के साथ अपने आर्थिक, रक्षा व सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर खास जोर दे रहा है। जर्मनी की इच्छा भारत के साथ श्रम संबंधी समझौता करने की भी है, ताकि यहां से प्रशिक्षित श्रमिकों की आपूर्ति हो सके। इसके अलावा वह भारत में अपने शैक्षणिक संस्थानों को भी बढ़ावा दे रहा है। वह भारत से पर्यटकों को लुभाने के लिए भी कार्यक्रम चला रहा है।

फोकस आन इंडिया को लेकर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगले वर्ष भारत के साथ रणनीतिक रिश्तों की 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। ऐसे में जर्मनी की सरकार भारत के साथ भविष्य का एजेंडा तय करना चाहती है।

इस प्रपत्र में यह भी कहा गया है कि जर्मनी आम भारतीयों के साथ भारतीय कारोबारी समुदाय और मीडिया में भी जर्मनी को लेकर व्यापक जागरूकता पैदा करेगा। रक्षा व स्वच्छ ऊर्जा दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिसमें जल्द ही दोनों देशों के बीच अलग-अलग समझौते होने की उम्मीद है।

रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए यूएई की यात्रा पर पहुंचे नौसेना प्रमुख

नई दिल्ली, एएनआइ : भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा पर हैं। त्रिपाठी ने मंगलवार को नेशनल डिफेंस कालेज (एनडीसी) यूएई के अपने दौरे के दौरान ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ सईद हसन एम. अल यामाही सहित अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की।

नौसेना प्रमुख ने बातचीत के दौरान भारत और यूएई में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अनुभव साझा करने के अवसरों पर प्रकाश डाला। भारतीय नौसेना ने एक्स पोस्ट में कहा, वार्ता का विषय भारत-यूएई संबंधों, समुद्री अवसरों, क्षमता निर्माण, सूचना साझाकरण, प्रशिक्षण आदान-प्रदान और अंतरसंचालनीयता बढ़ाने पर ध्यान देना था। इस बीच भारतीय नौसेना ने बिजनेस काल के हिस्से के रूप में रूसी नौसेना के प्रशांत बेड़े से संबंधित पनडुब्बी का स्वागत किया।

चीन से एलएसी समझौते पर देश को विश्वास में ले सरकार : कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी विवाद समाप्त करने के लिए चीन के साथ बनी सहमति के बिंदुओं पर केंद्र सरकार से देश को विश्वास में लेने की बात कही है। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि चीन के साथ एलएसी विवाद पर हुए ताजा समझौते के जरिये भारत की विदेश नीति को लगे झटके का सम्मानजनक ढंग से हल निकाला जा रहा है और सैनिकों की वापसी सुनिश्चित कर मार्च 2020 जैसी स्थिति बहाल की जाएगी।

पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग की लंबे अंतराल के बाद रूस में बुधवार को हुई मुलाकात से पहले कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने एलएसी विवाद पर हुए समझौते पर जारी बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि एलएसी की यह दुखद गाथा पूरी तरह से चीन के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नासमझी का नतीजा है। 19 जून 2020 को हमारा पक्ष तब सबसे ज्यादा कमजोर हुआ, जब प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट देते हुए कहा कि 'न कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है।'

- जयराम रमेश ने कहा, समझौते के बाद सरकार की ओर से कुछ अहम सवालों का जवाब दिया जाना जरूरी

एलएसी की यह दुखद गाथा चीन के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नासमझी का नतीजा

जयराम ने कहा कि अब जब चीन के साथ एलएसी विवाद खत्म करने का समझौता हुआ है, तब जनता को विश्वास में लेते हुए सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने चाहिए। पहला सवाल कि क्या भारतीय सैनिक डेपसांग में हमारी दावे वाली लाइन से लेकर बाटलनेक जंक्शन से आगे के पांच पेट्रोलिंग पाइंट्स तक पेट्रोलिंग करने में सक्षम होंगे। जैसा कि वे पहले करने में सक्षम थे। दूसरा क्या हमारे सैनिक डेमचोक में उन तीन पेट्रोलिंग पाइंट्स तक जा पाएंगे जो चार साल से अधिक समय से हमारे दायरे से बाहर है। तीसरा क्या हमारे सैनिक पैंगोंग त्सो में फिंगर- 3 तक ही सीमित रहेंगे। जबकि पहले वे फिंगर-8 तक जा सकते थे। चौथा क्या हमारी पेट्रोलिंग टीम को गोगरा-हाट स्प्रिंग्स क्षेत्र में उन तीन पेट्रोलिंग पाइंट्स तक जाने की छूट है, जहां वे पहले जा सकते थे। पांचवा क्या भारतीय चरवाहों को एक बार फिर चुशुल में हेलमेट टाप, मुक्पा रे, रेजांग ला, रिनचेन ला, टेबल टाप और गुरुंग हिल में पारंपरिक चारागाहों तक जाने का अधिकार दिया जाएगा। छठा क्या वे 'बफर जोन' जो चीनियों को सौंप दिए गए थे, जिसमें रेजांग ला में युद्ध नायक और मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का स्मारक स्थल भी शामिल था, अब अतीत की बात है।

करतारपुर गलियारे पर समझौते बढ़ाना अहम कदम : नड्डा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि श्री करतारपुर साहिब गलियारे पर भारत-पाक के बीच समझौते को बढ़ाने पर सहमति सिख समुदाय की आध्यात्मिक आकांक्षाओं के लिए अहम कदम है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत-पाक ने अगले पांच वर्षों के लिए श्री करतारपुर साहिब गलियारे पर समझौते को बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा, प्रति तीर्थयात्री प्रति यात्रा के लिए 20 डालर सेवा शुल्क को हटाने के संबंध में पाकिस्तान से आग्रह किया गया है।

नड्डा ने एक्स पर पोस्ट में कहा, हमारे सिख भाइयों-बहनों की आध्यात्मिक आकांक्षाओं को सम्मान देने की दिशा में अहम कदम के तहत मोदी सरकार ने श्री करतारपुर साहिब गलियारा संबंधी समझौते को और पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने हमारे देश की जीवंत सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का जश्न मनाने और बढ़ावा देने वाली पहलों को प्राथमिकता दी है।

तैयारी

विश्वस्तरीय सुविधाओं को जुटाने और क्षमता निर्माण में देगा मदद, 2035 तक उच्च शिक्षा के जीईआर को पचास प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य

उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी चलाएगा लीडरशिप प्रोग्राम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में एक लीडरशिप प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी में है। जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों को न सिर्फ क्षमता निर्माण के लिए मदद की जाएगी, बल्कि उनके शोध और शैक्षिक गतिविधियों को पूरी दुनिया तक पहुंचाया भी जाएगा। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए यह अहम पहल ऐसे समय शुरू की है, जब देश में 2035 तक उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को पचास प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

मौजूदा समय में देश में उच्च शिक्षा का जीईआर करीब 27 प्रतिशत है। ऐसे में अगले दस वर्षों में उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने जीईआर को दोगुना करना होगा। यह तभी संभव हो सकता है, जब संस्थानों के पास मौजूदा क्षमता में भी दोगुने की वृद्धि हो। यही वजह है कि यूजीसी ने आयोग ने इसके साथ ही संस्थानों में शोध और इनोवेशन को गति देने पर जोर दिया है। वहीं शीर्ष संस्थानों से आसपास के कमजोर संस्थानों को सहयोग देने का भी प्रस्ताव किया है। जिसमें कमजोर संस्थानों के लिए अपनी लैब व इनोवेशन सेंटर को खोलने जैसी पहल शामिल है। यूजीसी ने इस दौरान सभी संस्थानों से मिलजुलकर काम करने पर भी जोर दिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुताबिक, देश में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खुलने के बाद भारतीय संस्थानों के साथ इनकी प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि भारतीय संस्थान भी स्वयं को विश्वस्तरीय स्तर के मुताबिक तैयार करें। गौरतलब है कि देश में मौजूदा समय में आस्ट्रेलिया के तीन और इंग्लैंड के एक विश्वविद्यालयों ने अपना कैंपस खोलने की एलान किया है। इनमें आस्ट्रेलिया के दो विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस शुरू भी कर दिया है।

2035 तक उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का है लक्ष्य

27% है मौजूदा समय में देश में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात

लीडरशिप प्रोग्राम के तहत देशभर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में क्षमता निर्माण पर फोकस किया है। जिसमें नए क्लास रूम सहित दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जुटाना शामिल है।

****

कह कर रहेंगे माधव जोशी

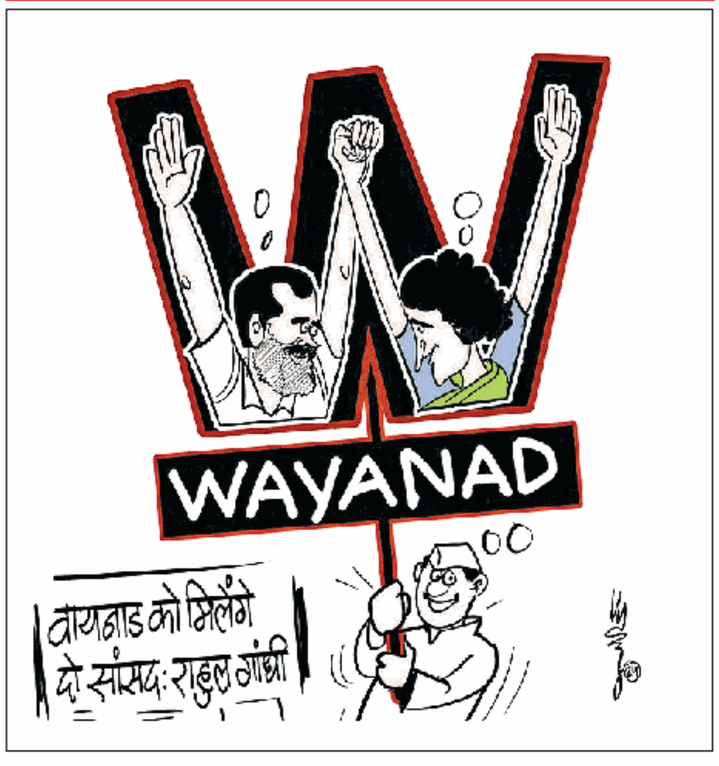

35 प्रत्याशियों की सूची जारी की है झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने अब तक विधानसभा चुनाव के लिए। पार्टी ने सभी वर्तमान विधायकों पर भरोसा जताया है। सरायकेला और जामा से अभी उम्मीदवार तय नहीं है। मतदान 13 और 20 नवंबर को है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 24 अक्टूबर, 2024

प्रियंका का चुनाव लड़ने की दिशा में पहला कदम, पर्चा भरा

वायनाड, प्रेट्र : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को औपचारिक रूप से अपना चुनावी सफर शुरू कर दिया। केरल के कलपेट्टा में एक विहंगम रोड शो के बाद वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए उन्होंने अपना नामांकन भरा। नेहरु-गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी की वह आखिरी सदस्य हैं जो चुनाव लड़ने जा रही हैं। हालांकि प्रियंका ने कहा कि उन्हें राजनीति में 35 सालों का अनुभव है। वह 17 साल की उम्र से ही इस क्षेत्र में आ गई थीं जब उन्होंने पहली बार अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी के लिए 1989 में चुनाव प्रचार किया था।

प्रियंका गांधी मंगलवार की रात ही अपनी मां व कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ वायनाड पहुंच गई थीं। बुधवार की सुबह उन्होंने अपने भाई व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ कलपेट्टा में एक विशाल रोड शो किया। इसमें गाजे-बाजे के साथ हजारों लोग शामिल हुए। 13 नवंबर को होने वाले उप चुनाव के नामांकन से पहले उन्होंने जनसभा को संबोधित कर कहा कि अपने पिता के अलावा उन्होंने मां, भाई और पार्टी के कई सहयोगियों के लिए भी चुनाव प्रचार किया है। वह पहली बार अपने लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। प्रियंका का यह बयान तब आया, जब वायनाड से भाजपा प्रत्याशी नव्या हरिदास ने कहा था कि राजनीति के क्षेत्र में वह प्रियंका से ज्यादा अनुभवी हैं।

प्रियंका ने वायनाड के भूस्खलन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने यहां तीन गांवों का दौरा किया था। वह वायनाड के लोगों के साहस से प्रभावित हैं। यह उनके लिए बड़े सम्मान की बात होगी कि उन्हें यहां के समुदाय व परिवार का हिस्सा बनने का अवसर मिले। जब पूरी दुनिया खिलाफ थी, तब वायनाड के लोगों ने उनके भाई राहुल का साथ दिया। इसके लिए वह उनकी आभारी हैं। राहुल आपसे दूर जाने से दुखी हैं। लेकिन वह राहुल व वायनाड के लोगों के बीच सेतु बनी रहेंगी। भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए प्रियंका ने कहा कि सत्तारूढ़ दल उनको बांटने में लगे हैं, जिनके वोट से वह सत्ता में आए। जनसभा के बाद प्रियंका कलक्ट्रेट आफिस गईं और सोनिया, राहुल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में नामांकन पत्र के तीन सेट दाखिल किए। तब पति राबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे।

- 13 नवंबर के उपचुनाव के लिए नामांकन भरने सोनिया व राहुल के साथ गईं कलेक्ट्रेट
- वायनाड से कांग्रेस प्रत्याशी ने रोड शो में कहा-मुझे राजनीति में 35 सालों का अनुभव

वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बुधवार को वायनाड के कलपेट्टा में नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले रोड शो के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा तथा पार्टी नेता राहुल गांधी। एएनआइ

वायनाड में दो सांसद होंगे : राहुल गांधी

वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने क्षेत्रीय जनता से आग्रह किया कि वह उनकी बहन का ध्यान रखें। राहुल ने कहा कि वह अब भी वायनाड से अनाधिकारिक सांसद रहेंगे। जबकि उनकी बहन प्रियंका औपचारिक सांसद बनेंगी। इसतरह वायनाड में दो सांसद होंगे। राहुल 2019 से 2024 तक वायनाड के सांसद रहे। उनके लोकसभा चुनाव के बाद वायनाड सीट छोड़ने पर यहां उपचुनाव हो रहे हैं।

प्रियंका सात दिन के लिए आएंगी, मैं पूरे पांच साल रहूंगी : नव्या हरिदास

वायनाड, एएनआइ : वायनाड से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नव्या हरिदास ने बुधवार को प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन के साथ ही घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। कोझिकोड में दो बार पार्षद रह चुकी नव्या ने कहा कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) की उम्मीदवार प्रियंका गांधी तो वायनाड में केवल सात दिन के दौरे पर आएंगी जबकि मैं पूरे पांच साल यहां रहूंगी। नव्या हरिदास ने कहा कि प्रियंका गांधी का उत्साह केवल एक दिन के लिए ही है। वह यहां रे परिवार के साथ आई हैं और नामांकन भरने के बाद दिल्ली लौट जाएंगी। चूंकि यह उनके लिए केवल सात दिनों का मामला ही है।

नव्या हरिदास। फाइल

प्रियंका की संपत्ति 12 करोड़, राबर्ट की 66 करोड़ रुपये

वायनाड, प्रेट्र : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नामांकन में दिए अपने हलफनामे में बताया है कि वाड्रा दंपती के पास कुल 88 करोड़ रुपये की संपत्ति है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ उम्मीदवार 52 वर्षीय प्रियंका के पास 12 करोड़ रुपये की संपत्ति है जिसमें शिमला के पास स्थित 12,000 वर्ग फीट का एक फार्महाउस है जिसकी कीमत 5.64 करोड़ रुपये है। उनके पास एक हांडा सीआरवी भी है जिसकी कीमत आठ लाख रुपये है। उनके पास 2.24 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड और 1.16 करोड़ के जेवर हैं। वह महरौली स्थित एक कृषि भूमि की सह-स्वामिनी हैं। इस जमीन के को-ओनर उनके भाई राहुल गांधी हैं। राबर्ट वाड्रा के पास 37.9 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है। जबकि अचल संपत्ति 27.64 करोड़ से अधिक की है। कुछ कंपनियों में साझेदारियां भी हैं।

दो एफआइआर दर्ज: 2010 में परास्नातक से बौद्ध शिक्षा में डिप्लोमा करने वाली प्रियंका के अनुसार उन पर एक एफआइआर 2023 की है, जिसमें धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। 2020 में यूपी में सरकारी आदेश का पालन नहीं करने का एक केस दर्ज है।

महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव और पवार 85-85 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

फार्मूला तय ▶ कुल 18 सीटें मविआ में शामिल छोटे सहयोगी दलों को दी जाएंगी

अन्य 15 विधानसभा सीटों पर बाद में लिया जाएगा निर्णय

राज्य ब्यूरो, जागरण ● मुंबई

महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (मविआ) में सीट बंटवारे का फार्मूला अंततः तय हो गया है। गठबंधन के तीनों प्रमुख दल शिवसेना (यूबीटी), राकांपा (शरदचंद्र पवार) और कांग्रेस में अभी 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बनी है। 18 सीटें महाविकास आघाड़ी में शामिल छोटे सहयोगी दलों को दी जाएंगी। बची 15 सीटों पर बाद में फैसला किया जाएगा।

मविआ में लंबे समय से सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस दोनों अपने लिए अधिक सीटों की मांग कर रही थीं। जबकि, राकांपा (शरदचंद्र पवार) के नेता शरद पवार शांत बैठे हुए थे। शिवसेना ने शुरू में ही संकेत दे दिए थे कि वह 120 से कम सीटों पर नहीं मानेगी, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में वह भाजपा के साथ गठबंधन में 124 सीटों पर चुनाव लड़ी थी।

दूसरी ओर कांग्रेस भी हाल के लोकसभा चुनावों में मिली अपनी अच्छी सफलता को आधार बनाते हुए गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती थी। सीटों की खींचतान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले एवं शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत के बीच कुछ कहासुनी भी हो गई थी। शिवसेना (यूबीटी) ने कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से भी संपर्क स्थापित कर विदर्भ एवं मुंबई की करीब एक दर्जन सीटें अपने लिए छोड़ने की बात की थी। लेकिन, कांग्रेस के प्रदेश नेता इस बार शिवसेना (यूबीटी) की जिद के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। अंततः बुधवार को शरद पवार ने यह विवाद सुलझाने की पहल की। उनकी अध्यक्षता में हुई तीनों दलों की बैठक में फिलहाल 85-85-85 का फार्मूला तय हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बैठक में 18 सीटें छोटे सहयोगी दलों के लिए छोड़ने पर सहमति बनी है। साथ ही बची 15 सीटों का फैसला भी तीनों प्रमुख दल जल्द ही कर लेंगे। गौरतलब है कि इस बीच शिवसेना (यूबीटी) ने अपने 65 उम्मीदवारों की पहली सूची बुधवार को जारी कर दी है। इसमें पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे का नाम उनके पिछले चुनाव क्षेत्र वरली से घोषित किया गया है।

मुंबई में बुधवार को महाविकास आघाड़ी की संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत तथा कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले। प्रेट्र

शिंदे ने सभी मंत्री और विधायकों सहित निर्दलियों को उतारा

मिह है, मुंबई: शिवसेना (शिंदे गुट) ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने सभी मंत्रियों और विधायकों को मैदान में उतारा है। इसमें सांसदें, मंत्रियों और विधायकों के परिवार के सदस्यों को भी मौका दिया गया है। वर्ष 2022 में विद्रोह के बाद शिंदे सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों को इस सूची में रखा गया है।

पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे (ठाणे में कोपरी-पचपखाड़ी) ने मंगलवार देर रात 45 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। मंत्री गुलाबराव पाटिल (जलगांव ग्रामीण), संजय राठौड़ (दिग्रस), अब्दुल सत्तार (सिल्लोड), दादा भुसे (मालेगांव आउटर), तानाजी सावंत (परांडा), शंभुराज देसाई (पाटन), उदय सामंत (रत्नागिरी) और दीपक केसरकर (सावंतवाड़ी) पहली सूची में शामिल हैं। पूर्व मंत्री संदीपन भुमरे के बेटे विलास भुमरे को पैठण क्षेत्र से टिकट मिला है। खानापुर विधायक अनिल बाबर के बेटे सुहास ने पिता की जगह ले ली है। एरंडोल विधायक चिमनराव पाटिल ने अपने बेटे अमोल पाटिल के लिए सीट खाली कर दी है।

अजीत पवार बारामती से ही चुनाव लड़ेंगे

राज्य ब्यूरो, जागरण ● मुंबई

- बारामती में एक बार फिर पवार बनाम पवार का मुकाबला देखने को मिलेगा

पूर्व कांग्रेस विधायक सुलभा संजय खोडके महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की उपस्थिति में राकांपा में सम्मिलित हुईं। एएनआइ

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपनी परंपरागत सीट बारामती से ही चुनाव लड़ेंगे। राकांपा की 38 उम्मीदवारों की पहली सूची में उनके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल एवं दिलीप वलसे पाटिल के नाम भी शामिल हैं। इससे तय हो गया है कि बारामती में एक बार फिर पवार बनाम पवार का मुकाबला देखने को मिलेगा।

हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बारामती संसदीय सीट से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार की हार के बाद अजीत पवार कई बार कह चुके हैं कि उन्हें परिवार में राजनीति को नहीं लाना चाहिए था। उन्होंने अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के विरुद्ध अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने पर भी अफसोस जाहिर किया था। इससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत पवार अब परिवार में कोई और राजनीतिक टकराव नहीं चाहते, क्योंकि बारामती विधानसभा क्षेत्र से इस बार राकांपा (शरदचंद्र पवार) से उनके सगे भतीजे युगेंद्र पवार को चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है।

युगेंद्र अजीत पवार के सगे भाई श्रीनिवास पवार के पुत्र हैं। श्रीनिवास का पूरा परिवार लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा पवार के विरुद्ध एवं सुप्रिया सुले के पक्ष में काम कर रहा था। लेकिन, अब राकांपा (अजीत) की पहली सूची में ही स्वयं अजीत पवार का नाम आने से स्पष्ट हो गया है कि वह एक बार फिर अपने ही परिवार में राजनीतिक टकराव के लिए मन बना चुके हैं। अजीत पवार बारामती विधानसभा सीट से आठवीं बार चुनाव लड़ेंगे। वह एक बार बारामती लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि अजीत पवार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए ही बारामती से चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

सोमैया ने अबू आजमी के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र

नई दिल्ली, एएनआइ : भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर भड़काऊ भाषण देने के लिए समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव अभियान के दौरान आजमी मुस्लिम समुदाय से धार्मिक आधार पर वोट करने की अपील कर रहे थे। वह चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं के बीच कट्टरता फैला रहे थे।

चुनावी परिदृश्य : गठबंधनों के बीच टिकट वितरण को लेकर खटपट

झारखंड में राजग में बेहतर तालमेल, महागठबंधन में दिख रही खींचतान

राज्य ब्यूरो, जागरण ● रांची

- भाजपा ने आजसू पार्टी, जदयू के साथ-साथ लोजपा (रामविलास) संग भी किया तालमेल
- आइएनडीआइए में सीटों के लिए खींचतान से लेकर खटपट तक

झारखंड में भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) अपने घटक दलों के साथ बेहतर तालमेल बनाए हुए है। भाजपा ने आजसू पार्टी, जदयू के साथ-साथ लोजपा (रामविलास) संग भी सीटों को लेकर तालमेल किया। अभी तक किसी सीट को लेकर आपस में खटपट की नौबत नहीं है, जबकि दूसरी ओर आइएनडीआइए में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान और रस्साकशी स्पष्ट नजर आ रही है। ज्यादातर सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस पार्टी में सहमति बन जाने के बाद भी अभी कुछ सीटों पर जिच है। इस पेंच को देखते हुए कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। पहले 22 सीटें मांगने और बाद में 12 सीटों को लेकर अड़ने के बाद राजद को छह सीटों पर मनाने में झामुमो सफल हो गया है, लेकिन अब भाकपा माले सीटों को लेकर अड़ गया है। मंगलवार को झामुमो और माले की ओर से जारी सूची में एक सीट धनवार ऐसी है, जिस पर दोनों ने अपने-अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि इस सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी प्रत्याशी हैं। झामुमो और भाकपा माले द्वारा प्रत्याशी उतारे जाने से पूर्ण तालमेल की संभावना अब कम ही है। इसके अलावा धनवार से सटे जमुआ विधानसभा सीट पर भी लगभग यही स्थिति है। माले के विरोध को दरकिनार करते हुए इस सीट पर झामुमो ने भाजपा से आए निवर्तमान विधायक केदार हाजरा को उतार दिया है। इससे यह संभावना है कि माले गठबंधन से छिटक सकता है। निरसा और सिंदरी सीट को लेकर भी माले का दबाव है। दरअसल भाकपा माले में हाल ही में माक् संवादी समन्वय समिति (मासस) का विलय हुआ है। इससे माले का प्रभाव क्षेत्र बढ़ा है और माले इसी हिसाब से गठबंधन में अपनी सीटें चाहता है। निरसा और सिंदरी मासस का प्रभाव क्षेत्र रहा है। मासस का बंगाल से सटे इन दोनों विधानसभा सीटों पर असर रहा है। यहां से मासस के विधायक पूर्व में जीतते रहे हैं।

टिकट नहीं मिलने पर झामुमो विधायक के बगावती तेवर

सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) में भी टिकट से वंचित रहे नेताओं का गुस्सा सामने आने लगा है। बुधवार को लिट्टीपाड़ा के विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने अपने रोष का इजहार किया। मरांडी ने कहा कि बगैर किसी गलत के उनका टिकट काटकर बाहरी व्यक्ति को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वे इसका खुलकर विरोध करेंगे। यही नहीं, वह चुनाव में भी प्रत्याशी बनकर उतरेंगे।

नेता और कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटी भाजपा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● रांची

- मंडल अध्यक्ष और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता से संवाद करेंगे नेता

भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण के बाद नेताओं के पार्टी छोड़ने और असंतोष पर रोक लगाने की कोशिश में है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष रांची पहुंचे और दो दिनों तक यहां प्रवास किया। प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्व सरमा भी लगातार असंतुष्ट नेताओं के घर जाकर उनसे बात कर रहे हैं। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रवींद्र राय को मनाने में पार्टी सफल रही है। लेकिन पार्टी की असली चिंता कार्यकर्ताओं के असंतोष से है। सोमवार को पलामू जिला भाजपा की बैठक में हुसैनाबाद के सातों मंडल अध्यक्ष नहीं पहुंचे थे। दुमका में लुईस मरांडी के झामुमो में शामिल होने के बाद उनके समर्थक भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़े। जबकि, जमशेदपुर पूर्वी सीट के लिए पार्टी की बैठक में क्षेत्र के कई प्रमुख कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहे हैं। नेताओं की नाराजगी से बड़ा खतरा कार्यकर्ताओं का असंतोष है, जिससे पार्टी परेशान है। ऐसे में बीएल संतोष ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और उनकी टीम को ऐसे कार्यकर्ताओं से बात करने का निर्देश दिया है। प्रदेश भाजपा को उम्मीद है कि नेताओं की सक्रियता से डैमेज कंट्रोल आसान हो जाएगा और कार्यकर्ता प्रत्याशी के पक्ष में जुट जाएंगे।

दूसरे दलों के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं पर भी भाजपा की नजर : आइएनडीआइए में टिकट बंटवारे के बाद कुछ क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नाराजगी जताई है। दुमका जिले में जामा विधानसभा सीट से लुईस मरांडी को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा हुई तो झामुमो कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह दिनेश साइमन मरांडी ने टिकट नहीं मिलने पर झामुमो नेतृत्व पर टिप्पणी की है। भाजपा ने अपने विधानसभा प्रभारियों को इस पर नजर रखने का निर्देश दिया है।

गैंगस्टर अमन नहीं लड़ सकेगा चुनाव, कोर्ट ने खारिज की याचिका

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : गैंगस्टर अमन साहू झारखंड की बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकेगा। बिलासपुर हाई कोर्ट ने बुधवार को अमन के चुनाव लड़ने के आवेदन को खारिज कर दिया। वहीं, झारखंड हाई कोर्ट में लगे आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

अमन के वकील ने कोर्ट में आवेदन लगाकर नामांकन के लिए उपस्थिति की अनुमति मांगी थी। बड़कागांव विधानसभा के नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। वकील हेमंत सिकरवार ने चुनाव के लिए नामांकन फार्म पर अमन साहू से हस्ताक्षर करवाए थे। उल्लेखनीय है अमन साहू छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस के रिमांड पर है। उससे पीआरए ग्रुप के आफिस के बाहर फायरिंग करवाने के मामले में पूछताछ की जा रही है। अमन पर रंगदारी व वसूली का भी आरोप है।

बिहार में पहली बिसात पर ही लड़खड़ाने लगी जन सुराज पार्टी, दो प्रत्याशियों को बदला

विकाश चंद्र पांडेय ● जागरण

- बेलागंज में प्रो. खिलाफत हुसैन के बजाय मो. अमजद और तरारी से एसके सिंह की जगह किरण सिंह पर दांव

किरण सिंह तरारी

मो. अमजद

पटना: चुनावी बिसात पर जन सुराज पार्टी (जसुपा) पहले ही दांव में लड़खड़ाने लगी है। पहले तो प्रत्याशियों के चयन के दौरान हाय-तौबा हुई और अब उन्हें बदलने की नौबत आ गई है।

बिहार के तरारी और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में उसने अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। प्रश्न यह कि ऐसी स्थिति क्यों बनी? उत्तर सीधा-सपाट है, होश से अधिक जोश के कारण। हालांकि, बदलाव का तार्किक कारण गिनाते हुए सूत्रधार प्रशांत किशोर (पीके) चुनावी जीत की रणनीति में जसुपा को आज भी सबसे आगे बता रहे।

पीके का कहना है कि टिप्पणी होगी कि जसुपा ने पहले ही कदम पर धक्का खा लिया, लेकिन हमारी पार्टी नई है और हमसे एक-दो गलतियां हो सकती हैं। हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। वस्तुतः जोश में आकर ही जसुपा उप चुनाव के मैदान में उतर आई। ऐसा तब जबकि बिहार में वर्ष भीतर ही विधानसभा का चुनाव होना है। अमूमन हर नई-नवेली पार्टी अपने पहले मुकाबले में उप चुनाव से कतराती है, लेकिन जसुपा ने यह चुनौती स्वयं स्वीकार की। अब उसे अपने आधे प्रत्याशियों (चार में से दो) को बदलना पड़ा है। उनमें एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह भी हैं, जो विधानसभा उप चुनाव में तुरुप का इक्का बताए गए थे। एसके सिंह का नाम नोएडा की मतदाता सूची में है। आखिरी क्षण में बिहार की मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा जाना संभव नहीं था। ऐसे में वह विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी नहीं बन सकते। उनकी जगह 40 वर्षीया किरण सिंह तरारी के मैदान में हैं। बेलागंज में प्रो. खिलाफत हुसैन के बजाय अब 55 वर्षीय मो. अमजद प्रत्याशी बनाए गए हैं, वह दो चुनावों में मात खा चुके हैं। सुखद यह कि पूर्व घोषित प्रत्याशियों ने ही मंगलवार को आरा में हुई प्रेस-वार्ता में अपने स्थानापन्न नए प्रत्याशियों का नाम आगे किया और उन्हें विजयी बनाने की प्रतिबद्धता जताई।

****

'पंजाब में शिअद से ज्यादा मजबूत है भाजपा, अकेले लड़ेंगे उपचुनाव'

जागरण संवाददाता, गिद्दड़बाहा (मुक्तसर)

- भाजपा के प्रदेश प्रभारी विजय रुपाणी ने कहा-पंजाब की जनता भाजपा के साथ, हमारा वोट शेयर बढ़ा

विजय रुपाणी। फाइल

भाजपा प्रदेश में विधानसभा की चार सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव अपने दम पर लड़ेगी और जीत भी दर्ज करेगी। पड़ोसी राज्य हरियाणा की तरह पंजाब में भी 2027 में भाजपा सरकार बनाएगी। यह दावा भाजपा के प्रदेश प्रभारी व गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने गिद्दड़बाहा में प्रेस कान्फ्रेंस में किया। रुपाणी ने कहा कि भाजपा पंजाब में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। इसी कारण इस उपचुनाव में शिअद से कोई भी गठबंधन नहीं किया जाएगा। रुपाणी ने कहा कि शिअद लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी से कमजोर रही है। भाजपा का वोट शेयर बढ़ा है। ऐसे में भाजपा अपने बलबूते पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता भाजपा के साथ है। इस मौके पर भाजपा के गिद्दड़बाहा से उम्मीदवार मनप्रीत बादल भी मौजूद थे। रुपाणी ने धान की खरीद को लेकर पंजाब की आप सरकार द्वारा केंद्र पर लगाए जा रहे आरोपों को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि धान खरीद के मामले में पंजाब सरकार राजनीति कर रही है। एक सवाल के जवाब में रुपाणी ने कहा कि केंद्र सरकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के किसी भी मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर रही। यह धार्मिक मामला है। इसमें सरकार कतई भी दखल नहीं दे सकती।

कर्नाटक में उपचुनाव से पहले भाजपा नेता योगेश्वर कांग्रेस में शामिल

बेंगलुरु, प्रेट्र: कर्नाटक में उपचुनाव से पहले भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सीपी योगेश्वर बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें 13 नवंबर को राज्य की चन्नपटना विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार बनाया जा सकता है। योगेश्वर ने सोमवार को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देने के बाद बुधवार सुबह मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात की। शामिल कराया। कर्नाटक में चन्नपटना समेत तीन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं।

सीपी योगेश्वर। फाइल

14.82 लाख अराजपत्रित राज्यकर्मियों को बोनस मिलेगा दीपावली पर उप्र में। हर कर्मचारी के हिस्से में आएंगे 6,908 रुपये। 1,727 रुपये मिलेंगे नकद, 75 प्रतिशत धनराशि जमा होगी जीपीएफ में। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा।

'जेपीसी की कार्यवाही पर कुछ नहीं बोला, सिर्फ हिंसा पर बात की'

वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज

जगदंबिका पाल। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : वक्फ बिल पर संसदीय समिति (जेपीसी) के प्रमुख जगदंबिका पाल ने बुधवार को विपक्ष के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा पैनल की बैठक के दौरान कांच की बोतल तोड़कर अध्यक्ष पर फेंकने के बारे में सार्वजनिक रूप से बताकर मानदंडों का उल्लंघन किया है।

पाल ने कहा- ''मैंने समिति की किसी कार्यवाही या विचार-विमर्श का राजफाश नहीं किया है। मैंने केवल समिति की बैठक के दौरान एक सदस्य द्वारा की गई हिंसा और उसके बाद उसके निलंबन के बारे में बयान दिया है।'' विपक्षी नेताओं ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर निशाना साधा और उन पर टीएमसी सदस्य कल्याण बनर्जी द्वारा कांच की बोतल तोड़ने और उन पर फेंकने की घटना को सार्वजनिक करके प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। द्रमुक सांसद ए राजा और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि जगदंबिका पाल ने संसदीय समिति की बैठकों के संचालन के लिए प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन किया है जोकि बंद कमरे में की जाती हैं। इस पर जगदंबिका पाल ने कहा कि मैंने हमेशा संसदीय प्रक्रिया के नियमों का पालन किया है और सदन की गरिमा को बनाए रखा है।

भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जेपीसी की बैठक के दौरान हुई घटना की कड़ी निंदा की। कहा- ''यह दुखद और शर्मनाक दोनों है कि हमारे देश के सांसद जेपीसी के भीतर गुंडागर्दी और इस तरह के घृणित कृत्यों में लिप्त हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान, लोकतंत्र और कानून के शासन की बात करते हैं फिर भी संसदीय प्रक्रिया में गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं।'' बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर मंगलवार को जेपीसी की बैठक के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पीने के पानी के लिए रखी शीशे की बोतल तोड़कर अध्यक्ष जगदंबिका पाल की ओर उछाल दी थी। बाद में बनर्जी को समिति से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। उधर, तीन भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे, अभिजीत गंगोपाध्याय और अपराजिता सारंगी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने और वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक के दौरान हिंसा के लिए जांच लंबित रहने तक उन्हें सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की है। यही नहीं, बनर्जी की निचले सदन से सदस्यता रद करने की मांग करते हुए कहा गया है कि मामला लोकसभा आचार समिति को सौंपा जाना चाहिए।

मायावती के पोस्टर के साथ आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित, एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सहारनपुर : पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा अध्यक्ष मायावती के पोस्टर के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने कोतवाली के उपनिरीक्षक की ओर से मुकदमा दर्ज किया था। बसपा की ओर से भी कोतवाली में तहरीर दी गई है। रामपुर कलां के एक युवक ने करवाचौथ के त्योहार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के पोस्टर के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाया था। इसके बाद इस वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। वीडियो प्रसारित होने के बाद बसपा तथा भीम आर्मी जय भीम सहित अन्य संगठनों ने रोष व्यक्त किया।

शाह से मिले उमर अब्दुल्ला, राज्य के मुद्दे पर की चर्चा

अमित शाह और उमर अब्दुल्ला। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ अन्य मुद्दों पर उनसे चर्चा की।

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उमर अब्दुल्ला की यह पहली दिल्ली की यात्रा है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के साथ उनकी वार्ता करीब 30 मिनट चली। बैठक के बाद उमर ने बताया कि यह केवल शिष्टाचार भेंट थी और इस दौरान राज्य के दर्जे पर भी बात हुई। यहां बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और तीन दिन पूर्व गांदरबल के गगनगीर क्षेत्र में एक हमले में आतंकियों ने डाक्टर समेत सात लोगों की जान ले ली। जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से पुलिस व आंतरिक सुरक्षा का विषय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। उमर फिलहाल नई दिल्ली में हैं और वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। हाल ही में सरकार के गठन के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पास किया था।

पांच वर्ष बाद हुर्रियत बैठक, सियासी रुख में बदलाव की जगी है उम्मीद

राजनीतिक समीकरणों के बीच इस बैठक को माना जा रहा अहम

कश्मीर पर पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को नकार सकता है अलगाववादी संगठन

राज्य ब्यूरो, जागरण ● श्रीनगर

श्रीनगर में उदारवादी हुर्रियत नेता मीरवाइज मौलवी उमर फारूक (दाएं से दूसरे) के आवास पर बैठक में उपस्थित हुर्रियत की कार्यकारी परिषद के सदस्य मसरूर अब्बास अंसारी (बाएं से), प्रो. अब्दुल गनी बट और बिलाल गनी लोन। जागरण

हुर्रियत कान्फ्रेंस के उदारवादी गुट ने लगभग पांच वर्ष बाद मंगलवार को बैठक की। जम्मू-कश्मीर में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से अभी तक हुर्रियत की गतिविधियां और बैठकें बंद थीं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अलगाववादी गुट बदलाव की राह पकड़ सकता है। बैठक के बाद कोई अधिकारिक बयान नहीं आया, पर चर्चा है कि अलगाववादी संगठन कश्मीर मुद्दे पर अपनी पूर्व नीति में बदलाव लाते हुए जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को खारिज कर सकता है।

यहां बता दें कि विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के नेताओं ने अलगाववाद की सियासत से किनारा कर मुख्यधारा की राजनीति में वापसी की राह पकड़ ली थी और चुनाव भी लड़ा था। अगस्त, 2019 के बाद से केंद्र सरकार ने सभी अलगाववादी संगठनों और उनके नेताओं की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा रखी थी। उग्रपंथी अलगाववादियों की गिरफ्तारी से कश्मीर में न सिर्फ पत्थरबाजी और हिंसक प्रदर्शन बंद हो गए, बल्कि सुरक्षा और विश्वास का वातावरण भी बना। उदारवादी गुट के वरिष्ठ नेताओं की भी पांच वर्ष में कभी आपस में न कभी मुलाकात और न बैठक हुई। टेलीफोन संपर्क भी लगभग बंद रहा।

> अब तक हुर्रियत नेताओं की बैठक और आवाजाही पर अघोषित रोक थी, अचानक यह रोक हट गई। उदारवादी हुर्रियत पहले भी कश्मीर मुद्दे पर कहीं न कहीं भारतीय पक्ष का ही परोक्ष समर्थन करती रही है। माना जा रहा है कि हुर्रियत कश्मीर मुद्दे पर अपने स्टैंड में बड़े बदलाव का एलान कर सकती है।
>
> -अजय बाचलू, कश्मीर मामलों के जानकार

> हुर्रियत की बैठक कानून-व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा भी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस बैठक की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह से उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। अगर गृह मंत्रालय ने अनुमति दी है तो निश्चित रूप से इस बैठक के बाद कुछ खास सुनने या देखने को मिल सकता है।
>
> -बिलाल बशीर, कश्मीर मामलों के जानकार

इनके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए और कई बार उन्हें नजरबंद रखा गया।

मंगलवार को संगठन के नेता उदारवादी हुर्रियत नेता मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के आवास पर एकत्रित हुए। बैठक में हुर्रियत की कार्यकारी परिषद के सदस्य प्रो. अब्दुल गनी बट, बिलाल गनी लोन, मसरूर अब्बास अंसारी मौजूद रहे। बैठक लगभग दो घंटे चली और इसका एक वीडियो मीरवाइज ने स्वयं एक्स हैंडल पर अपलोड किया है। बैठक में बातचीत पर एक हुर्रियत नेता ने कहा कि काफी दिन से हम मिले नहीं थे। सब बैठे थे और कश्मीर के मौजूदा राजनीतिक-सामाजिक हालात और हुर्रियत की भूमिका पर चर्चा हुई। कश्मीर में शांति और खुशहाली, कश्मीरियों के लिए उनके हक की बहाली ही हमारा मकसद है। कश्मीरियों के साथ इंसाफ होना चाहिए।

कट्टरपंथी गुट के ज्यादातर नेता जेल में: जम्मू-कश्मीर में हुर्रियत कान्फ्रेंस दो धड़ों में बंटी हैं। उदारवादी गुट की अगुआई मीरवाइज मौलवी उमर फारूक करते हैं। यह गुट पहले भी केंद्र से वार्ता में शामिल रहा है। वहीं कट्टरपंथी गुट की कमान सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद जेल में बंद अलगाववादी मसर्रत आलम के हाथों में है। कट्टरपंथी गुट के सभी प्रमुख नेता जेल में बंद हैं या फिर निष्क्रिय बैठे हैं।

आबादी बढ़ाने की सियासत संसदीय सीटों पर नजर

वर्ष 2026 के बाद संसद की लोकसभा सीटों का पुनर्निरीक्षण किया जाना है। फिलहाल इनकी संख्या पिछले 50 वर्षों से 543 ही है। संभावना जताई जा रही है कि इस बार परिसीमन आयोग के नियमों के चलते दक्षिणी राज्यों की सीटें कम हो सकती हैं। इसके चलते इन राज्यों को राजनीतिक और आर्थिक नुकसान का डर सताने लगा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन कि इस सप्ताह की शुरुआत में दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील के पीछे भी यही कारण है। जनसंख्या वृद्धि की सीमित दर के चलते तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक के साथ ही पश्चिम बंगाल को लोकसभा की सीटें कम होने का खतरा नजर आ रहा है। भले ही यह आशंकाएं सही हों या नहीं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि में गुणात्मक बढ़ोतरी कोई वाजिब तरीका नहीं लगता। और अगर नए परिसीमन में सीटें कम नहीं भी हुईं, तो बढ़ने की संभावनाएं क्या हैं और देश में किन राज्यों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होने की संभावना है, यह इस वक्त सबसे जरूरी सवाल है और इसके संभावित जवाब भी जानना जरूरी हैं।

सीटों की गणना : 2026 के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मिलने वाली सीटों को तय करने की तीन प्रमुख गणनाएं या संभावनाएं हो सकती हैं।

संभावना

- अगर सीटें 543 ही फिक्स रखी जाएं और जनसंख्या में हिस्सेदारी के लिहाज से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें नजदीकी पूर्ण संख्या में बदल दी जाएं। तो इस तरह से आठ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाते में शून्य सीटें आती हैं। अगर इनको न्यूनतम एक सीट दी जाए, तो सीटों की संख्या बढ़कर 549 हो जाती है।
- अब दूसरे आंकलन में मान लेतें हैं कि किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को शून्य सीट ना मिले और कुल सीटों की संख्या भी 543 रहे, तो इस लिहाज से कुछ दक्षिणी राज्यों को उनकी मौजूदा सीटों से कम सीटें मिलती हैं।
- ऐसे में अब तीसरी गणना बेहद जरूरी हो जाती है। इस गणना में इस बात का ध्यान रखा गया है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें किसी भी हाल में मौजूदा संख्या से कम नहीं होनी चाहिए।

परिणाम

- अगर जनसंख्या में परिवर्तन का ध्यान रखा जाए और किसी भी राज्य को शून्य सीटें ना मिले, तो पांच दक्षिणी राज्यों की 23 सीटें कम हो जाएंगी। देश की जनसंख्या में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले उप्र, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और मप्र की 35 सीटें बढ़ जाएंगी।
- अगर सीटों की संख्या पूर्ववत 543 फिक्स रखी जाए, तो दक्षिणी राज्यों के पास से 25 सीटें चली जाएंगी व पांच सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की 33 सीटें बढ़ जाएंगी।
- अगर किसी भी राज्य की सीटें मौजूदा से कम ना की जाएं और बड़े राज्यों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व मिले, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु को 23 ज्यादा सीटें मिलेंगी, जबकि केरल की यथावत रहेंगी। शीर्ष पांच राज्यों को 150 सीटें ज्यादा मिल जाएंगी।

जनसंख्या और प्रतिनिधित्व का आंकड़ा

दरअसल, 1976 में परिसीमन आयोग के आदेश के चलते लोकसभा सीटों की संख्या को 543 पर ही तय कर दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2001 में जनसंख्या को सीमित रखने को प्रोत्साहित करने के मकसद से इन सीटों को अगले 25 वर्षों के लिए फिर से फिक्स कर दिया गया। अब 2026 में फिर से सीटों की संख्या पर फैसला लिया जाना है।

जागरण रिसर्च

राज्यवार जनसंख्या के अनुसार सीटों की गणना

प्रदेश	जनसंख्या में हिस्सेदारी (%)	मौजूदा लोकसभा सीटें	किसी की शून्य सीट ना हों	कुल 543, शून्य सीटें भी ना हों	सीटें कम नहीं, बड़े राज्य को ज्यादा सीटें
उत्तर प्रदेश	17.0	80	92	91	133
बिहार	9.2	40	50	50	72
महाराष्ट्र	9.1	48	49	49	71
राजस्थान	5.9	25	32	31	46
मध्य प्रदेश	6.3	29	34	34	49
गुजरात	5.2	26	28	28	41
पश्चिम बंगाल	7.1	42	38	38	55
कर्नाटक	4.8	28	26	26	38
झारखंड	2.9	14	16	15	22
हरियाणा	2.2	10	12	12	17
असम	2.6	14	14	14	20
छत्तीसगढ़	2.2	11	12	12	17
दिल्ली	1.6	7	9	8	12
ओडिशा	3.3	21	18	18	26
आंध्र प्रदेश	3.8	25	21	20	30
तेलंगाना	2.7	17	15	15	21
पंजाब	2.2	13	12	12	17
तमिलनाडु	5.5	39	30	29	43
केरल	2.6	20	14	14	20
जम्मू-कश्मीर	1.0	5	5	5	8
उत्तराखंड	0.8	5	5	5	7
मेघालय	0.2	2	1	1	2
मणिपुर	0.2	2	1	1	2
हिमाचल प्रदेश	0.5	4	3	3	4
अरुणाचल प्रदेश	0.1	2	1	1	2
गोवा	0.1	2	1	1	2
अन्य राज्य	0.9	12	12	12	12
कुल		543	549	543	*790

हाई कोर्ट ने निलंबित होमगार्ड के मामले में राज्य से मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

> **आरजी कर मामले में न्याय मांगने पर अस्थायी होमगार्ड को निलंबित करने का आरोप**

कलकत्ता हाई कोर्ट ने निलंबित किए गए एक अस्थायी होमगार्ड के मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आरोप है कि आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में न्याय की मांग करने पर होमगार्ड काशीनाथ पांडा को निलंबित कर दिया गया था।

न्यायाधीश कौशिक चंद ने आदेश दिया कि राज्य एक रिपोर्ट पेश करे कि काशीनाथ को ऐसी सजा क्यों भुगतनी पड़ी। होमगार्ड पर लगे आरोपों की जानकारी पुलिस को दी जानी चाहिए। वादी के वकील ने कोर्ट में कहा कि होमगार्ड को बचाव का कोई मौका दिए बिना नौकरी से हटा दिया गया है। सामाजिक अन्याय का विरोध क्यों नहीं किया जा सकता? यह पूरी तरह से मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप है। इसी सप्ताह मामले पर फिर सुनवाई होगी। बता दें कि हावड़ा जिले के निवासी काशीनाथ पांडा पिछले पांच वर्षों से बैरकपुर कमिश्नरेट के तहत बेलघरिया थाने में अस्थाई होम गार्ड के रूप में काम कर रहा था। 21 सितंबर को उसने फेसबुक पर एक गाने का वीडियो पोस्ट कर आरजी कर मामले में न्याय की गुहार लगाई थी। भक्ति गीत में कुछ पंक्तियां खुद से जोड़कर उसने गीत को परिवर्तित किया था।

छेड़छाड़ पर विरोध प्रदर्शन के बाद मणिपुर के चूड़चंद्रपुर में कर्फ्यू

इंफाल, आइएएनएस : मणिपुर के आदिवासी बहुल चूड़चंद्रपुर में जिला प्रशासन ने बुधवार को तुइबोंग उपमंडल में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया है। स्थानीय संगठनों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन एक गैर स्थानीय व्यापारी के खिलाफ आरोपों से शुरू हुआ था, जिस पर एक आदिवासी महिला से छेड़छाड़ का प्रयास करने का आरोप है। तुइबोंग में स्थिति तब बिगड़ गई जब स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग करते हुए सड़कों जाम लगा दिया और लकड़ियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को 12 घंटे का बंद भी रखा। मणिपुर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (पीपुल्स वार ग्रुप) के छह उग्रवादियों को इंफाल पूर्व जिले से गिरफ्तार किया है।

बाराबंकी में ढाबा संचालक थूक लगाकर बना रहा था रोटी, वीडियो प्रसारित होते ही किया सीज

जागरण संवाददाता, बाराबंकी

> **खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम ने जब्त की सामग्री, हिरासत में आरोपित इरशाद**

सुढियामऊ स्थित एक होटल पर रोटी में थूक लगाकर पकाता कारीगर सोत-इंटरनेट मीडिया >>

गाजियाबाद में पेशाब से आटा गूंथने और सीतापुर में दूध के क्रेट में मानव मल रखकर किराना दुकान पर फेंकने की घटना के बाद मंगलवार को बाराबंकी में एक ढाबे में रोटियों पर थूक लगाकर पकाने का मामला प्रकाश में आया है। रोटियों में थूक लगाने के वीडियो का संज्ञान लेते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम ने जांच कर ढाबे को सीज कर दिया है। मामले में विभाग मुकदमा भी दर्ज कराएगा। आरोपित को हिरासत में लिया गया है।

जिले में रामनगर क्षेत्र के सुढ़ियामऊ गांव में सड़क किनारे इरशाद उर्फ इब्राहिम का ढाबा है। वह तंदूर में रोटी डालने से पहले थूक लगाता था। कुछ लोगों ने उसकी इस करतूत का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। मामला मंगलवार को जब सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वितीय शैलेंद्र कुमार के संज्ञान में आया तो उन्होंने मौके पर टीम भेजी। उन्होंने बताया कि ढाबे का पंजीकरण नहीं है। संचालक को ढाबा बंद करने के लिए नोटिस दिया गया है और विभागीय कर्मचारी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। मौके पर मिली खाद्य सामग्री को भी कब्जे में लिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि जिस जमीन पर ढाबा संचालित हो रहा था, उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है।

राजस्थान में पूर्व मंत्री ने कहा, सरकार गिराने के लिए था 60 करोड़ का आफर

राजेंद्र गुढ़ा। फाइल

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान में पिछली अशोक गहलोत सरकार में सैनिक कल्याण राज्यमंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि मैंने दो बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाई। दोनों समय छह-छह विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया। सरकार गिराने के लिए मुझे 60 करोड़ रुपये का आफर मिला था, लेकिन सोचा था कि भाजपा के घमंड को चकनाचूर करूंगा, इसलिए आफर ठुकरा दिया। हालांकि, गुढ़ा ने यह नहीं बताया कि उन्हें यह आफर किसने दिया था। बुधवार को झुंझुनूं के सुलताना कस्बे में एक सभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि भाजपा ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा में चुनी हुई सरकार को गिरा दिया था।

मुद्दा

दीपावली की छुट्टियों के चलते सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाली गई, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बोले-जल्द सुनवाई संभव नहीं,10 को होंगे रिटायर

वैवाहिक दुष्कर्म पर अब सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ करेगी सुनवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

> **प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ करस रही थी सुनवाई, 10 नवंबर को सेवानिवृत्ति हो रहे हैं प्रमुख न्यायाधीश**

भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने वैवाहिक दुष्कर्म के 'अपराधीकरण' मामले की सुनवाई बुधवार को चार सप्ताह के लिए टाल दी है। दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा अपनी दलीलें रखने के लिए मांगे गए एक-एक दिन के समय को देखते हुए चीफ जस्टिस को लगा कि मामले की सुनवाई दीपावली की छुट्टियों के पहले पूरी होनी संभव नहीं है, इसलिए सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी गई। चार सप्ताह बाद नई पीठ मामले पर सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं जिनमें वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाओं में आइपीसी की धारा 375 के अपवाद दो और नए कानून बीएनएस की धारा 63 के अपवाद दो को रद करने की मांग की गई है जो पति को दुष्कर्म से छूट देता है। बुधवार को मामला प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगा था। पीठ ने जब पक्षकारों के वकीलों से पूछा कि वे बहस के लिए कितना समय लेंगे, इस पर वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि जितनी सामग्री रिकार्ड पर रखी गई है, एक दिन का समय लगेगा। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि उन्हें एक दिन का समय चाहिए क्योंकि मामले के परिणाम दूरगामी हैं। अन्य वकीलों ने भी इसी तरह समय मांगा जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले की सुनवाई निकट भविष्य में पूरी करना संभव नहीं होगा। इसकी सुनवाई चार सप्ताह बाद अब नई पीठ ही कर पाएगी। ध्यान रहे कि दीपावली की छुट्टियां 26 अक्टूबर से शुरू होंगी और कोर्ट चार नवंबर को खुलेंगे। सीजेआइ के पास तब तक पांच कार्यदिवस ही बचेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सुनवाई शुरू की थी। एक याचिकाकर्ता की वकील करुणा नंदी और कुछ और वकीलों की ओर से पक्ष रखा जा चुका था।

स्वामी श्रद्धानंद की याचिका पर विचार से इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्वामी श्रद्धानंद (84) की याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। कारावास में पत्नी की हत्या के आरोपित श्रद्धानंद ने अदालत से उस फैसले की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें उन्हें आजीवन कारावास का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई, पीके मिश्रा और केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को शेष जीवन के लिए जेल से रिहा करने से इन्कार करने वाले फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) का उल्लंघन करता है। इस पर पीठ ने कहा कि एक सजा के रूप में इसे लागू किया जा सकता है, जिसे अब पांच न्यायाधीशों द्वारा बरकरार रखा गया है।

क्या उदयनिधि स्टालिन एक तमिल नाम है : एल मुरुगन

एल मुरुगन

> **केंद्रीय मंत्री ने हिंदी थोपने की टिप्पणी पर तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री पर साधा निशाना**

नई दिल्ली, एएनआइ: तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की हिंदी थोपने वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने बुधवार को कहा कि द्रमुक भेदभाव के पक्ष में है। उन्होंने सवाल किया कि क्या उदयनिधि स्टालिन एक तमिल नाम है और कहा कि उन्हें पहले अपने परिवार में तमिल नाम रखना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि कोई भी तमिलनाडु में हिंदी नहीं थोप रहा है। जो लोग हिंदी भाषा पढ़ने के इच्छुक हैं वे पढ़ सकते हैं। आप आपत्ति क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि द्रमुक का मतलब है भेदभाव। वे सामाजिक न्याय की बात करते हैं लेकिन इसका पालन नहीं करेंगे। पीएम मोदी तमिल भाषा को दुनिया भर में ले जा रहे हैं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के यह कहने के बाद विवाद खड़ा हो गया कि दंपतियों को अपने बच्चों के लिए तमिल नाम रखने चाहिए ताकि राज्य में हिंदी थोपे जाने से बचा जा सके। उन्होंने कहा, 'मैं नवविवाहितों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के लिए सुंदर तमिल नाम रखें। कई लोग राज्य में हिंदी थोपने का प्रयास सीधे तौर पर नहीं कर सकते, इसलिए तमिल थाई वाजथु (राज्य गीत) से कुछ शब्द हटा रहे हैं।

न्यूज गैलरी

पीएम ओडिशा में करेंगे 150 फीट की प्रतिमा का शिलान्यास

राउरकेला (ओडिशा) : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिरसा मुंडा जयंती व जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को ओडिशा के राउरकेला में बिरसा मुंडा की 150 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास करेंगे। राउरकेला के ही बिरसा मुंडा स्टेडियम में इस बाबत प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पांच जनजातीय प्रतिभाओं को भी सम्मानित करेंगे। इसी दिन पीएम शहीद माधो सिंह पाकेट खर्च छात्रवृति योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत अनुसूचित जनजाति समुदाय के एक लाख विद्यार्थियों के खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। (जासं)

भरतपुर मेडिकल कालेज में छात्राओं की रैगिंग

जयपुर : राजस्थान में भरतपुर के मेडिकल कालेज में एमबीबीएस की छात्राओं के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। आरोपित कालेज के ही सीनियर छात्र हैं, जो छात्राओं को गाना गाने के लिए मजबूर कर रहे थे। दो दिन तक 13 छात्राओं को रैगिंग कर परेशान किया गया। इस घटनाक्रम का वीडियो पीड़ित छात्राओं के स्वजनों और मेडिकल कालेज प्रशासन तक पहुंचा है। परेशान छात्राओं ने प्राचार्य डा. तरुण लाल से इसकी शिकायत की है। प्राचार्य ने छात्राओं की शिकायत पर जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। बता दें कि इसके पहले भी तीन बार भरतपुर मेडिकल कालेज में छात्र-छात्राओं की रैगिंग के मामले सामने आ चुके हैं। (जासं)

शेयर कारोबार में धोखाधड़ी के आरोप में तीन गिरफ्तार

कोच्चि: केरल के कोच्चि में फेसबुक प्रोफाइल के जरिए शेयर की खरीद-फरोख्त में भारी मुनाफा दिलाने का वादा कर लोगों से 52.22 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को शिकायत के आधार पर अलप्पुझा से अल्ताफ हुसैन और मोहम्मद शियास तथा मलप्पुरम से मोहम्मद शबीब को गिरफ्तार किया गया है। (प्रेट्र)

सेना का दो दिवसीय चाणक्य रक्षा संवाद आज से

नई दिल्ली: भारतीय सेना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीति निर्माण के तहत सुरक्षा गतिशीलता पर चर्चा के लिए गुरुवार से अपने दो दिवसीय प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद 2024 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। अपनी व्यापक चर्चाओं के माध्यम से यह संवाद सैन्य अधिकारियों, नीति निर्माताओं, रणनीतिक विचारकों और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। (आइएएनएस)

जगन मोहन के गुरु को आवंटित जमीन वापस ली

अमरावती: आंध्र प्रदेश में देवेपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने पिछली वाईएसआर कांग्रेस सरकार द्वारा विशाखापत्तनम के पास श्री सारदा पीठम को आवंटित 15 एकड़ जमीन वापस लेने का फैसला किया है, इसकी घोषणा बुधवार को की गई। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। श्री सारदा पीठम के पुजारी स्वरूपानंदेंद्र सरस्वती को पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी का आध्यात्मिक गुरु माना जाता था। (आइएएनएस)

लेंगपुई हवाई अड्डे को वायुसेना को सौंपने का विरोध

आइजल: मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के अध्यक्ष जोरमथंगा ने कहा कि राज्य के एकमात्र लेंगपुई हवाई अड्डे को वायु सेना को सौंपने की किसी भी योजना का उनकी पार्टी विरोध करेगी। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट मुख्य विपक्षी पार्टी है। पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जोरमथांगा ने कहा कि लेंगपुई हवाई अड्डा राज्य को अन्य क्षेत्रों के साथ संपर्क स्थापित करने के स्रोत के तौर पर काम करता है। (प्रेट्र)

श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्वामित्व विवाद : सभी 15 वादों की एक साथ सुनवाई का रास्ता साफ

उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का रिकाल प्रार्थना-पत्र खारिज

वाद विंदु तय करने सहित अन्य अर्जियों की सुनवाई छह को

विधि संवाददाता, जागरण ● प्रयागराज

मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि के स्वामित्व संबंधी सभी 15 सिविल वादों की इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकलपीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का वह रिकाल एप्लीकेशन खारिज कर दिया, जिसमें एक साथ सुनवाई का 11 जनवरी, 2024 का आदेश वापस लेने की मांग की गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिविल वाद बिंदु तय करने सहित अन्य विचाराधीन अर्जियों की सुनवाई के लिए अगली तिथि छह नवंबर तय की गई है।

कोर्ट ने 24 पेज के अपने फैसले में कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 4-ए (पुराने वाद में नए वाद जोड़ने का नियम) के अंतर्गत कोर्ट को समान प्रकृति के वादों की एक साथ समेकित कर सुनवाई करने की शक्ति प्राप्त है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए कोर्ट ने 15 वादों की एक साथ सुनवाई का आदेश दिया है। ऐसा आदेश देने के लिए किसी पक्षकार की सहमति अथवा अनुमति लेने का प्रविधान नहीं है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सभी वादों की एक साथ सुनवाई के आदेश पर विपक्षी की आपत्ति का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। विपक्षी अधिवक्ता नसीरुज्जमा ने कहा था कि वादों को समेकित कर सुनवाई पर कोई आपत्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने भी वादों को समेकित किए जाने पर सहमति दी थी। तीन अन्य वाद भी लंबित थे। उन्हें समेकित नहीं किया गया है। केवल 15 वादों को ही मूल वाद भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के साथ समेकित कर सुनवाई का आदेश दिया गया है। तथ्यों, वाद कारण व अनुतोष के अनुसार वादों को समेकित करने से अदालत व पक्षकारों का समय बचेगा। कोर्ट ने कहा कि वादों के निस्तारण में सुविधा सिद्धांत को देखते हुए पक्षकारों के हित व न्याय हित में आदेश पारित किया गया है। मंदिर पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह, सौरभ तिवारी इत्यादि ने इसे बड़ी जीत माना है और उम्मीद जताई है कि इससे शीघ्रता से न्याय मिल सकेगा।

बता दें, यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन के कार्यकाल का एक बड़ा निर्णय है। वह नवंबर में रिटायर हो रहे हैं।

औरंगजेब के राज में बनाई गई शाही ईदगाह मस्जिद

शाही ईदगाह मस्जिद औरंगजेब के राज में बनाई गई। मंदिर पक्ष का मत है कि भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बना मंदिर तोड़कर इसे बनाया गया। वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, मंदिर प्रबंधन प्राधिकरण और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह के बीच समझौता हुआ। इसमें दोनों पूजास्थलों को एक साथ संचालित करने की अनुमति दी गई। वादियों का तर्क है कि समझौता धोखाधड़ीपूर्ण और कानून की दृष्टि से अमान्य है। मई 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा न्यायालय में लंबित उन सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित विभिन्न राहतों की मांग की गई थी। मस्जिद पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली।

पचास पैसे गोल करने में डाक विभाग पर 15 हजार का जुर्माना

- डाक विभाग सेवा में कमी पर 10 हजार, कानूनी खर्च के 5 हजार दे : उपभोक्ता फोरम
- नकद भुगतान पर रसीद में 50 पैसे कम दिखाए, डिजिटल भुगतान स्वीकार नहीं हुआ

चेन्नई, प्रेट्र : भारतीय डाक सेवा को एक उपभोक्ता को पचास पैसे राउंड आफ (पूर्णांक) करना महंगा पड़ा। उसके बदले में उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता को रिफंड लौटाने के साथ ही इस सरकारी विभाग पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हर्जाने के तौर पर दस हजार रुपये मानसिक परेशानी, गलत व्यापारिक तरीकों और सेवा में कमी के चलते वसूले गए हैं।

कांचीपुरम जिले में एक उपभोक्ता फोरम ने डाक विभाग को पांच हजार रुपये बतौर अदालती कार्यवाही पर हुए खर्च के लिए देने को कहा है। शिकायतकर्ता ए.मनाशा के अनुसार उसने 13 दिसंबर, 2023 को 30 रुपये नकद देकर पोझिचालुर पोस्ट आफिस से एक रजिस्टर्ड डाक भेजनी थी। लेकिन उसकी रसीद पर केवल 29.50 रुपये की रकम दिखा रही थी। लिहाजा, उसने वह पूरी रकम यूपीआइ के जरिये देने की पेशकश की लेकिन उसमें भी कुछ तकनीकी कारणों से डाक के भुगतान को डिक्लाइन दिखा रहा था। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि प्रतिदिन लाखों लेन-देन होते हैं, अगर पूरी धनराशि लेकर भी कम दिखाई जाती रही तो सरकार को राजस्व का बहुत नुकसान होगा। उन्होंने इसे अवैध करार देते हुए इससे उन्हें गंभीर मानसिक परेशानी की बात कही। डाक विभाग ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उस समय कुछ तकनीकी कारणों से डिजिटल भुगतान स्वीकार नहीं हो रहा था। इसलिए उनसे कैश लिया गया था। उन्होंने बताया कि पोस्टल साफ्टवेयर में स्वतः ही 50 पैसे राउंड आफ हो रहे थे। जबकि वह राशि काउंटर एकाउंट सबमिशन में अलग से दिखा रही थी, इसलिए उनकी शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

मनाशा ने कहा कि भारतीय डाकघर की रोजाना के लेन-देन को राउंड आफ करने की कथित प्रथा से बड़ी मात्रा में पैसे की हेराफेरी हो सकती है। यहां तक कि काला धन और सरकार को जीएसटी राजस्व का नुकसान भी हो सकता है। डाकघर ने कहा कि 50 पैसे से कम की राशि को हमेशा 'नजरअंदाज' किया जाता है। साथ ही साफ्टवेयर ऐसी किसी भी राशि को निकटतम रुपये में बदल देता है।

राज्यों को है इंडस्ट्रियल अल्कोहल के नियमन का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

- शीर्ष कोर्ट ने 8 :1 के बहुमत से अपना 1990 का सात सदस्यीय पीठ का फैसला पलटा

राज्य सूची में 'इंटोक्सिकेटिंग लिकर' में इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्यों को इंडस्ट्रियल अल्कोहल के उत्पादन, विनिर्माण एवं आपूर्ति के नियमन का अधिकार है। 8:1 के बहुमत वाले इस फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि आठ में 'इंटोक्सिकेटिंग लिकर' के दायरे में इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी शामिल होगी।

नौ सदस्यीय पीठ में बहुमत का फैसला लिखने वाले जजों में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस हृषिकेश राय, अभय एस. ओका, जेबी पार्डीवाला, मनोज मिश्रा, उज्जल भुइयां, सतीश चंद्र शर्मा और अगस्टीन जार्ज मसीह शामिल थे। जबकि जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई और अपने 238 पृष्ठों के फैसले में कहा कि राज्यों के पास इंडस्ट्रियल अल्कोहल के नियमन की शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इस वजह से राज्यों को इंडस्ट्रियल अल्कोहल के नियमन का अधिकार नहीं मिल जाता क्योंकि इसे एक प्रोसेस के जरिये मानव उपभोग लायक अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के इस फैसले से अपना 1990 का सिंथेटिक्स एंड कैमिकल लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिया गया सात जजों की पीठ का फैसले पलट दिया है। उस फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल के उत्पादन पर नियामक शक्तियां केंद्र के पास हैं। एथिल अल्कोहल (इसमें 95 प्रतिशत ऐथेनाल होती है) अल्कोहल का औद्योगिक स्वरूप होता है और यह मनुष्यों के उपभोग के लिए अनुपयुक्त होता है।

बहुमत का फैसला लिखने वाले प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि प्रविष्टि आठ के तहत 'इंटोक्सिकेटिंग लिकर' के कच्चे माल से लेकर उत्पादन तक सभी चीजों का नियमन होता है। पीठ ने 364 पृष्ठों के अपने फैसले में कहा, 'सूची एक की प्रविष्टि 52 के तहत सिर्फ घोषणा करके संसद पूरे उद्योग को अपने दायरे में नहीं ला सकती। सूची दो की प्रविष्टि 24 के तहत राज्य विधानसभा की शक्तियां सूची एक की प्रविष्टि 52 के तहत संसद द्वारा बनाए कानून द्वारा कवर किए गए क्षेत्र तक ही है।' पीठ ने कहा कि संसद के पास इंटोक्सिकेटिंग लिकर के उद्योग पर नियंत्रण का कानून बनाने की विधायी शक्ति नहीं है। बहुमत के फैसले में कहा गया है कि प्रविष्टि आठ में शब्द 'इंटोक्सिकेटिंग लिकर' में ऐसे सभी अल्कोहालिक लिक्विड शामिल हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं।

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 11वां आरोपित कैथल से गिरफ्तार

- अमित को गिरफ्तार कर साथ ले गई मुंबई क्राइम ब्रांच
- जीशान को करनाल में किराये पर दिलाया था मकान

जागरण संवाददाता, कैथल

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अमित उर्फ नाथी को हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने जाशीन अख्तर को फरारी के दौरान करनाल में किराये के एक मकान में शरण दी थी। सिद्दीकी की हत्या से दो महीने पहले दोनों बदमाश 15 दिन साथ रहे थे।

कैथल जिले के गांव बात्ता के रहने वाले 29 वर्षीय अमित पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या के एक मामले में जाशीन अख्तर करीब 15 महीने तक कैथल जेल में रहा था। कलायत के एक व्यापारी पर गोली चलाने के मामले में पुलिस जाशीन को 21 अगस्त, 2022 को पंजाब की कपूरथला जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई थी। सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर गुरमेल सिंह लगभग 15 महीने तक जेल में रहा था, जहां जाशीन और गुरमेल में दोस्ती हुई थी।

काट रहा था फरारी

जेल से बाहर आने के बाद जाशीन ने सिद्दीकी हत्याकांड से पहले करीब डेढ़ महीने तक कैथल में फरारी काटी थी। वह अगस्त और सितंबर में शहर के एक होटल और निजी संस्थान में रहा था। उसने कुछ दिन गांव हरसौला में भी बिताए। वह जिन-जिन के संपर्क में आया था मुंबई क्राइम ब्रांच उन सभी से दो दिनों तक पूछताछ की। मिड-डे के मुताबिक, मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी (डिटेक्शन) दत्ता नलावडे ने कहा, "सिद्दीकी की हत्या के मामले में अमित की भूमिका स्थापित हो गई है। उसने न केवल मुख्य साजिशकर्ता को शूटरों से जोड़ा, बल्कि पूरी साजिश में भी शामिल था।

सलमान से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : फिल्म अभिनेता सलमान खान से पांच करोड़ रुपये रंगदारी मांगने और नहीं देने पर बाबा सिद्दीकी से भी बदतर स्थिति करने की धमकी देने के आरोपित शेख हुसैन को मुंबई की जुहू डीसीबी पुलिस ने झारखंड के जमशेदपुर से बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। वह जमशेदपुर में सब्जी बेचता था। पुलिस ने शेख हुसैन के पास से उस मोबाइल को भी जब्त किया हैं जिससे मुंबई की ट्रैफिक पुलिस को वाट्सएप पर गुरुवार को एक धमकी भरा संदेश मिला था, संदेश में बालीवुड अभिनेता सलमान खान से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी। संदेश में जेल में बंद गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के साथ उनके विवाद को सुलझाने का दावा किया गया था। उसने बताया कि बीते कई दिनों से टीवी पर सलमान की हत्या कराने की खबरें चल रही थी। वह इन्हीं खबरों को देखा करता था। उसने सोचा की इसी बहाने वह सलमान खान से रंगदारी मांगने का मैसेज कर मामले को तूल पकड़ा सकता है।

कहां मिलेगा मौसम का पूर्वानुमान

प्रथम पृष्ठ से आगे

मौसम का पूर्वानुमान पंचायतीराज मंत्रालय के डिजिटल मंचों-ई-ग्रामस्वराज, मेरी पंचायत एप और ग्राम मानचित्र के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इसके लिए मोबाइल पर संबंधित एप को डाउनलोड करना होगा।

इन मंचों पर ग्राम पंचायतों को तापमान, वर्षा, हवा की गति और बादल छाए रहने के बारे में दैनिक जानकारी मिलेगी। इससे किसानों को बुवाई, सिंचाई और कटाई की गतिविधियों की योजना बनाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चक्रवात और भारी वर्षा जैसी चरम मौसम स्थितियों के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों को एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे, जिससे लोगों की जान, फसल और संपत्ति की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

नीट पेपर लीक के आरोपित संजीव के पास आय से 144% अधिक संपत्ति

- नालंदा में स्वजन के नाम पर खरीदी जमीन, वित्तीय संस्थानों में लगाई काली कमाई

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना

नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया ने स्वजन के नाम पर कई अवैध संपत्तियां अर्जित की हैं। आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी में संजीव के पास आय से 144 प्रतिशत अधिक संपत्ति मिली है। इसमें स्वजन के नाम पर जमीन के साथ कई वित्तीय संस्थानों में निवेश के कागजात मिले हैं। इसके अलावा छापेमारी में साढ़े 11 लाख नकद राशि भी मिली है।

संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया नालंदा के नालंदा उद्यान महाविद्यालय में तकनीकी सहायक के पद पर है। इसी पद का दुरुपयोग कर संजीव पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस सूचना के सत्यापन के बाद ईओयू ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में संजीव पर प्राथमिकी दर्ज की और फिर मंगलवार को पटना और नालंदा के चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।

ईओयू के अनुसार संजीव के ठिकानों पर छापेमारी में नालंदा में जमीन खरीद के कागजात मिले हैं। साथ ही सोने-चांदी के जेवरात और बर्तन, एक दर्जन से ज्यादा मोबाइल और लैपटाप, कई बीमा पालिसियों में निवेश के कागजात, वित्तीय संस्थाओं में निवेश के कागजात और वित्तीय लेन-देन के कागज मिले हैं। संपत्तियों के लीज और एकरारनामे के कागजात भी बरामद किए गए हैं। संजीव और स्वजन के नाम पर बाइक, कार और 16 पहिया के ट्रक जैसे वाहनों की खरीद के कागजात भी मिले हैं। मालूम हो कि संजीव का नाम नीट पेपर लीक समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं की गड़बड़ी में आया है। मामले में उसके बेटे डा. शिव समेत कई सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि संजीव मुखिया लंबे समय से फरार है।

डाक सहायक पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा

सीबीआइ ने छपरा प्रधान डाकघर में डाक सहायक के पद पर तैनात जैनेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ ने पुख्ता जानकारी प्राप्त करने के बाद जैनेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी सीबीआइ को जानकारी मिली थी कि छपरा में डाक सहायक के पद पर पदस्थापित जैनेंद्र कुमार ने पहली नवंबर 2011 से 31 दिसंबर 2023 के बीच अपने पदस्थापन की अवधि में सभी स्रोतों से अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। उक्त अवधि के दौरान जैनेंद्र को अपने वेतन से 80,85,042 रुपये की शुद्ध आय हुई। जबकि उक्त अवधि के दौरान उन्होंने 1,24,74,993 रुपये की संपत्ति अर्जित की।

63 फीट ऊंची रामांजनेय मूर्ति

बेंगलुरु में बुधवार को राजाजीनगर स्थित राममंदिर में 63 फीट ऊंची रामांजनेय मूर्ति का लोकार्पण हुआ। यह हनुमान जी के साथ भगवान राम की मूर्ति है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए पहुंचे। अंजना पुत्र हनुमान जी को आंजनेय भी कहा जाता है। प्रेट्र

जवाब देते रहे मुख्य सचिव, किसानों ने 384 स्थानों पर जला दी पराली

- हरियाणा में 33 और नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस, पांच कृषि अधिकारी निलंबित

सुधीर तंवर ● जागरण

चंडीगढ़ : हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव बुधवार को पराली जलाने वाले किसानों और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे रहे थे तो दूसरी तरफ इससे बेपरवाह किसान पराली जलाने में मशगूल थे। एक ही दिन में हरियाणा में 15 तो पंजाब में 57 किसानों ने पराली जलाई। उत्तर प्रदेश में 68, राजस्थान में 50 और मध्य प्रदेश में 194 किसानों ने पराली में आग लगाई है। 24 घंटों में 384 स्थानों पर पराली जलाने की घटनाएं सामने आईं।

उत्तर भारत में अभी तक 4262 स्थानों पर पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। हरियाणा में 680 स्थानों पर पराली जलाई गई है। पंजाब में दो गुना से ज्यादा 1638 स्थानों पर पराली जली है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 808, राजस्थान में 382, दिल्ली में 11 और मध्य प्रदेश में 743 स्थानों पर पराली में आग लगाई गई है। बुधवार को पराली जलाने के मामलों पर अंकुश नहीं लगाने के आरोप में कुरुक्षेत्र में पांच और कृषि अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया, जबकि पूरे प्रदेश में 33 अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए। इनमें करनाल के 24, पंचकूला के तीन, सोनीपत के चार और रोहतक के दो अधिकारी शामिल हैं। इस दौरान 46 और किसानों के दस्तावेजों में रेड एंट्री की गई। हरियाणा में अभी तक 357 किसानों पर रेड एंट्री की कार्रवाई हुई है, जिस कारण वे अगले दो साल तक अपनी फसल एमएसपी पर नहीं बेच पाएंगे।

प्रदूषण मुक्त वातावरण नागरिकों का मौलिक अधिकार

अमृतसर के बाहरी क्षेत्र में एक खेत में पराली जलाता किसान। प्रेट्र

प्रथम पृष्ठ से आगे

शीर्ष कोर्ट ने कहा -'अब समय आ गया है कि केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकारों को याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। पर्यावरण प्रदूषण अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के मौलिक अधिकार के घोर उल्लंघन का मामला है। यह सिर्फ आयोग के आदेशों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि सरकार को खुद जवाब देना होगा कि वह नागरिकों के प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार की रक्षा कैसे करेगी? यह मुकदमा हमारे लिए सिर्फ यह सुनिश्चित करने का है कि नागरिकों का सम्मान और स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार कायम रहे।'

शीर्ष कोर्ट ने पूछा- पराली जलाने पर जुर्माना इतना कम क्यों? : कोर्ट ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने और नाममात्र का जुर्माना वसूल कर छोड़ दिए जाने पर सवाल उठाया। पूछा- जुर्माना इतना कम क्यों है। जब सीएक्यूएम की ओर से बताया गया कि यह राशि एनजीटी ने तय की है तो कोर्ट का सवाल था कि एनजीटी को क्यों तय करना पड़ा? ये तो आयोग को तय करना चाहिए था। कोर्ट ने आयोग को जुर्माने की राशि बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। बता दें, खस्ताहाल सड़कें और उड़ने वाली धूल, वाहनों की बढ़ती संख्या और पुरानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है।

पीठ ने पंजाब से कहा

इस साल पंजाब में पराली जलाने के 1084 मामले सामने आए हैं और केवल 473 लोगों से जुर्माना वसूला गया है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। राज्य कानून के प्रविधानों को लागू करने में मनमाने तरीके अपना रहा है।

कोर्ट ने हरियाणा से कहा

राज्य में पराली जलाने के 419 मामले सामने आए हैं और सिर्फ 32 दोषियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। 320 लोगों से नाममात्र का जुर्माना वसूला गया है। यह ढिलाई नहीं तो फिर क्या है?

'प्रधानपति कल्चर' को हतोत्साहित किया जाना चाहिए : हाई कोर्ट

- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा-ग्रामीणों की सहमति से गांव सभा की लोकोपयोगी जमीन का अन्य लोकहित में इस्तेमाल हो

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम प्रधानों खासकर महिला प्रधानों के अधिकार व कर्तव्य को लेकर तीन महीने के भीतर मंडलवार प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 'प्रधानपति कल्चर' को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब गांव सभा की लोकोपयोगी जमीन, दूसरे लोकोपयोगी कार्य के लिए ली जाए तो ग्रामीणों की सहमति हो ताकि लोग किसी सार्वजनिक इस्तेमाल की जमीन का अन्य लोकहित में इस्तेमाल होने के खिलाफ हाई कोर्ट में न आएं।

इस टिप्पणी के साथ एकल पीठ ने अपने आदेश में गाजीपुर के अंबिका यादव व व कई अन्य की तरफ से दाखिल जनहित याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने गांव सभा की चारागाह, नवीन परती, गड़ही व खलिहान की जमीन पर पानी टंकी व आरसीसी सेंटर निर्माण को जनहित में मानते हुए हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है, हालांकि कहा है कि यदि निर्माण शुरू न किया गया हो तो इसे किनारे शिफ्ट किया जाए।

सरकार की तरफ से कहा गया कि चारागाह की जमीन के छोटे हिस्से पर पानी टंकी बनने से जमीन की नवैयत (प्रकार) नहीं बदलेगी। लोकोपयोगी जमीन पर किसी को भूमिधरी अधिकार नहीं मिलेगा। कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि ग्राम प्रधान या परिवार या अन्य द्वारा यदि अतिक्रमण किया गया है तो एक महीने में कार्रवाई की जाए।

****

14.82 लाख अराजपत्रित राज्यकर्मियों को दीपावली पर बोनस देगी उत्तर प्रदेश सरकार। इस तरह हर कर्मचारी को 6,908 रुपये बोनस मिलेगा। 1,727 रुपये नकद मिलेंगे, 75 प्रतिशत धनराशि जीपीएफ में जमा होगी।

न्यूज गैलरी

बिहार में आइएएस अधिकारी सात दिनों की रिमांड पर

पटना: भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस को विशेष कोर्ट ने बुधवार को सात दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर देने का आदेश पारित किया है। कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिए हैं कि वह दो दिनों के अंदर संजीव हंस को अपनी रिमांड पर ले लें। भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग मामले में हंस के साथ फंसे राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव को रिमांड पर देने के संबंध में गुरुवार को सुनवाई होगी। (राब्यू)

बिहार में पहली बार सरकारी विद्यालयों की होगी रैंकिंग

पटना : बिहार में पहली बार सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग होगी। नवंबर के पहले सप्ताह से शिक्षा विभाग बिहार के सभी 81 हजार सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग प्रक्रिया शुरू करेगा। यह रैंकिंग प्रतिवर्ष नवंबर एवं मार्च में होनी है। बिहार में 43 हजार प्राथमिक विद्यालय हैं, जहां पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। 29 हजार मध्य विद्यालय हैं, जहां पहली से आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। नौ हजार 360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जहां नौवीं से बारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। रैंकिंग हेतु प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग-अलग फार्मेट जारी किए गए हैं। (राब्यू)

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी सख्त हिदायत

नई दिल्ली : लखीमपुर खीरी 2021 हिंसा मामले में हत्या के आरोपित पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वह जमानत की शर्तों का सख्ती से पालन करें। पीठ ने मिश्रा के अधिवक्ता से कहा कि जमानत शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। पीड़ितों के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को जमानत की शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया था, लेकिन वह एक अक्टूबर को वहां (लखीमपुर खीरी) ऐसे गए जैसे दो अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश वाले दिन सुनवाई हो। (प्रेट्र)

'बदलापुर यौन शोषण में दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई'

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से ठाणे जिले के बदलापुर क्षेत्र में एक स्कूल में दो बच्चियों के यौन शोषण के मामले की जांच और प्राथमिकी दर्ज करने में चूक पर जवाब तलब किया है। उसने पूछा है कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने कहा कि बदलापुर के दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या विभागीय जांच की गई है। (प्रेट्र)

आज ओडिशा पहुंचेगा 'दाना' तूफान

एनडीआरएफ की 288 टीमें तैनात, ओडिशा में 10 लाख को सुरक्षित पहुंचाने में जुटे बचाव दल

बंगाल-ओडिशा समेत कई राज्यों में 24-25 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना

जागरण टीम, भुवनेश्वर

'दाना' तूफान को लेकर 25 अक्टूबर तक हर ओर सतर्कता बढ़ी हुई है। ओडिशा और बंगाल में तूफान से बचाव की व्यापक तैयारियां की गई हैं। ओडिशा में एनडीआरएफ की 288 टीमें तैनात की गई हैं। तूफान की भयावहता का अंदाजा लगाते हुए 14 जिलों से 10 लाख लोगों को सुरक्षित शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। इस तूफान का असर ओडिशा से लेकर बंगाल, बिहार और झारखंड तक दिख सकता है। पुरी में तूफान के राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच सतह से टकराने की संभावना है।

बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवात का रूप धारण कर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। अभी यह पारादीप से 560 और सागरद्वीप से 630 किलोमीटर दूरी पर है। गुरुवार 24 अक्टूबर की रात या शुक्रवार 25 अक्टूबर की सुबह यह पुरी समुद्रतट और बंगाल के सागरद्वीप तट से टकराएगा। इस दौरान हवा की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रतिघंटे हो सकती है। मौसम विभाग ने बंगाल-ओडिशा समेत कई राज्यों में 24 और 25 अक्टूबर को भारी बारिश होने की संभावना जताई है। एनडीआरएफ के सेकंड इन कमान टूआइसी बर्द्धमान मिश्रा के अनुसार, एनडीआरएफ को तटवर्ती जिले में तैनात किया गया है। ओडिशा के सात जिलों में तूफान और भारी वर्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। दक्षिण-पूर्व रेलवे ने अगले तीन दिनों के लिए लगभग 300 ट्रेनें रद कर दी हैं।

मंत्रियों को दी जिम्मेदारी : ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने बुधवार को तूफान से बचाव के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाकर नौ मंत्रियों व नौ वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों को राहत व बचाव कार्यों की कार्ययोजना व निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है।

राज्य सरकार ने आपदा राहत बल को तैनात करते हुए स्कूल-कालेजों को बंदकर सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद कर दी है। पर्यटकों के लिए भी चेतावनी जारी करते हुए उन्हें समुद्र तट की ओर से जाने से मना कियाहै। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व समारोहों पर तूफान थमने तक के लिए रोक लगा दी गई है। विभिन्न समुद्री तटों पर धारा 144 लगा दी गई है।

कटक में एनडीआरएफ तीसरी बटालियन से तटवर्ती इलाकों के लिए रवाना किए जाते जवान। जागरण

हमने कई तूफान झेले, घबराएं नहीं लोग : पटनायक

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील की है कि तूफान से उन्हें घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी सुरक्षित रहें और सावधानी बरतें। हमने कई तूफान झेले हैं और इस बार भी बेहतर ढंग से सामना करेंगे।

'दाना' तूफान के कारण बुधवार को ओडिशा के बालेश्वर में नावों को घाट पर बांध दिया गया। प्रेट्र

अब सोलन में मजार पर विवाद, हटाने की मांग

जागरण संवाददाता, सोलन

- देवभूमि संघर्ष समिति का आरोप, कब्जा दिखाने के लिए चिल्ड्रेन पार्क में बनाई मजार

शिमला के उपनगर संजौली और मंडी के जेल रोड मस्जिद विवाद के बाद अब सोलन शहर में मजार को लेकर विवाद सामने आया है। देवभूमि संघर्ष समिति का आरोप है कि चिल्ड्रेन पार्क के पास अवैध तरीके से मजार का निर्माण किया गया है। प्रशासन को चेतावनी दी कि जांच के बाद इसे हटाएं अन्यथा शिमला की तर्ज पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देवभूमि संघर्ष समिति सोलन के संयोजक नीरज ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आजादी से पहले इस जगह को कब्रिस्तान कहा जाता था। उस समय यह भूमि बघाट रियासत की थी और मुस्लिम समुदाय का अवैध कब्जा था। 1995 से पहले सोलन प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के बीच समझौता हुआ था। इसके अनुसार समुदाय ने यह जगह चिल्ड्रेन पार्क बनाने के लिए छोड़ने को कहा था। इसके बदले मुस्लिम समुदाय को 13 बीघा भूमि दी गई। इसके बावजूद समुदाय ने कब्जा दिखाने के लिए अवैध तरीके से मजार बना दी। नीरज ने जिला प्रशासन से इसकी जांच करवाने और अवैध कब्जा हटाने की मांग की है।

संजौली में अवैध निर्माण गिराने में मदद के लिए तैयार : नीरज ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें पता चला है कि संजौली मस्जिद कमेटी को मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने के लिए मजदूर और पैसे की कमी का सामना करना पड़ रहा है। समिति उनका साथ देने के लिए तैयार है उन्हें केवल एक घंटे का समय दें। समिति प्रदेश के सभी सदस्यों के साथ मिलकर अवैध हिस्से को गिरा देगी।

दुकानों के बाहर नाम व पता लिखने में सरकार को नोटिस

जागरण संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दुकानों के बाहर नाम-पता लिखने को लेकर दो मंत्रियों की ओर से दिए बयान के पश्चात सामाजिक तनाव पैदा होने की आशंका को लेकर दायर जनहित याचिका पर प्रदेश सरकार और नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार और नगर निगम से तीन सप्ताह के भीतर याचिका का जवाब तलब किया है। जनहित याचिका में कहा है कि हिमाचल के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर दुकानों के बाहर नाम-पता लिखने का आदेश जारी करने का निर्णय लिया है।

बंगाल में बच्ची से दुष्कर्म, जिंदा जलाया

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी

- मुख्य आरोपित गिरफ्त में, आठ दिन पहले बच्ची को ले गया था अपने साथ
- आरोपितों को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया

बंगाल में दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं लगातार घट रही है। पहले आरजी कर अस्पताल फिर कृष्णानगर और अब जयगांव। अलीपुरद्वार जिले के जयगांव में एक सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसे जिंदा जलाने की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक वाई. रघुवंशी ने कहा कि इस जघन्य अपराध के आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सुबूत जुटाए जा रहे हैं। मुख्य आरोपित के शरीर पर पीड़िता के नाखून के खरोंच के निशान मिले हैं। डीएनए जांच में इससे मदद मिलेगी। फोरेंसिक टीम को भी जांच में लगाया गया है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि आठ दिन से लापता बच्ची का जला हुआ शव मंगलवार को बरामद किया गया। जानकारी मिलने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग में गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। सड़क बंदकर प्रदर्शन किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। एएसपी मानवेंद्र दास के अलावा एसडीपीओ और अन्य बड़े अधिकारियों ने स्वयं मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रित किया। स्वजन का कहना है कि बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसे जलाकर मार डाला गया है। जांच में जुटी पुलिस ने सबसे पहले मुख्य आरोपित बबलू मियां को गिरफ्तार किया। वही आठ दिन पहले बच्ची को अपने साथ ले गया था। उसका बच्ची के घर आना-जाना था। उसके बाद बुधवार को दो और आरोपितों की गिरफ्तारी हुई। तीनों आरोपितों को अलीपुरद्वार कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया है।

भाजपा ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। वह बुधवार को जब पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तो पुलिस ने उनको रोक दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी मुख्यमंत्री को घेरा।

उत्तराखंड में शिक्षक ने छात्रा का अपहरण कर किया दुष्कर्म

संवाद सूत्र, जागरण, अल्मोड़ा : उत्तराखंड में अल्मोड़ा के चौखुटिया क्षेत्र के सरकारी स्कूल में पदस्थ अतिथि शिक्षक द्वारा मंगलवार को दूसरे स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपित शिक्षक कमालुद्दीन को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे बुधवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी मंगलवार दोपहर स्टेशनरी लेने बाजार गई थी। जब शाम तक वह नहीं लौटी तो उन्होंने पूछताछ शुरू की। एक व्यक्ति ने बताया कि बच्ची को उसके पहले के स्कूल के एक शिक्षक को बाइक पर ले जाते देखा है।

ओटीटी प्लेटफार्म की नकारात्मक सामग्री पर मंथन करेगा संघ

जागरण संवाददाता, मथुरा

- कल से होने वाली दो दिवसीय कार्यकारी मंडल की बैठक में चर्चा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 25 व 26 अक्टूबर को बैठक होगी। इसमें इंटरनेट के ओटीटी प्लेटफार्म पर उपलब्ध सामग्री से बच्चों के मन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव पर भी मंथन होगा। विजयदशमी पर संघ डा. प्रमुख मोहन भागवत ने अपने उद्बोधन में इसे नैतिक भ्रष्टाचार करार दिया था। पंच परिवर्तन के साथ संघ शताब्दी वर्ष में अपना कार्य विस्तार करेगा।

दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र गऊ ग्राम परखम में होने वाली बैठक में 393 संघ कार्यकर्ता शामिल होंगे। बुधवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि बैठक में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में निर्धारित वार्षिक योजना की समीक्षा तथा संघ कार्य के विस्तार का वृत्तांत भी लिया जाएगा। संगठनात्मक लक्ष्यों को अगले वर्ष विजयदशमी से पूर्व पूर्ण करने पर भी विचार होगा। अगली विजयदशमी पर संघ स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। तब नागपुर समेत देशभर में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इस पर भी बैठक में चर्चा होगी। गत विजयदशमी पर संघ प्रमुख डा. मोहन भागवत ने अपने उद्बोधन में कई विषयों पर ध्यान दिलाया है। इसमें एक है इंटरनेट पर ओटीटी में उपलब्ध नकारात्मक सामग्री। इस पर व्यापक चर्चा होगी। महर्षि दयानंद सरस्वती, भगवान बिरसामुंडा, अहिल्याबाई होल्कर, रानी दुर्गावती, झारखंड में अनुकूल चंद ठाकुर द्वारा संचालित सत्संग संस्था का भी उल्लेख संघ प्रमुख ने उद्बोधन में किया था। इस पर भी चर्चा होगी।

इसके अलावा पंच परिवर्तन में सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य को भी समाज में ले जाए जाने पर भी चर्चा होगी। बैठक में संघ प्रमुख के साथ ही अखिल भारतीय स्तर के पदाधिकारी, 46 प्रांतों के प्रांत प्रमुख लोग उपस्थित रहेंगे।

चकेरी और डुमना एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी, मुकदमा दर्ज

जागरण टीम, नई दिल्ली : वाराणसी, जयपुर और नागपुर समेत देश के कई एयरपोर्टों को उड़ाने की धमकी के बाद अब कानपुर के चकेरी और जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है। इस मामले में चकेरी और खमिरिया थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई। चकेरी एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे सीआइएसएफ के सहायक कमांडेंट केएस राठौर के मुताबिक चार से छह अक्टूबर तक सीआइएसएफ के विशेष विमानन सुरक्षा समूह कानपुर की ईमेल पर तीन धमकी भरे संदेश आए। सभी ईमेल में चकेरी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को देने के बाद बुधवार को थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। उधर, डुमना एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारी रजत बांगड़े द्वारा खमरिया थाने में दर्ज रिपोर्ट दर्ज के अनुसार 20 अक्टूबर को एक्स पर पोस्ट कर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस ने अज्ञात पर वायुयान सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।

दिव्यांग कंपार्टमेंट की सीटें भी होंगी आरक्षित

प्रेम नारायण द्विवेदी ● जागरण

- स्लीपर की श्रेणी में रखे जाएंगे कोच, दिव्यांगजन व उनके सहचर के लिए आवंटित होंगी चार सीटें

गोरखपुर: दुरंतो एक्सप्रेस जैसी पूरी तरह आरक्षित ट्रेनों (राजधानी, शताब्दी और हमसफर आदि) के एलएचबी सेकेंड लगेज गार्ड एंड दिव्यांग कंपार्टमेंट (एलएसएलएआरडी) की सीटें भी आरक्षित होंगी। रेलवे बोर्ड ने इन कोचों को भी स्लीपर (शयनयान) श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है।

हालांकि, इन कोचों में दिव्यांगजन और उनके सहचर के लिए चार सीटें शयनयान वाली आवंटित की जाएंगी, लेकिन शेष सीटें सामान्य यात्रियों के लिए जनरल चेयर कार (टू एस) के रूप में आरक्षित होंगी। सामान्य यात्रियों से किराया शयनयान वाला ही वसूला जाएगा। अलबत्ता, अन्य कोचों की भांति इनमें भी खानपान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे बोर्ड के इस फैसले से आरक्षित ट्रेनों में जनरल श्रेणी के भी 30 से 40 यात्रियों को कन्फर्म सीटें मिल जाएंगी।

रेलवे बोर्ड के निदेशक (यात्री विपणन-सेकेंड) संजय मनोचा ने सभी क्षेत्रीय रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों (पीसीसीएम) को पत्र लिखकर

प्रतीकात्मक।

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड के निदेशक ने पत्र के माध्यम से एलएसएलआरडी में भी यात्रियों को आरक्षित स्थान उपलब्ध कराने तथा खानपान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है।

नई व्यवस्था के अनुसार एलएसएलआरडी में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित चार सीटों वाले हिस्से में दो नीचे वाली सीटें दिव्यांगजनों के लिए तथा दो ऊपर वाली सीटें उनके सहचरों के लिए आवंटित होंगी। इन कोचों की पहचान डीडी-1 के रूप में होगी। 30/31 या अधिक सीट वाले दूसरे हिस्से को सामान्य यात्रियों के लिए निर्धारित किया जाएगा। इस कोच की पहचान डीएल-1 के रूप में होगी।

दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित एलएसएलआरडी को स्लीपर श्रेणी में रूप रखा जाएगा। सामान्य यात्रियों को टू एस के रूप में सीटों की बुकिंग की जाएगी। इन सीटों का किराया स्लीपर श्रेणी के रूप में ही वसूला जाएगा। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनों के एलएसएलआरडी में भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी। एलएसएलआरडी के आधे हिस्से में गार्ड यान होता है। आधा हिस्सा दिव्यांगजन या महिलाओं के लिए आरक्षित होता है।

यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्ण रूप से आरक्षित ट्रेनों में लगाए जा रहे एलएसएलआरडी में उपलब्ध अतिरिक्त सीटों के लिए इसे टू एस आरक्षित श्रेणी में बुकिंग करने के दिशा निर्देश जारी हुए हैं। इसमें दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित एलएसएलआरडी के हिस्से को स्लीपर श्रेणी माना जाएगा। इस व्यवस्था से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी।

– पंकज कुमार सिंह, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे

शेट्टी हत्याकांड में छोटा राजन को जमानत, उम्रकैद भी निलंबित

मुंबई, एएनआइ: बांबे हाई कोर्ट ने मुंबई के होटल मालिक जया शेट्टी के 2001 के हत्याकांड में गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकाल्जे उर्फ छोटा राजन की उम्रकैद को स्थगित करके उसे जमानत दे दी है। इसके बावजूद छोटा राजन के दिल्ली के तिहाड़ जेल से जल्दी छूटने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उस पर क्राइम रिपोर्टर जे.डे की हत्या समेत कई अन्य शहरों में और भी कई मामले चल रहे हैं।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने बुधवार को छोटा राजन को एक लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी है।

इसी साल मई में एक विशेष अदालत ने होटल मालिक की हत्या के इस मामले में छोटा राजन को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ छोटा राजन ने हाई कोर्ट में अपील की थी। उसने सजा को निलंबित करने के साथ ही अंतरिम जमानत मांगी थी। उल्लेखनीय है कि चार मई, 2001 को सेंट्रल मुंबई स्थित गामदेवी के गोल्डन क्राउन होटल के मालिक जया शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

बंगाल के राशन आवंटन घोटाले में 14 जगहों पर ईडी ने की छापेमारी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- व्यवसायियों, राशन डीलरों के विभिन्न ठिकानों पर तलाशी
- केंद्रीय एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए

बंगाल के राशन आवंटन घोटाले में बुधवार को ईडी ने कोलकाता तथा इसके आसपास के जिलों में 14 जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारियों ने व्यवसायियों, राशन डीलरों के विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं।

सबसे पहले ईडी की टीम ने कोलकाता में व्यवसायी महेंद्र अग्रवाल के दो आवासों पर और फिर हावड़ा में कई जगहों पर छापेमारी की। राशन डीलर लोकनाथ साहा के घर व गोदाम पर भी छापेमारी की गई। इसके अलावा उत्तर जगदीशपुर में राशन डीलर के कई गोदामों पर छापेमारी की गई। अधिकारियों ने जगतबल्लबपुर सहकारी कृषि विकास समिति के कार्यालय का भी दौरा किया। उन्होंने उत्तर 24 परगना के गायघाटा में एक राशन गोदाम पर भी छापा मारा। गौरतलब है कि बीते सितंबर माह में ईडी ने राशन आवंटन घोटाले में राज्य में सात जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था।

1000 करोड़ रुपये का है घोटाला : इस घोटाले में राशन सामग्रियां सस्ती कीमत पर चावल मिल मालिकों को आपूर्ति की गई थी तथा बाद में उन्होंने इसे पैकेटबंद कर ऊंचे दाम पर खुले बाजार में बेचा था। केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि घोटाले में 1000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने 28 सितंबर को मामले में अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी की चार्जशीट में कुल आठ नाम हैं।

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री के परिसरों पर ईडी के छापे

चेन्नई, प्रेट्र: ईडी ने बुधवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और अन्नाद्रमुक विधायक आर वैथिलिंगम और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापे मारे। यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग के एक मामले की जांच में की गई है। वैथिलिंगम अन्नाद्रमुक सरकार में मंत्री रहे।

चेन्नई और तंजावुर में वैथिलिंगम के आवास समेत राज्य के चार शहरों में मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रविधानों के तहत छापेमारी की जा रही है। विधानसभा में ओराथानाडु सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले 69 वर्षीय वैथिलिंगम के समर्थक उनके घर के बाहर उस समय जमा रहे, जब ईडी छापा मार रही थी। इस दौरान सीआरपीएफ की सुरक्षा टीम भी मौजूद रही। मनी लांड्रिंग का यह मामला तमिलनाडु सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निदेशालय द्वारा इसी वर्ष वैथिलिंगम के खिलाफ दर्ज शिकायत पर आधारित है। इसमें आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया है।

स्वावलंबी बनने के साथ रोजगार भी दे रहीं गांव में चौका-चूल्हा करने वालीं

जागरण विशेष

शैलेंद्र गोदियाल ● जागरण

उत्तरकाशी में तुल्याड़ा मल्ली गांव की महिलाएं एलईडी व झालर सहित अनेक प्रकार के उत्पाद बना कर रहीं हैं लाभ अर्जित, खेती-किसानी का काम भी संभालतीं

उत्तरकाशी: महिलाएं अब चौखट के अंदर तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने खुद को साबित किया है। शहर में ही नहीं, गांवों में भी। इसका आदर्श उदाहरण पेश किया है उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के तुल्याड़ा मल्ली गांव की महिलाओं ने। चौका-चूल्हा, खेती-किसानी व मवेशियों की देखभाल के साथ ही उन्होंने स्वरोजगार की राह पकड़ी तो घर-आंगन में संपन्नता का प्रकाश फैल गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के सहयोग से गांव की कई महिलाएं एलईडी के साथ लड़ी व झालर सहित कई प्रकार की लाइट बनाकर खूब लाभ अर्जित कर रही हैं। इतना ही नहीं, वे आसपास के गांव की महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं।

जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 40 किमी दूर चिन्यालीसौड़ ब्लाक के तुल्याड़ा मल्ली गांव में कुछ महिलाओं ने अपर्णा स्वयं सहायता समूह का गठन कर वर्ष 2019 में एनआरएलएम के तहत उत्तरकाशी में 15 दिन प्रशिक्षण लिया। इस दौरान उन्होंने एलईडी के साथ कन्सिल लाइट, सोलर लाइट, लड़ी, फोकस लाइट व ट्यूब लाइट बनाना सीखा। इनमें सरिता रमोला, शशि रमोला, रीना रमोला, निर्मला रमोला, अंजू रमोला, निर्मला पंवार, पुष्पा रावत, रेशमा रंगड़, कुमारी रमोला समेत 10 महिलाएं शामिल थीं। प्रशिक्षण के बाद जब ये महिलाएं गांव लौटीं तो चौका-चूल्हा, खेती-किसानी व मवेशियों की देखभाल के साथ गांव में ही सामूहिक रूप से एलईडी बल्ब तैयार करना शुरू किया। इसके लिए प्रशिक्षण देने वालों के माध्यम से दिल्ली से सामान मंगवाया। एलईडी बल्ब तैयार कर पहले अपने घरों में ही उपयोग किया और फिर गांव में बेचे। अब दीपावली और सरस मेले के लिए उत्पाद तैयार कर रहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन्होंने करीब 10 लाख रुपये का कारोबार किया था, जिसमें इन्हें पांच लाख का शुद्ध लाभ हुआ। अप्रैल 2024 से लेकर सितंबर तक समूह आठ लाख रुपये का कारोबार कर चुका है।

चिन्यालीसौड़ में खोला स्थायी रूप से एक स्टाल

आकर्षित करते हैं ये उत्पाद

समूह से जुड़ी महिलाएं प्रति माह करीब 10 हजार रुपये कमा रही हैं। महिलाएं अब चिन्यालीसौड़ और उत्तरकाशी के इलेक्ट्रिकल व्यापारियों के लिए भी एलईडी के साथ कन्सिल लाइट, सोलर लाइट, लड़ी, फोकस लाइट व ट्यूब लाइट तैयार कर रही हैं। अपर्णा स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सरिता रमोला ने बताया कि एनआरएलएम के तहत ब्लाक मुख्यालय चिन्यालीसौड़ में स्थायी रूप से एक स्टाल खोला गया है। लोग खरीदारी के लिए यहीं पहुंचते हैं।

₹10 लाख का कारोबार किया वर्ष 2023-24 में

₹8 लाख का कारोबार अप्रैल से सितंबर तक कर चुकीं हैं

महिलाएं इस तरह एलईडी, व झालर आदि तैयार कर संवार रही आर्थिकी ● जागरण

स्थानीय उत्पादों को मिल रहा बाजार

महिलाएं स्थानीय उत्पाद, मसलन दालें, लाल चावल, बासमती चावल, सिलबट्टे से पिसा नमक, अचार, मंडुवा व झंगोरा सहित अन्य उत्पाद भी बेच रही हैं। इन उत्पादों को समूह तुल्याड़ा के साथ कुमराड़ा और बदाण गांव की महिलाओं से खरीदता है। इससे आसपास के गांव की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। समूह विभिन्न मेलों में एलईडी के साथ स्थानीय उत्पादों के स्टाल भी लगाता है। सरस मेला गुरुग्राम और सरस मेला कुरुक्षेत्र में भी समूह ने स्टाल लगाए थे। इस बार देहरादून सरस मेले का भी समूह को आमंत्रण मिला है।

उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने ब्रिज पर लाइटिंग का दिया जिम्मा: उत्तरकाशी जिले के कई विभाग इन महिलाओं से एलईडी के लिए संपर्क करने लगे, जिन्हें अब तक 20 हजार से अधिक एलईडी बल्ब बेचे जा चुके हैं। महिलाओं की कार्यकुशलता देखते हुए उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने जनवरी 2021 में चिन्यालीसौड़ के आर्च ब्रिज पर लाइटिंग का कार्य समूह को सौंपा। ब्रिज की लाइटिंग के लिए समूह ने कच्चा माल दिल्ली से मंगवाया, जिससे लड़ियां और 60 से अधिक फोकस लाइट तैयार करने के बाद पुल की लाइटिंग की गई।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

डमी कैंडिडेट बन परीक्षा देने वाली दो महिलाएं गिरफ्तार

जासं, जयपुर: राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा (रीट) - 2021 के पेपर लीक मामले में जोधपुर पुलिस ने डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाली दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। डमी कैंडिडेट बिठाने की आरोपित छम्मी बिश्नोई से पूछताछ में दोनों का नाम सामने आया था। इनमें से एक आरोपित भंवरी पुणे में स्वजन के यहां किचन डेकोर का काम कर रही थी, दूसरी आरोपित संगीता सांचौर में छिपकर रह रही थी। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम था। तीन महीने पहले वृंदावन से गिरफ्तार छम्मी से पूछताछ में दोनों का नाम सामने आया था। दोनों मूल परीक्षार्थी की जगह डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देती थीं। रीट में भी उन्होंने डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी।

****

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 24 अक्टूबर, 2024

दैनिक जागरण

उत्तरदायित्व की भावना का अभाव प्रगति को रोकता है

चीन से संबंध सुधार

रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के संबंध सामान्य होने की संभावना बढ़ अवश्य गई है, लेकिन इसमें समय लगेगा, क्योंकि बीते चार वर्षों में चीन ने अपनी हरकतों से भारत का भरोसा खोने का काम किया है। भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच करीब पांच वर्षों के बाद विस्तार से वार्ता इसीलिए हो सकी, क्योंकि चीन देपसांग एवं डेमचोक से अपनी सेनाएं पीछे हटाने और सीमा पर निगरानी की पहली वाली स्थिति बहाल करने पर सहमत हुआ। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए इस पर जोर दिया कि सीमा पर शांति रहनी चाहिए और आपसी विश्वास एवं सहयोग को बढ़ावा देने के साथ एक-दूसरे की संवेदनशीलता का सम्मान किया जाना चाहिए। यह कहना आवश्यक था, क्योंकि चीन यह तो चाहता है कि भारत उसके हितों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरते, लेकिन खुद उसकी ओर से भारत की संवेदनशीलता की परवाह नहीं की जाती। इसका प्रमाण यह है कि वह कभी कश्मीर तो कभी अरुणाचल प्रदेश को लेकर मनगढ़ंत दावे करता रहता है। इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि चीन किस तरह पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। इस क्रम में वह पाकिस्तान के उन आतंकियों का संयुक्त राष्ट्र में बचाव तक करता है, जो भारत के लिए खतरा हैं। ऐसे में भारत का उसके प्रति संशकित रहना स्वाभाविक ही है।

यह ठीक है कि रूस में भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि भी शीघ्र मिलेंगे। इस मेल-मुलाकात में विश्वास बहाली के उपायों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ऐसा पहले भी हो चुका है। अब चीन को यह आभास कराया जाना चाहिए कि उसने पहले गलवन और फिर अन्य स्थानों पर नियंत्रण रेखा में यथास्थिति बदलने के जो प्रयत्न किए, उसने ही दोनों देशों के संबंधों को पटरी से उतारने का काम किया। इसके लिए चीन अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकता। भारत को चीन से संबंध सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ने के पहले इसकी पड़ताल करनी चाहिए कि कहीं वह फिर से वैसी हरकत तो नहीं करेगा, जैसी डोकलाम, गलवन, देपसांग आदि में की। यह ध्यान रहे कि अतीत में चीन ने अपने अतिक्रमणकारी रवैये को तभी छोड़ा है, जब भारत ने यह जताने में संकोच नहीं किया कि वह बहुपक्षीय सहयोग के ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों को अपेक्षित महत्व देने से इन्कार कर सकता है। इस बार चीन इसलिए भी झुका, क्योंकि उसे यह आभास हुआ कि भारत का असहयोग उसके आर्थिक हितों पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। निःसंदेह संबंध सामान्य होने से चीन के आर्थिक हित सधेंगे, लेकिन भारत को अपने आर्थिक हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।

पुलिस के कलंक

यह चिंता की बात है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पूरे देश में सराहना हो रही है, लेकिन निचले स्तर पर भ्रष्टाचार में कमी नहीं आ पा रही है। कानपुर में दो दारोगाओं का कृत्य तो हैरान करने वाला है और चोरों पर मोर पड़ जाने की कहावत को चरितार्थ करता है। इन दरोगाओं ने सर्राफ की मदद से 25 लाख रुपये के जेवरात तो चोरों से हड़पे ही, चोर से एक लाख रुपये अलग से वसूले। ऐसे ही एक दूसरे मामले में दारोगा ने मोमबत्ती के एक व्यापारी से 50 हजार रुपये वसूल लिए। अब अधिकारियों ने दो दरोगाओं की गिरफ्तारी और थाना प्रभारी समेत सात पुलिसकर्मियों का निलंबन कर महकमे की छवि बचाने की कोशिश की है, लेकिन गंभीर सवाल यह है कि जिन्हें अपराध रोकने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित किया जाता है, वह स्वयं ही अपराधियों जैसा आचरण क्यों करने लगते हैं? कानपुर के ये दोनों प्रकरण तो उदाहरण के तौर पर हैं। इस तरह के न जाने कितने मामले हर जिले में सामने आते रहे हैं। थानों में तैनात पुलिसकर्मियों में भ्रष्टाचार एक ऐसा नासूर है जिसका इलाज करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन रोग बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि पुलिस महकमे में तैनात हर कर्मी भ्रष्ट है, लेकिन कुछ मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। विशेष तौर पर थानों की कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। अधिकारियों ने कुछ माह पहले बलिया के नरही थाने में हर माह डेढ़ करोड़ रुपये की वसूली का राजफाश किया था। आगरा में अभियान चलाकर दो दिन के भीतर 12 दरोगा, छह मुंशी सहित 56 दागी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। देखा जा रहा है कि प्रदेश के हर जिले में इस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि थानों में तैनात पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

राजनीतिक लड़ाई का मोहरा बनते कारोबारी

गौरव वल्लभ

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नवाचार और उद्यमशीलता सम्मान करने वाली संस्कृति को बढ़ावा देना अनिवार्य है

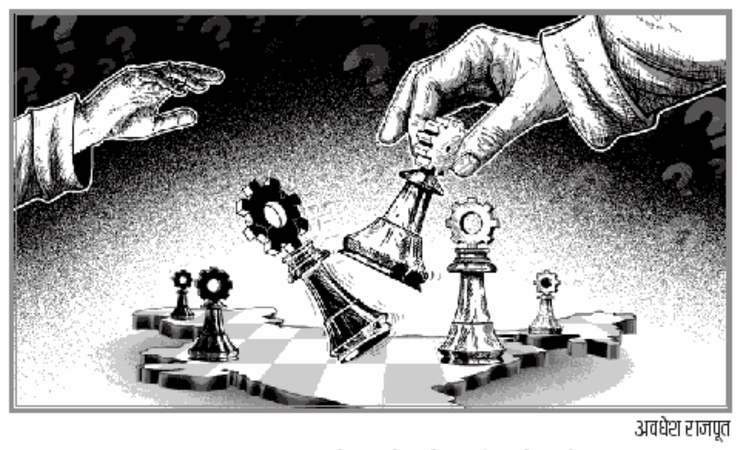

अवधेश राजपूत

भारत अभूतपूर्व औद्योगिक कायापलट के दौर से गुजर रहा है। परिवर्तन की यह बयार देश के आर्थिक विकास और सामाजिक लोकाचार को परिभाषित करेगी। करीब 24.7 लाख उद्यमियों के इस विशाल परिवार ने वित्त वर्ष 2023 में 8.8 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर के विस्मयकारी लेनदेन के स्तर को छुआ। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में संघर्ष करने वाले बड़े व्यवसायों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्यमों तक व्यवसाय पारंपरिक प्रतिमानों को फिर से परिभाषित कर रहे हैं और आर्थिक समावेशिता को बढ़ावा दे रहे हैं। उद्यम की यह लहर केवल एक सांख्यिकीय घटना नहीं, बल्कि नवाचार और महत्वाकांक्षा की अदम्य भावना का प्रतिबिंब है, जो भारतीय समाज के हर तबके में व्याप्त है। फिर भी विडंबना यह है कि जैसे-जैसे ये उद्यमी देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वे हमलों का सामना कर रहे हैं। रचनात्मक आलोचना प्रतिस्पर्धा एवं नवाचार को बढ़ावा देते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यह विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। उद्यमियों को अपने मानकों को बढ़ाने और मूल्य प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। आलोचनात्मक मूल्यांकन से प्रेरित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बेहतर उत्पादों, सेवाओं और अंततः अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर ले जा सकती है। हालांकि आलोचना जब स्वस्थ और भली मंशा से न की जाए तो वह केवल नकारात्मकता को बढ़ाती है। हमारे सार्वजनिक विमर्श में कुछ तबकों द्वारा अक्सर ऐसा किया जाने लगा है। वेल्थ क्रिएटर्स यानी संपदा सृजन करने वालों को अनावश्यक रूप से निशाने पर लिया जा रहा है। उद्यमियों को अपनी राजनीतिक लड़ाई का मोहरा बनाया जा रहा है।

नवाचार और कड़ी मेहनत के माध्यम से अर्जित सफलता का जश्न मनाने के लिए सामाजिक आख्यान को बदलने की आवश्यकता इस समय कहीं अधिक महसूस हो रही है। आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए उद्यमशीलता के प्रयासों का समर्थन करने वाली संस्कृति को अपनाना महत्वपूर्ण है। हमारे पाठ्यक्रम में व्यापक उद्यमिता शिक्षा की अनुपस्थिति के कारण कई लोग व्यावसायिक उपक्रमों की चुनौतियों और योगदानों को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। एक उद्यमी तमाम मुश्किल पड़ावों को पार कर सफलता के गंतव्य तक पहुंचता है। युवा उद्यमियों का ही उदाहरण लें तो कभी-कभी योग्यता के आधार पर मूल्यांकन करने के बजाय उनकी उम्र के कारण उन्हें खारिज कर दिया जाता है। इसी तरह, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह विशिष्ट पृष्ठभूमि के चलते भी उद्यमियों को भेदभाव झेलना पड़ सकता है। जबकि लैंगिक पूर्वाग्रह महिला उद्यमियों के लिए एक बाधा बनी हुई है, जिन्हें अपने लिए मुकाम बनाने में और परिश्रम करना पड़ता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कारोबारी हस्तांतरण को भाई-भतीजावाद के आरोप झेलने पड़ते हैं, जबकि ऐसा करते हुए विरासत व संचित ज्ञान के महत्व को अनदेखा कर दिया जाता है।

अनुचित आलोचना के प्रभाव बहुत गहरे और दूरगामी होते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर ही देखें तो इससे कारोबारी प्रवर्तकों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनामी झेलनी पड़ती है। यह उनके कर्मचारियों तक फैलता है, जिससे उनका मनोबल गिरता है और उत्पादकता घटती है। नवाचार को हतोत्साहित करना एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। जब जोखिम लेने वालों को सामाजिक रूप से दंडित किया जाता है तो यह रचनात्मकता और प्रगति को रोकता है। नकारात्मकता से भरे माहौल में निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है। घरेलू और विदेशी दोनों तरह की पूंजी स्थिर और अनुकूल परिस्थितियों को प्राथमिकता देती है। अनुचित आलोचना अस्थिरता को बढ़ाकर निवेशक बिरादरी का भरोसा तोड़ती है, जो आर्थिक विकास की गति को कुंद करता है। प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करने से अधिक टिकाऊ और समावेशी विकास हो सकता है। आर्थिक विकास को गति देने में उद्यमशीलता की अपरिहार्य भूमिका को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने पारंपरिक समाजवादी-उन्मुख नीतियों से धीरे-धीरे अधिक बाजार-हितैषी रणनीतियों की ओर रुख किया है। यह महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन व्यवसायों के फलने-फूलने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उद्यमियों को सशक्त बनाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक गहराई से जोड़ने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। जैसे स्टार्टअप इंडिया योजना कर रियायतों, नियमों को सरल बनाने और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर एक अनुकूल तंत्र के निर्माण में सहायक बनी है। इसी तरह मुद्रा योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति अपनी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार असाधारण योगदान को मान्यता और सम्मान देकर और नवाचार एवं उत्कृष्टता की राष्ट्रव्यापी संस्कृति को बढ़ावा देकर इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। इन प्रयासों के बावजूद उद्यमियों को अनुचित आलोचना से बचाने के लिए सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता है। इसके साथ ही जवाबदेही भी बनाए रखनी है।

उद्यमियों को नैतिक प्रथाओं, पारदर्शिता और सामाजिक प्रभाव के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। साथ ही, वे आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए मान्यता एवं सम्मान के हकदार हैं। खुले संवाद को प्रोत्साहित करना, वित्तीय साक्षरता बढ़ाना और उद्यमिता शिक्षा को अकादमिक पाठ्यक्रम में शामिल करना समझ के स्तर पर बनी खाई को पाटने में मददगार हो सकते हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नवाचार का जश्न मनाने वाली और उद्यमशीलता का सम्मान करने वाली संस्कृति को बढ़ावा देना अनिवार्य है। सरकार, मीडिया, शैक्षणिक संस्थानों और समाज का सामूहिक प्रयास ऐसा माहौल बनाने के लिए आवश्यक है, जहां आलोचना प्रगति में बाधा बनने के बजाय सुधार के साधन के रूप में काम करे।

(लेखक एक्सएलआरआइ, जमशेदपुर में वित्त के प्रोफेसर एवं भाजपा नेता हैं)

response@jagran.com

अलग माहौल वाले विधानसभा चुनाव

अवधेश कुमार

महाराष्ट्र और झारखंड में सीटों के बंटवारे पर जो खींचतान हुई, उससे आइएनडीआइए की एका की पोल ही खुली

महाविकास अघाड़ी में नहीं दिख रहा एका। प्रेट्र

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है, जिसकी कल्पना हाल के लोकसभा चुनाव के बाद नहीं की जा रही थी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस सहित उसके घटक दलों के स्वर में उत्साह और आत्मविश्वास की गूंज थी। ऐसा लगता था कि उन्होंने लड़ाई में जबरदस्त जीत हासिल की और भाजपा पराभव की ओर है। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के नतीजों ने माहौल बदल दिया। यदि महाराष्ट्र और झारखंड में आइएनडीआइए में सीट बंटवारे को लेकर जो कुछ हुआ, उसी को आधार बनाएं तो पता चल जाएगा कि स्थिति कितनी बदली हुई है। एक ओर भाजपा ने आत्मविश्वास और परिपक्वता से सहयोगी दलों के साथ सीटों का तालमेल किया और दोनों राज्यों में आपसी विरोध नहीं दिखा। दूसरी ओर महाराष्ट्र और झारखंड में आइएनडीआइए के बीच सीटों को लेकर जिस तरह की खींचतान तथा सार्वजनिक बयानबाजी हुई, उससे तथाकथित एकजुटता की वास्तविकता सामने आई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेता एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ही नहीं करते रहे, अपने हिसाब से प्रत्याशी उतारने की घोषणा भी करते रहे।

यह कहना ठीक नहीं होगा कि भाजपा नेतृत्व वाले राजग में सीटों को लेकर समस्याएं नहीं। मूल बात है कि आप इसे हैंडल कैसे करते हैं। महायुति में देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे में से किसी ने सीटों के बंटवारे को लेकर असंतोष प्रकट नहीं किया। भाजपा ने महाराष्ट्र में आरंभिक 99 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जहां दूसरे का दावा नहीं था। झारखंड में भी उसने शांति से सीटों का बंटवारा कर लिया और स्वयं 68 सीटों पर लड़ते हुए आजसू को 10, जदयू को दो एवं लोजपा को एक सीट दी। लोजपा का प्रदेश में जनाधार नहीं है और जद-यू भी ऐसी स्थिति में नहीं कि साथ न लेने पर भाजपा को क्षति पहुंचा दे। बावजूद इसके गठबंधन में एका बनाए रखने के लिए भाजपा ने ऐसा किया। दोनों गठबंधनों के बीच का यह गुणात्मक चरित्र चुनाव परिणाम पर प्रभाव नहीं डालेगा, यह मानना व्यावहारिक नहीं। महाराष्ट्र का अंकगणित देखें तो 2019 के विधानसभा चुनाव परिणामों का अब इसलिए महत्व नहीं, क्योंकि शिवसेना और राकांपा दोनों टूट चुकी हैं। यद्यपि भाजपा और कांग्रेस में टूट नहीं हुई है, लेकिन साथी दलों से इन्हें तब प्राप्त मतों का अनुमान लगाना संभव नहीं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में 48 में से राजग को केवल 18 तथा महाविकास अघाड़ी को 30 सीटें प्राप्त हुईं।

झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी के साथ परिवार बंट गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन और सीता सोरेन भाजपा के साथ हैं। झामुमो की लोकप्रियता नीचे है। हरियाणा में जीतते-जीतते हारना और जम्मू-कश्मीर में बुरे प्रदर्शन के कारण कांग्रेस के अंदर निराशा है। इसके साथ आइएनडीआइए घटकों के बीच संदेश गया है कि कांग्रेस की हैसियत अपनी बदौलत सफलता पाने की नहीं है। जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की प्रवृत्तियां बदलती दिखाई दी हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के लिए दलितों के बीच विस्तृत पैठ बनाना कठिन रहा है, क्योंकि यह प्रदेश दलित आंदोलन का केंद्र है, जिसके निशाने पर हिंदुत्व और भाजपा रही है। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार संविधान और आरक्षण खत्म कर देगी, ऐसा प्रचार दलितों और पिछड़ों के एक वर्ग तक पहुंचा। उसने आइएनडीआइए के पक्ष में मत दिया, लेकिन हरियाणा के दलितों के बड़े वर्ग ने भाजपा के पक्ष में जाकर जता दिया कि वह इस गलत प्रचार के झांसे में नहीं आने वाला। हरियाणा सरकार गठित होने के बाद नायब सिंह सैनी सरकार ने अनुसूचित जाति आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू कर दिया, जिसका लाभ दलितों के अंदर वंचित वर्ग को मिलेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के समय देखा गया कि भाजपा उम्मीदवारों और संगठनों में तो तालमेल था, लेकिन राज्य सरकार को लेकर संगठन परिवार के अंदर असंतोष और नाराजगी थी। इसके बाद भी राहुल गांधी ने जिस तरह हिंदुत्व पर कटाक्ष किए और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का उपहास उड़ाया, उसकी प्रतिक्रिया हुई।

वास्तव में लोकसभा चुनाव में जहां भी भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा, वहां यह भाव व्याप्त हो रहा है कि यद्यपि भाजपा संगठन और सरकारों ने हमारी अनेक अपेक्षाएं पूरी नहीं की, किंतु देश के समक्ष खतरे को देखते हुए उसके विरोधियों के साथ जाना आत्मघाती होगा। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच हिजबुल्ला सरगना के मारे जाने के बाद देश के कुछ हिस्सों में किए गए आक्रामक प्रदर्शनों से डर पैदा हुआ। फिर जगह-जगह सिर तन से जुदा के नारे ने इसे और बढ़ाया। कई जगह दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर हमले और हिंसा देखने को मिली। झारखंड में घुसपैठ, कट्टरपंथ, मतांतरण, लव जिहाद की घटनाओं ने लोगों के मन पर असर डाला है। हरियाणा की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दे किसान आंदोलन, अग्निवीर, संविधान, आरक्षण और दलितों, पिछड़ों तथा अल्पसंख्यकों पर खतरे की बात से मतदाता सहमत नहीं। राहुल गांधी के रणनीतिकार यह मानने को तैयार नहीं कि हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में मतदाताओं ने उनके तर्कों और मुद्दों को ठुकरा दिया है, इसलिए वे उसी नैरेटिव पर काम कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम को तंत्र, चुनाव आयोग और ईवीएम को आरोपित करना बताता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस अपनी नीतियों पर पुनर्विचार विचार करने को तैयार नहीं।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

स्वबुद्धि और आत्मबल

मानव जीवन जटिलताओं से परिपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति, बुद्धि और वृत्तियां विलक्षण होती हैं। इसीलिए यह अनिवार्य है कि मनुष्य अपने जीवन में अपने पथ का चयन स्वयं करे, क्योंकि आत्मपरिचय की गहनता किसी अन्य द्वारा संपूर्णतः समझना संभव नहीं है। जब हम परायों के परामर्श और अनुभूतियों पर निर्भर होते हैं, तो हम आत्मविस्मृति के पाश में बंध जाते हैं। समाज और परिवेश की अपेक्षाओं से प्रभावित होकर लिया गया कोई भी निर्णय हमारी आंतरिक चेतना और प्रकृति के अनुरूप नहीं होता। ऐसा पथ, जो केवल बाह्य प्रेरणाओं पर आधारित हो, मनोवांछित सुख और संतोष नहीं प्रदान कर सकता। व्यक्ति को अपनी स्वबुद्धि और आत्मबल के आधार पर अपने लक्ष्य और दिशा का निर्धारण करना चाहिए।

स्वपथ का चयन आत्मशक्ति और स्वावलंबन को उत्प्रेरित करता है। जब हम स्वयं अपने निर्णयों का भार वहन करते हैं, तो हमारा आत्मबल और धैर्य विकसित होता है। इस प्रक्रिया में त्रुटियां भी स्वाभाविक हैं, परंतु उन्हीं त्रुटियों से हमें जीवन की वास्तविक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक विफलता हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करती है। स्वनिर्णय का पथ हमें आत्मविकास की ओर अग्रसर करता है। किसी भी पथ का चयन करते समय अपने अंतर्मन की वाणी और विवेक की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। यद्यपि समाज व परिवार से प्राप्त परामर्श मूल्यवान हो सकते हैं, किंतु अंतिम निर्णय व्यक्ति की अपनी प्रकृति और अनुभवों के आधार पर ही होना चाहिए। आत्मनिर्णय से उत्पन्न स्वाधीनता व्यक्ति के जीवन को गरिमा और संप्रभुता प्रदान करती है। यह न केवल बाह्य रूप से, बल्कि आंतरिक रूप से भी उसे सशक्त बनाती है। स्वयं के निर्णयों से अर्जित सफलता या असफलता जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। आपको अपने विषय में आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं जान सकता।

नृपेन्द्र अभिषेक नृप

खत्म हो बाल विवाह कुप्रथा

सुनीता मिश्रा

हमारे समाज में बाल विवाह की कुप्रथा आज भी कायम है, जिसे रोका जाना चाहिए

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को पर्सनल ला के जरिए बाधित नहीं किया सकता। बाल विवाह के कारण अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार छिन जाता है। नाबालिगों की जबरन और कम उम्र में शादी करना उनकी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन है। यह बच्चों की स्वतंत्रता, पसंद, आत्मनिर्णय और बचपन का आनंद लेने के अधिकार से वंचित करता है। इससे दोनों पक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बाल विवाह कुप्रथा को खत्म करने के लिए केंद्र, राज्यों, जिला प्रशासन, पंचायतों और न्यायपालिका को कई दिशानिर्देश भी जारी किए। साथ ही, सजा से बचने के लिए बच्चों की सगाई करने की प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत बताई। अदालत के दिशानिर्देशानुसार आम लोगों में इसको लेकर जागरूकता बढ़ाने के उपाय किए जाने चाहिए। हर समुदाय के लिए अलग तरीके अपनाए जाएं।

वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2019-2021 के पांचवें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बाल विवाह के जो आंकड़े दिए गए हैं, उनके मुताबिक 23.3 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हुई, जबकि 17.7 प्रतिशत लड़कों की शादी 21 वर्ष से कम आयु में हुई। ये आंकड़े 20 से 24 वर्ष की लड़कियों और 25 से 29 वर्ष के लड़कों पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम, बाल विवाह में शामिल बच्चों की सुरक्षा और अपराधियों पर मुकदमा चलाना है। इस कानून में लड़कों के लिए शादी की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष तय की गई है। इसका उल्लंघन करने पर दो वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान है। बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़कियों पर, बल्कि उनके परिवार, समाज और देश पर भी पड़ता हैं। इससे लड़कियों की शिक्षा व स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है।

बाल विवाह कुप्रथा समाज के लिए अभिशाप है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को गरीबी की ओर धकेलता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर लिया गया फैसला न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में बाल विवाह के खिलाफ बड़ा बदलाव लाने की क्षमता भी रखता है। सरकार के साथ बच्चों के अधिकारों व उनकी भलाई के लिए समाज को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। इसके तहत स्वास्थ्य खतरे व सामाजिक आर्थिक परिणामों की भी जानकारी दी जाए, ताकि सभी बच्चों को सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर मिल सके।

(लेखिका स्वंतत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

भारत के दोनों हाथों में लड्डू

यदि ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं तो भारत, रूस और अमेरिका की तिकड़ी बनेगी। यदि कमला हैरिस चुनाव जीत जाती हैं तो भारत, रूस और चीन की तिकड़ी बनेगी। दोनों स्थितियों में भारत को कोई समस्या नहीं होने वाली। अमेरिका की वर्तमान सरकार ने कनाडा के माध्यम से भारत में पिछले तीन साल से जो अस्थिरता फैलाने की कोशिश की है और खासकर चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया है, ऐसे में चीन को निष्प्रभावी करने के लिए उसे जो साथ और विश्वास भारत का चाहिए था, वह उसने खो दिया है। अमेरिका ने अतिमहत्वाकांक्षा में अपने एक विश्वसनीय बनने जा रहे सहयोगी को अपने से दूर कर लिया, लेकिन अमेरिका के लिए मुश्किल इतनी भर ही नहीं है। यदि यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर रूस को अलग-थलग नहीं कर पा रहे हैं तो यह स्पष्ट होता जा रहा है कि दुनिया में उनकी दादागीरी के समाप्ति के दिन आ रहे हैं। अमेरिका ने बहुत प्रयास किया कि उसके उकसावे में चीन और भारत आपस में लड़ जाएं, लेकिन अंततः दोनों देशों ने इस उकसावे के आमंत्रण को पूरी बुद्धिमानी से अस्वीकार कर दिया। जहां चीन की गिरती हुई आर्थिक स्थिति भी इसके लिए जिम्मेदार है, वहीं भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत भी इसमें सहयोगी बनी। भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हम यूरोप और अमेरिका समर्थक रहना तो चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत राष्ट्र का अहित नहीं हो सकता। यदि ब्रिक्स सम्मेलन में अपनी-अपनी करेंसी में व्यापार करने पर सहमति बन जाती है तो यह डालर के प्रभाव को भी कमतर कर देगी। यदि अपना अलग पेमेंट गेटवे स्थापित करने पर बात आगे बढ़ी तो हर जगह अमेरिका की जो आंख लगी रहती है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। अब अमेरिका के पास दो विकल्प हैं- पहला कमला हैरिस जीतें और गलतियों को दोहराते रहें और दूसरा, ट्रंप जीतें और भारत के लिए कुछ बहुत बड़ा आफर करें। यदि अमेरिका और चीन में से किसी को चुनना होगा तो भारत अमेरिका को चुनेगा, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, उनमें भारत के दोनों हाथों में लड्डू है।

डा. भूपेंद्र सिंह@DrBS07

दोषारोपण की राजनीति

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिश ने हाल ही में कहा कि आनंद विहार में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उसका कारण उत्तर प्रदेश से आने वाली डीजल बसें हैं, तो बाकी पूरी दिल्ली का क्या? जब प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है, तब ये लोग पड़ोसी राज्यों को दोष देने लगते हैं। चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा। दिल्ली सरकार अपनी सभी नाकामियों के लिए अपने पड़ोसी राज्यों यानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर दोषारोपण करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है। आनंद विहार में दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च करके प्रदूषण कम करने के लिए यंत्र लगाए थे। जनता के टैक्स के पैसे को खर्च करने के बाद भी उनसे कुछ फायदा नहीं हुआ है।

विंध्या वशिष्ठ, दिल्ली

भरोसेमंद नहीं अमेरिका

भरोसे के लायक नहीं है अमेरिका- शीर्षक आलेख में राजीव सचान ने भारत के खिलाफ अमेरिका द्वारा किए जा रहे षड्यंत्रों का तथ्यपरक विश्लेषण किया है। वैश्विक स्तर पर भारत की हर जगह पर उपस्थिति अमेरिका को रास नहीं आ रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के समक्ष इसी दोस्ती का आभार जताया और कहा कि रूस हमारा सबसे भरोसेमंद मित्र है। ब्रिक्स देशों में अधिकांश अमेरिका विरोधी भी हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका खुलकर विरोध भले न करते रहे हों, लेकिन अमेरिका के पिछलग्गू तो नहीं ही हैं। दरअसल, ब्रिक्स देशों का संगठन बना ही इसलिए था, ताकि जी-7 की दादागिरी से निपटा जा सके। रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने के लिए रूस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आगे किया है। अमेरिका-भारत साझेदारी के भविष्य के बारे में व्यापक आशावाद के बावजूद रिश्ते जितने दिख रहे हैं, उससे कहीं अधिक नाजुक हैं।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

64,871 बूथों का डिजिटाइजेशन किया था भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में, जो देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने बूथ कमेटी और मतदाताओं का पूरा विवरण आनलाइन किया था।

डा. अनिता राठौर
वरिष्ठ स्तंभकार

भारत-चीन एलएसी समझौता

समझौते का स्वागत हो सजगता भी रहे कायम

रूस में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के आरंभ होने से एक दिन पहले भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) पर पेट्रोलिंग व्यवस्था संबंधी समझौता हो गया है। इससे न केवल डिसइंगेजमेंट (सैनिकों का मोर्चे से बैरकों में लौटना) होगा, बल्कि वर्ष 2020 के सैन्य टकराव से जो मुद्दे उठे थे, उनका भी समाधान हो जा सकता है। दोनों देशों के बीच स्थिति को सामान्य करने के संदर्भ में यह एक बहुत बड़ा कदम है। वस्तुत: पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पिछले 54 माह से जो सैन्य गतिरोध बना हुआ था, वह समाप्त हो जा सकता है, फिर भी चीन के प्रति सजग तो रहना ही होगा

चीन की ओर से संकेत अच्छे मिले हैं, परंतु एलएसी के निकट सैन्य निगरानी में कमी नहीं की जानी चाहिए। फाइल

मंगलवार यानी 22 अक्टूबर से रूस के कजान में शुरू हुए 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग व्यवस्था संबंधी जो समझौता हुआ था, वह उम्मीदों के मुताबिक सही दिशा में बढ़ रहा है। अगले एक हफ्ते के भीतर भारत और चीन दोनों की सेनाएं 2020 में हुए गलवन घाटी टकराव से पहले की स्थिति में चली जाएंगी। चूंकि चीन इतिहास में कई बार समझौता करके भी पीछे लौटने की हरकत करता रहा है, इस वजह से भारत इस बार पूरी तरह से सतर्क था और तब तक पुरानी पेट्रोलिंग व्यवस्था की अपनी मांग को लेकर अडिग रहेगा, जब तक चीन इसे व्यावहारिक तौर पर शुरू नहीं कर देता। वैसे चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इस समझौते की पुष्टि करते हुए कहा है कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर चीन और भारत की कूटनीतिक एवं सैन्य स्तर पर करीबी बातचीत जारी है। उम्मीद की जा रही है कि लद्दाख क्षेत्र में सैन्य टकराव की आशंकाएं समाप्त हो जाएंगी।

दरअसल यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहे हैं, उनके कारण शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद विश्व एक बार फिर से दो खेमों में विभाजित होता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका और उसके यूरोपिय साथी हैं, जो यूक्रेन व इजरायल के समर्थन में खड़े हैं और दूसरी ओर रूस, चीन एवं ईरान का त्रिकोण है, जो पश्चिम का विरोध कर रहा है। भारत इन दोनों खेमों के बीच फिलहाल सेतु के रूप में है, लेकिन दोनों ही खेमे उसे अपने अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि भारत का चीन से सीधा सीमा विवाद चल रहा था, इसलिए उसके लिए किसी एक खेमे का सदस्य बनना संभव नहीं था। चीन ने सीमा विवाद को हल करके भारत को प्रलोभन अवश्य दिया है, लेकिन सवाल यह है कि चीन पर कितना भरोसा किया जा सकता है?

फिलहाल भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्रिक्स पश्चिम-विरोधी समूह बनकर न रह जाए। क्वाड, आकस, रूस-चीन 'नो-लिमिट्स पार्टनरशिप', यूक्रेन युद्ध और ईरान का ब्रिक्स सदस्य बनने के बाद यह दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है कि ब्रिक्स को पश्चिम के विरोध में खड़ा किया जाए। हालांकि ब्रिक्स के गठन का आधार ही पश्चिम-प्रभावित विश्व व्यवस्था को चुनौती देना था, लेकिन विस्तृत ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी बनने से बचना चाहिए। भारत के पास विशिष्ट अवसर है कि वह अपनी 'सेतु' वाली स्थिति का प्रयोग ब्रिक्स के भविष्य को दिशा देने के लिए करे।

वैसे भी भारत ने स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में संकोच नहीं किया है, जैसा कि यूक्रेन-रूस युद्ध में रूस पर पश्चिम की पाबंदी के बावजूद वह रूस से सस्ता तेल लेता रहा और इस तरह दुनिया को बता दिया कि वह किसी एक खेमे का सदस्य नहीं है। नई दिल्ली के लिए जरूरी है कि वह चीन के साथ एलएसी समझौते को द्विपक्षीय मामला ही रखे, उसे अंतरराष्ट्रीय खेमेबाजी की राजनीति का हिस्सा नहीं बनने दे। इस समझौते के संदर्भ में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि इस 'सकारात्मक' समझौते से दोनों पक्ष 2020 की स्थिति में वापस पहुंच गए हैं और डिसइंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी हो गई है। उनके अनुसार अब भारतीय सैनिक उसी तरह से पेट्रोलिंग कर सकेंगे, जैसा वह 2020 के गतिरोध से पहले करते थे।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत व चीन के बीच संबंध निरंतर पिघलती बर्फ की पतली परत पर टिके हुए थे, पूर्वी लद्दाख में 2020 के घातक टकराव के बाद से दोनों पक्ष जबरदस्त सैन्य तैयारी में जुटे हुए थे, जैसे किसी भी पल जंग का बिगुल बज जाएगा। गतिरोध वाले क्षेत्रों में बफर जोन के बावजूद दोनों देशों ने अधिक फौज की तैनाती से अपनी अपनी किलेबंदी भी की हुई थी, जो चिंता का विषय थी।

हालांकि भारत अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चीन से संपर्क में रहा है, लेकिन 2020 से द्विपक्षीय वार्ता केवल डिसइंगेजमेंट तक ही सीमित रही है। अब जो यह कदम आगे बढ़ा है, उस तक पहुंचने के लिए पिछले 53 माह में 20 चक्र से भी अधिक सैन्य वार्ताएं हुई हैं और इनके अतिरिक्त विदेश मामलों के अधिकारियों के बीच भी मल्टी-लेवल की अनेक बैठकें हुई हैं, खासकर पिछले दो-तीन माह में तो बैठकों का सिलसिला निरंतर चला है। सवाल यह कि आखिरकार यह गतिरोध टूटा कैसे? यह सही है कि बीजिंग आक्रामक जिद्दी प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि समझौता करने के लिए वह अपनी घरेलू चुनौतियों से प्रभावित हुआ है, विशेषकर धीमी होती अर्थव्यवस्था और अत्यधिक सैन्यीकृत सीमा को कायम रखने के खर्च से बीजिंग की निगाह इस बात पर भी लगी हुई थी कि नई दिल्ली के वाशिंगटन से स्ट्रेटेजिक व सैन्य संबंध गहरे होते जा रहे हैं और रक्षा व्यापार भी धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है।

बीजिंग के दिमाग में यह भी है कि इस्लामाबाद भी वाशिंगटन की तरफ बढ़ता जा रहा है। दरअसल, पाकिस्तान ने चीन को कुंठित कर दिया है, चीन के प्रिय सीपीईसी प्रोजेक्ट को गति न देकर और चीनी वर्कर्स व इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित न करके, जो दोनों ही अतिवादी तत्वों का निशाना हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर बताया गया, विश्व दो खेमों में विभाजित होता जा रहा है, पश्चिम को चुनौती देने के लिए रुसी खेमे को भारत की जरूरत है, जिसके लिए आवश्यक था कि भारत व चीन के बीच सीमा विवाद का हल निकले और इन दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हों। इधर नई दिल्ली भी बीजिंग से समझौता करके वाशिंगटन को संदेश देना चाहता था कि वह पन्नून और निज्जर (कनाडा के जरिये) के बेबुनियाद केस उछालकर उसे 'फार-ग्रांटेड' न ले।

संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर उठते सवाल

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी
चेयर प्रोफेसर, केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा, पंजाब

विश्व आज परिवर्तन के दौर में है। इस दौर में संयुक्त राष्ट्र ने भविष्य की खोज के लिए एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया। इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार हिबाकुशा को मिला, जिसकी मंशा है कि संपूर्ण विश्व परमाणु शस्त्र विहीन बन जाए और निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिले। विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार उत्पादक देश अमेरिका, रूस और चीन इस संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। वीटो पावर इनके पास है। विश्व में अपनी बेहतर छवि बनाने का प्रयास संयुक्त राष्ट्र ने अब तक किया है। विश्व शांति एवं मानवाधिकारों के साथ सतत विकास के लक्ष्य हों या जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने की कवायद, इन सब पर संयुक्त राष्ट्र इन्हीं देशों के चंदे से अपने हर वक्तव्य के साथ खड़ा होता है।

पिछली सदी के अंतिम दशक में ईराक में जो कोहराम मचा, वह किसी से छुपा नहीं है। आज यूक्रेन और रूस के हालात हों या गाजा संकट हो, बेबस संयुक्त राष्ट्र केवल एक अपील एजेंसी बन गया है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र को लेकर उभरी नकारात्मक छवि को ठीक करने का उपाय संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस के पास नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय है। इस समय मानवाधिकारों के हनन, शरणार्थियों की समस्या और अनागरिक होने का संकट भी है। भूख, स्वास्थ्य और गरीबी से जूझती तीसरी दुनिया के लोग अपनी लाचारगी लिए घूम रहे हैं। अफगानिस्तान और म्यांमार में महिलाओं एवं शरणार्थियों के संकट, बांग्लादेश में तख्तापलट व असंतोष संयुक्त राष्ट्र के लिए भी हैं, क्योंकि उसने जो एमडीजी से एसडीजी-2030 की जो यात्रा तय करने का सोचा था, वह अब लक्ष्य से बहुत दूर जा चुकी है।

संयुक्त राष्ट्र अब यह सोच रहा है कि चंदे देने से ना-नुकुर करने वाले देश अपना वित्तीय पोषण करने से यदि हाथ पीछे कर लेंगे तो उसके साथ जुड़े मानव संसाधन का क्या होगा? इस समय संयुक्त राष्ट्र के सामने यह एक चुनौती है कि जलवायु परिवर्तन के लिए व्यापक सहयोग हो और सतत विकास लक्ष्य को हासिल किया जाए, लेकिन बहुत से देश सतत विकास लक्ष्य-2030 के लिए कोई व्यवस्थित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हैं। वैसे आज बहुत ही सुनियोजित ढंग से विश्व में पृथ्वी की चिंता हो रही है और वहीं दूसरी ओर युद्ध भी हो रहे हैं, हथियार निर्यात किए जा रहे हैं, परंतु संयुक्त राष्ट्र कुछ करने की स्थिति में नहीं है। कई देशों की जब सुरक्षा परिषद में विस्तार के लिए पहल हुई तो कुछ वीटो देशों ने सहयोग करने को कहा, लेकिन भारत के पक्ष में स्वयं चीन ने कई बार वोट करने से मना कर दिया। संयुक्त राष्ट्र विस्तार की पहल भी नाकाम दिख रही है। आज जब विश्व में कई तरह की समस्याएं हैं, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार आवश्यक हो गया है। यदि ऐसा हो जाए तो कई मामलों पर एकाधिकार वाली स्थिति को रोका जा सकता है।

आज समस्या यह है कि 24 अक्टूबर, 1945 को जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तो उस समय की प्रतिबद्धताएं अब बहुत पीछे छुट गई हैं। वह समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नए पुनरुत्थान के लिए समर्पित होकर शांति व विकास की यात्रा के लिए था। विकास की गतिशीलता को व्यापक पैमाने पर ले जाने की प्रतिबद्धताएं निजी हितों में भी देखी जा रही हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र से निराश होती भारत और विश्व की आबादी इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि हमारे लिए कब ऐसा पल आएगा जब संयुक्त राष्ट्र अपनी निष्ठा के साथ विश्व में शांति और सम्मान दिलाने में कामयाब हो सकेगा। एक बात यह तय है कि यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं किया गया तो वह अपने लक्ष्य को हासिल करने से कोसों दूर रह जाएगा।

खरी-खरी

कुर्सी पर वफादारी की खड़ाऊं

रेखा शाह आरबी

सियासत और वफादारी ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। अगर सियासत में वफादारी निभाई जाए तो वह खतरे में पड़ जाती है। और सियासत निभाई जाए तो वफादारी खतरे में पड़ जाती है। इनका जब भी गठबंधन होता है जबरदस्ती का ही होता है। इसके अनेक उदाहरण राजनीति में भरे हैं। वैसे कुछ लोगों के नसीब में जब राहु केतु और शनि की एक साथ युति होती है, तो मजबूरी में ही सही, सियासत में भी वफादारी दिखानी पड़ जाती है। यह सब कुछ कुर्सी के लिए होता है। और कुर्सी न किसी की सगी होती है, न कभी सगी होगी। जब मौका मिला, जिसको मौका मिला, उसी की हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक नेता को सबसे ज्यादा और सबसे पहले अपनी कुर्सी की चिंता होती है। उसके बाद देश दुनिया और अपने कार्यकर्ताओं की चिंता होती है। लेकिन कभी-कभी बाजी ऐसी पलटती है कि नेता को अपनी कुर्सी भी दूसरे को देनी पड़ती है। अब वह किस मन से देता है यह मन कोई नहीं समझ सकता। और जब ऐसी स्थिति में कोई नेता आता है तो वह अपने सबसे विश्वस्त व्यक्ति को ही अपनी कुर्सी अमानत के तौर पर दे देता है। उसका विश्वस्त व्यक्ति भी उस कुर्सी को अमानत समझकर उस पर स्वयं न बैठकर अपने मलिक के खड़ाऊं को रखकर राज-काज चलाता है।

परंतु देखा गया है कि कुर्सी तो स्वयं ही बेवफा प्रेमिका की भांति है तो वह वफादारी कैसे निभा सकती है। जब कुर्सी पर खड़ाऊं बैठी होती है तो कभी लुढ़क कर इधर गिरती है, कभी लुढ़क कर उधर गिरती है। बहुत मुश्किल से कुर्सी पर वह अपना संतुलन बना पाती है। खड़ाऊं से ज्यादा लुढ़कने का चांस उसकी देखभाल करने वाले की होती है। जैसे ही मौका मिलता है पहली फुर्सत में खड़ाऊं को नौ दो ग्यारह कर देता है और स्वयं उस पर काबिज हो जाता है। इसमें न तो खड़ाऊं का कोई दोष होता है, न ही खड़ाऊं रखने वाले का दोष होता है। कुर्सी है ही ऐसी चीज कि किसी को टिकने नहीं देती है। सबकी वफादारी को पलीता लगा देती है।

पोस्ट

नेता राजनीति के लिए कह देते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, लेकिन आखिर उन बच्चों को खिलाएगा कौन?

मनु गौर@mgtaxab

बोतल फूटे या अंगुली टूटे। वोट बैंक का साथ न छूटे। देश की राजनीति में जो नेता रचनात्मक योगदान नहीं दे पाते, वे मीडिया की हेडलाइंस में आने के लिए कितने फूहड़ काम करते दिखते हैं। राजनीति में बढ़ती इस दरिद्रता पर तरस आता है।

नवनीत मिश्रा@navneetmishra99

अप्रैल 2023 में जारी दिल्ली सरकार के दस्तावेज कहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए अलग-अलग विभागों की तरफ से 2017-18 और 2020-21 के बीच कुल 6,856.9 करोड़ रुपये खर्च किए गए। फिर भी दिल्ली तेरी यमुना मैली हो गई!

रुबिका लियाकत@RubikaLiyaquat

जामिया मिलिया में हिंदू छात्रों का दीवाली मनाना लोगों को अखर गया और फलस्तीन के समर्थन में नारे लगाते हुए जलते हुए दीपकों को जूतों से रौंद दिया गया। याद रहे कि इस यूनिवर्सिटी की तनख्वाह से लेकर ग्रांट तक और बिजली से लेकर पानी तक हमारे टैक्स के पैसे से दिया जाता है।

अनुपम मिश्रा@scribe9104

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को वहाल किए जाने की मांग सही है?

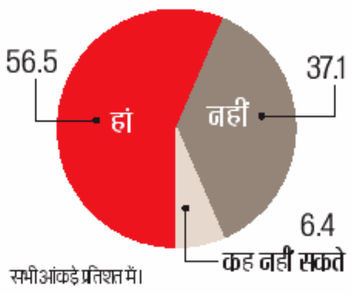

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या भारत को चीन के साथ अपने संबंध सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

'अनुभव' देने में गईं गुजर पीढ़ियां चार,
फिर भी उनकी पार्टी रही हार पर हार।
रही हार पर हार बहन जी अब हैं आईं,
जब भाई की फौज पार सौ ना कर पाई।
रहीं लड़ाती आप सदा प्रत्याशी नव-नव,
लो जाकर वायनाड जरा लड़ने का अनुभव!

- ओमप्रकाश तिवारी

राजनीति में भाजपा का नवाचार

धनंजय प्रताप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान रहा है। पार्टी का कैडर खड़ा करने में कुशाभाऊ ठाकरे या प्यारेलाल खंडेलवाल जैसे नेताओं ने पसीना बहाकर जो संगठन खड़ा किया, उसी का प्रसाद है कि भाजपा 2003 के बाद से चंद महीनों को छोड़कर लगातार सत्ता में बनी हुई है। नई सदी के पांच विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चार में जीत दर्ज की। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटें भाजपा की झोली में आई हैं। यह रिकार्ड तो भाजपा का चुनावी राजनीति का है, लेकिन यदि पार्टी की संगठनात्मक पकड़ और क्षमता की बात करें तो भी मध्य प्रदेश ने भाजपा को कई ऐसे नवाचार दिए, जो देशभर में लागू किए गए हैं। पन्ना प्रमुख के नवाचार में मध्य प्रदेश की ही देन है।

वर्ष 1993 में मुस्लिम बहुल सीट भोपाल उत्तर में पहली बार पन्ना प्रमुख बनाए गए थे। उस समय रमेश शर्मा गुट्टू भैया भाजपा के प्रत्याशी थे, तब इसी नवाचार की बदौलत पहली बार मुस्लिम बहुल सीट से कोई हिंदू प्रत्याशी चुनाव जीता था। इसके बाद जब भोपाल दक्षिण से उमाशंकर गुप्ता वर्ष 2013 में भाजपा प्रत्याशी थे, राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल इस बैठक में शामिल होने भोपाल आए। गुप्ता ने बैठक व्यवस्था भी पन्ना प्रमुख के हिसाब से की थी। रामलाल पन्ना प्रमुख के इस नवाचार को देखकर आश्चर्यचकित थे, उन्होंने कहा कि हम जो करना चाहते थे, वह मध्य प्रदेश ने आरंभ कर दिया। फिर यह व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दी गई।

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां भाजपा ने 64,871 बूथों का डिजिटाइजेशन किया था। यानी बूथ कमेटी और मतदाताओं का पूरा ब्यौरा आनलाइन किया गया था। प्रदेश संगठन की इस उपलब्धि को देखकर ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जून 2023 में 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को चुना। इस कार्यक्रम में देशभर के बूथ कार्यकर्ता आए थे और ऐसे एक लाख कार्यकर्ताओं ने बूथ में रहकर उसकी कार्यपद्धति सीखी व अपने राज्यों में जाकर इसे लागू किया। कैडर आधारित पार्टी होने का भाजपा की यही मजबूती उसे चुनाव में सफलता दिलाती है। अब इस वर्ष मध्य प्रदेश भाजपा ने एक नवाचार किया है, वह है- आइ एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स। वस्तुतः यह प्रधानमंत्री मोदी का विजन था कि एक लाख गैर राजनीतिक प्रोफेशनल्स को राजनीति में लाया जाए, ताकि वे 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभा सकें।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने सदस्यता अभियान के तहत पांच अक्टूबर को भोपाल के रविंद्र भवन में इस अभियान का श्रीगणेश किया। इसमें डेढ़ सौ प्रोफेशनल्स को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। इसके बाद उज्जैन, जबलपुर और इंदौर जैसे बड़े शहरों में भी बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स को भाजपा से जोड़ा गया। भाजपा की दिल्ली में सदस्यता की बैठक में जब इस 'आइ एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स' के बारे में विष्णु दत्त शर्मा ने बताया तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने केवल प्रशंसा ही नहीं की, बल्कि देश के अन्य राज्यों में इसे लागू करने का निर्देश भी दिया। 'आइ एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स' अभियान राजनीति में शुचिता लाने का एक प्रयास है।

इंदौर में सदस्यता अभियान के लिए आयोजित सम्मेलन में शामिल प्रोफेशनल्स। भाजपा

इस प्रयास की पृष्ठभूमि में जाएं तो पता चलेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम-वैचारिक संगठन प्रज्ञा प्रवाह की भोपाल में एक बड़ी बैठक हुई थी। इसमें सरसंघचालक डा. मोहन भागवत भी उपस्थित थे। यहां तय किया गया था कि राजनीति में शुचिता लाने के लिए गैर राजनीतिक लोगों की भागीदारी पार्टी में बढ़ाई जाना चाहिए। बैठक के कुछ समय बाद नगरीय निकाय के चुनाव हुए तो भाजपा ने इंदौर में पुष्यमित्र भार्गव और जबलपुर में डा. जामदार को महापौर का टिकट दिया। भाजपा राजनीतिक शुचिता के लिए अब राजनीति में सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी में है।

मध्य प्रदेश में मिशन-2028 की तैयारी में जुटी पार्टी इस बार अपने टिकट बांटने के फार्मूले में बदलाव करेगी। पार्टी टिकट चयन में सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शामिल न कर प्रोफेशनल्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच से भी बेहतर छवि वाले लोगों को प्रत्याशी बनाएगी। पार्टी की तैयारी 10 से 15 प्रतिशत टिकट समाज के बीच काम करने वाले अच्छे लोगों को देने की है। भाजपा ने 'आइ एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स' के जरिए इस पर काम करना आरंभ भी कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का मानना है कि इससे आने वाले समय में राजनीति में भ्रष्टाचार, अहंकार और जनता से दूरी बनाकर रहने वाले नेताओं से मुक्ति भी मिलेगी और समाज के लोगों की भागीदारी भी राजनीति में बढ़ेगी। समाज में जो अच्छा काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भाजपा ने राजनीतिक क्षेत्र में एक बढ़िया प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया है। 'आइ एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स' से आने वाले समय में राजनीतिक शुचिता लाना है, यह लक्ष्य अब मध्य प्रदेश भाजपा का है।

मंथन

मुस्लिम ओबीसी आरक्षण की समीक्षा

मुनीष त्रिपाठी
वरिष्ठ पत्रकार

देश के अनेक राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है कि लगभग संपूर्ण मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में शामिल कर दिया गया है, जिससे उन्हें आरक्षण की सुविधा मिल रही है। ऐसे में मुस्लिम ओबीसी आरक्षण की समीक्षा आवश्यक है

देश में जनगणना का कार्य पिछले लगभग चार वर्षों से लंबित है। बीते कुछ समय से विपक्ष के कई नेताओं द्वारा जनगणना के साथ जातीय गणना भी करने की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में ऐसा किए जाने के संकेत दिए हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि जातीय गणना के साथ मुस्लिम जातियों की भी जातीय गणना की जा सकती है। केंद्र सरकार यदि इस पर अमल करती है तो वर्ष 2025 में पहली बार सामान्य जातीय गणना के अनुसार मुस्लिम समुदाय के जातियों की भी गणना होगी।

वैसे इस मामले में एक विडंबना यह है कि जातीय गणना का सीधा संबंध विपक्षी पार्टियां आरक्षण की मांग से जोड़ती आ रही हैं। आरक्षण का मुद्दा भारत में समय समय पर उठता रहता है। आरक्षण खतरे में है, इसे मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस सहित विपक्ष ने तमाम नैरेटिव गढ़े हैं। ऐसे में यह भी समझा जाना चाहिए कि ओबीसी आरक्षण कोटे में भारत की कई राज्य सरकारें सेंधमारी कर रही हैं। कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जहां राज्य सरकारें संपूर्ण मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में शामिल करने की कोशिश कर रही हैं। यद्यपि कुछ प्रदेश सरकारों को ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को शामिल करने में सफलता भी मिल रही है। कुछ में कोर्ट के चलते मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने में कामयाबी नहीं मिली है।

तुष्टीकरण : कुछ दिनों पहले बंगाल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे का जिक्र किया जिसमें सरकार द्वारा 78 ओबीसी जातियों में से 77 ओबीसी जातियां मुस्लिम बताई गई हैं। जाहिर है, यहां ममता सरकार के फैसले से मुस्लिम जनसंख्या ओबीसी आरक्षण का हक मारती नजर आ रही हैं। वैसे फिलहाल कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। सत्ता पक्ष के अनुसार ओबीसी वोट के लिए ओबीसी गणना करने की मांग विपक्ष की कोरी राजनीति है, जबकि सच्चाई यह है कि विपक्ष द्वारा ओबीसी के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ओबीसी आरक्षण का उपयोग मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। वैज्ञानिक तरीके से सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी जातियों की पहचान कर संविधान में उन्हें आरक्षण का अधिकार दिया गया है, लेकिन बंगाल में मुस्लिम जातियों को ओबीसी की सूची में उसी दिन शामिल कर लिया गया जिस दिन उनका आवेदन आया था। यानी उनके पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक सर्वे नहीं किया गया।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ओबीसी आरक्षण तुष्टीकरण की राजनीति के लिए है? दोहरेपन की बात यह है कि एससी, एसटी और ओबीसी की बात करने वाले आइएनडीआइए में शामिल कांग्रेस की तेलंगाना सरकार, कर्नाटक सरकार और ममता बनर्जी की सरकार मुस्लिम आरक्षण को ही बढ़ाने के लिए ओबीसी समाज के असली हक को ही मार रही हैं। इन राज्यों में हिंदू ओबीसी के अधिकारों को छीनकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण किया जा रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले भी बंगाल सरकार द्वारा 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत करने को रद कर दिया था व 2010 के बाद बंगाल में जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर ममता सरकार से जवाब मांगा है कि उसने किस आधार पर मुस्लिम जातियों को यह कोटा दिया है।

अन्य कई राज्यों की स्थिति : वहीं देश के कई राज्य ऐसे हैं, जहां मुस्लिमों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। केरल में ओबीसी को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। इसके अंदर ही कुछ कोटा मुस्लिमों के लिए भी है। यहां मुसलमानों को नौकरियों में आठ प्रतिशत और उच्च शिक्षा में 10 प्रतिशत का कोटा मिलता है। तमिलनाडु में भी मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है। यहां पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 3.5 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कोटे में मुसलमानों की 95 प्रतिशत जातियां शामिल हैं। इसी तरह बिहार में मुसलमानों की कुछ जातियों को 'अति पिछड़ा वर्ग' में शामिल किया गया है। अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों और उपजातियों को 18 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। बिहार में हुए जातिगत सर्वे में 73 प्रतिशत मुसलमानों को 'पिछड़ा वर्ग' माना गया था। देश भर में आरक्षण के मामले को तूल पकड़ते हुए देख राजस्थान सरकार ने भी राज्य में दिए जा रहे मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। वहीं हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को जो आरक्षण मिल रहा है, उस पर यहां की सरकार मौन साधे हुए है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुस्लिम ओबीसी जातियों को आरक्षण पर उठाए हैं सवाल। फाइल

ऐसे में देश को इतिहास के वर्ष 1909 के उस कटु अध्याय को नहीं भूलना चाहिए, जिसमें मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत विधान परिषदों, विधानसभाओं में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की शुरुआत की गई थी, जिसने अलगाववाद को जन्म देकर भारत विभाजन की नींव रखी थी।

****

एनएसडीएल का युवा निवेशकों के लिए नया प्लान

नई दिल्ली: युवाओं को जोड़ने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ने युवा प्लान लांच किया है। इसके तहत डीमैट खाता खोलने वाले 24 वर्ष से कम आयु के युवाओं को पहले 36 महीनों के लिए शून्य निपटान शुल्क का लाभ मिलेगा। एनएसडीएल के अंतरिम प्रबंध निदेशक एस गोपालन ने कहा कि हम नवाचार को लेकर प्रतिबद्ध हैं। (एएनआइ)

हमने चालू वित्त वर्ष के अंत तक 900 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा है। साथ ही हम कंस्ट्रक्शन उपकरण बाजार में फिर से प्रवेश करने जा रहे हैं।
— शांतनु राय, चेयरमैन, बीईएमएल

सेंसेक्स 80,081.98 ▼ 138.74 | निफ्टी 24,435.50 ▼ 36.60 | सोना प्रति दस ग्राम ₹81,500 ▼ ₹500 | चांदी प्रति किलोग्राम ₹1,02,000 ▼ ₹1,000 | डालर ₹84.08 बदलाव नहीं | क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल $75.30

एक नजर में

पेटीएम को नए यूपीआइ यूजर जोड़ने की मिली अनुमति

नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआइ) ने पेटीएम को नए यूपीआइ यूजर जोड़ने की अनुमति दे दी है। हालांकि, इसके लिए पेटीएम को सभी दिशानिर्देशों और नियमों का पालन करना होगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंधों के बाद इस कदम को पेटीएम के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। (प्रेट्र)

बीमा भागीदारी के लिए जियो-आलियांज में वार्ता

मुंबई: भारत में बीमा कारोबार में भागीदारी के लिए रिलायंस समूह की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जर्मनी की आलियांज एसई से बातचीत कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, आलियांज और जियो साधारण व जीवन बीमा कंपनी स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। गत मंगलवार को बजाज फिनसर्व ने कहा था कि उसकी भागीदार आलियांज संयुक्त उपक्रम से बाहर निकलना चाहती है। (रायटर)

अपने आइसक्रीम कारोबार को अलग करेगी एचयूएल

नई दिल्ली: दिग्गज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड (एचयूएल) अपने आइसक्रीम कारोबार को अलग करेगी। कंपनी क्वालिटी वाल्स, कारनेटो और मैग्नम ब्रांड नाम से आइसक्रीम कारोबार करती है। कंपनी के सीएफओ रितेश तिवारी ने कहा कि आइसक्रीम कारोबार का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जाएगा। (प्रेट्र)

अदिति राव हैदरी हमदर्द हनी की नई ब्रांड एंबेसडर बनीं

नई दिल्ली: हमदर्द फूड्स इंडिया ने अदिति राव हैदरी को अपने लोकप्रिय ब्रांड हमदर्द हनी का नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है। इसके साथ ही कंपनी ने नया मीडिया कैंपेन 'नो काम्प्रोमाइज हनी' लांच किया है। यह अभियान शहद चुनते समय गुणवत्ता और शुद्धता के महत्व के बहुत ही आकर्षक तरीके से दर्शाता है। हमदर्द फूड्स के सीईओ हामिद अहमद ने बताया कि हमारे ब्रांड के साथ हैदरी का जुड़ाव परंपरा और आधुनिकता का एक आदर्श मिश्रण है। (वि.)

एक साल में सेंसेक्स ने दिया 30 प्रतिशत रिटर्न

पिछली दिवाली के 62 हजार अंक से बढ़कर इस बार 80 हजार के पार पहुंचा बीएसई का प्रमुख सूचकांक

राजीव कुमार ● जागरण

नई दिल्ली: दिवाली पर निवेशक शुभ मुहूर्त में बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ताकि मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। वाकई में बाजार पर मां लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। पिछली दिवाली से लेकर अब तक बाजार में लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिख रही है। सेंसेक्स 62,000 से 80,000 अंक को पार कर गया है। वहीं, इक्विटी म्युचुअल फंड ने तो पिछले एक साल में 50 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।

एचडीएफसी डिफेंस फंड और एलआइसी एमएफ इन्फ्रा फंड ने तो पिछले एक साल में क्रमशः 73 और 65 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले एक साल में कुछ चुनिंदा शहरों के प्रापर्टी बाजार ने भी 30 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है, लेकिन बाजार और म्यूचुअल फंड का रिटर्न सभी निवेशकों के लिए एक समान है चाहे वह गांव में या फिर दिल्ली-मुंबई में रहकर निवेश कर रहा हो। बाजार के रिटर्न का ही आकर्षण है कि अब देश में 18 करोड़ लोगों के पास डीमैट खाते हैं जबकि मात्र चार साल पहले डीमैट खाता रखने वालों की संख्या सिर्फ 3.6 करोड़ थी। यह बाजार के रिटर्न का ही आकर्षण है कि निवेशकों में 22 प्रतिशत महिलाएं हैं और 69 प्रतिशत निवेशक 40 साल से कम उम्र के हैं। इक्विटी संबंधित किसी भी निवेश के लिए डीमैट खाते की जरूरत होती है। पीएचडी चैंबर आफ कामर्स के मुख्य अर्थशास्त्री एसपी शर्मा का मानना है कि बाजार का रिटर्न बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। वर्ष 2001 में निफ्टी 1000 अंक पर था, जो अभी 25,000 को पार कर रहा है। लंबी अवधि में बाजार कम से कम हर साल 15 प्रतिशत रिटर्न जरूर दे रहा है। जानकारों का कहना है कि 20-25 साल पहले प्रापर्टी बाजार में निवेश करने वाले दो-तीन साल में दोगुने का लाभ कमा रहे थे जो अब म्यूचुअल फंड में हो रहा है।

69 प्रतिशत निवेशक 40 साल से कम उम्र के

18 करोड़ लोगों के पास हैं अभी डीमैट खाते

एनसीआर में प्रापर्टी निवेश पर 57 प्रतिशत का रिटर्न मिला

प्रापटाइगर डाट काम के सीएफओ विकास वधावन ने बताया कि पिछले एक साल में मेट्रो और मिनी मेट्रो में प्रापर्टी निवेशकों को 7-22 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। सबसे अधिक एनसीआर में 57 प्रतिशत का रिटर्न दिख रहा है। जानकार कहते हैं कि एनसीआर जैसी जगहों पर प्रापर्टी से कमाई के लिए कम से कम 50 लाख रुपये का निवेश करना होगा। जबकि इक्विटी म्युचुअल फंड और सिस्टमेटिक इंवेस्टमेंट प्लान (एसआइपी) के जरिये मात्र 1000 रुपये प्रतिमाह के निवेश से अच्छी कमाई की जा सकती है। पांच साल पहले अगर किसी ने 10,000 रुपये प्रतिमाह का एसआइपी किया था तो अभी उसके फंड का मूल्य कम से कम 15-17 लाख रुपए के बीच है। मतलब पांच साल में छह लाख रुपये का निवेश ढाई गुने से अधिक का रिटर्न दे रहा है।

म्यूचुअल फंड एक संपदा के रूप में विकसित हो रहा है, जो छोटे शहरों के छोटे निवेशकों को काफी लुभा रहा है। तभी 10 साल पहले यानी कि 2014 में म्यूचुअल फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 10 लाख करोड़ था जो अब 60 लाख करोड़ को छूने जा रहा है। **-रोचक बख्शी,** फाउंडर, ट्रू नार्थ फाइनेंशियल सर्विसेज

छह सत्रों में 10 हजार रुपये बढ़ा चांदी का मूल्य

नई दिल्ली, प्रेट्र: त्योहारी और शादियों की खरीदारी के कारण बुधवार को सोना और चांदी के मूल्य में लगातार छठे दिन तेजी दर्ज की गई। आल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, दिल्ली में सोने के मूल्य में 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई और अब यह 81,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। यह इसका सर्वकालिक उच्च स्तर है। इसी तरह, चांदी के मूल्य में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब दिल्ली में चांदी का मूल्य 1.02 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। इन छह सत्रों में चांदी 10 हजार रुपये प्रति किलोग्राम और सोना 2,850 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ चुका है। एसकेआइ कैपिटल के प्रबंध निदेशक नरेंद्र वाधवा का कहना है कि सोना और चांदी की कीमतों पर पश्चिम एशिया में भूराजनीतिक तनाव और भारत में बढ़ती मांग का साफ असर दिख रहा है।

सरकार सस्ते दामों पर बेचेगी साबुत चना और मसूर दाल

- केंद्र ने बढ़ती कीमतों पर अंकुश के लिए भारत ब्रांड का किया विस्तार
- समितियों को तीन लाख टन चना और 68,000 टन मूंग आवंटित

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने बुधवार को सब्सिडी वाली दालों के अपने कार्यक्रम के विस्तार का एलान किया। अब सरकार बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए 'भारत' ब्रांड के तहत साबुत चना और मसूर दाल भी बेचेगी। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि सहकारी नेटवर्क भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और केन्द्रीय भंडार के जरिये साबुत चना 58 रुपये प्रति किलोग्राम और मसूर दाल 89 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा।

सरकार ने सहकारी समितियों को तीन लाख टन चना और 68,000 टन मूंग आवंटित किया है। एनसीसीएफ की प्रबंध निदेशक अनीस जोसेफ चंद्रा ने कहा कि वितरण दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से शुरू होगा। 10 दिन के भीतर इसके देशव्यापी विस्तार की योजना है। प्रथम चरण के अंतर्गत वर्तमान दरें गेहूं के आटे के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम (27.50 रुपये से ऊपर), चावल के लिए 34 रुपये प्रति किलोग्राम (29 रुपये से अधिक), चना दाल के लिए 70 रुपये प्रति किलोग्राम (60 रुपये से ऊपर) हैं। वहीं मूंग दाल तथा मूंग साबुत की कीमत क्रमशः 107 रुपये प्रति किलोग्राम और 93 रुपये प्रति किलोग्राम है। सरकार प्याज के लिए 35 रुपये और टमाटर के लिए 65 रुपये प्रति किलो की दर बनाए रखने की भी कोशिश कर रही है।

गैर-बासमती सफेद चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाया

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने बुधवार को गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगा 490 डालर प्रति टन का न्यूनतम मूल्य हटाने की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य गैर-बासमती सफेद चावल का निर्यात बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को ही इसके निर्यात पर लगा पूर्ण प्रतिबंध हटाते हुए न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू किया था। सरकार ने एक दिन पहले ही उसना चावल पर निर्यात शुल्क हटाया है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि न्यूनतम निर्यात मूल्य को तुरंत प्रभाव से हटा लिया गया है। गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर पिछले वर्ष 20 जुलाई को प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार के पास पर्याप्त भंडारण होने और खुदरा मूल्यों के नियंत्रण में रहने के कारण निर्यात प्रतिबंध व न्यूनतम मूल्य हटाने जैसे कदम उठाए गए हैं।

एआइ से नई नौकरियों का सृजन होगा, पर कई खत्म भी होंगी

कोलकाता, प्रेट्र: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य (ईएसी-पीएम) संजीव सान्याल ने बुधवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से नई नौकरियों का सृजन होगा और कई पुरानी खत्म भी होंगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे अपनाया जाता है। उद्योग संगठन भारत चैंबर आफ कामर्स के एक कार्यक्रम में सान्याल ने दावा किया कि एआइ अत्यधिक कुशल लोगों को प्रभावित करेगी और मध्यस्थ के काम खत्म हो जाएंगे।

सान्याल ने कहा, 'एआइ को लेकर बहुत चर्चा है। बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि हम इसे कैसे अपनाते हैं। सरकार और जनता के बीच इस पर बहस चल रही है। यह भी सच है कि अगर हम इसे नहीं अपनाएंगे तो पीछे रह जाएंगे।' उन्होंने दावा किया कि उच्च कौशल वाले क्षेत्रों में मौजूदा लोगों की भूमिका समाप्त हो जाएगी जबकि नौकरियां समाप्त भी होंगी और सृजित भी होंगी। अर्थशास्त्री ने कहा, 'एक क्षेत्र है, जहां एआइ निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा और वह शिक्षा है।' उन्होंने कहा कि अमेरिका ने एआई के लिए 'लेसे फेयर' यानी बिना कोई हस्तक्षेप के चीजों को अपने तरीके से आगे बढ़ने की नीति को अपनाया है, जबकि यूरोप नौकरशाही के जरिये नियंत्रण के पक्ष में है।

संजीव सान्याल ● फाइल फोटो

पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य ने कहा-यह इस बात पर निर्भर होगा कि हम इसे कैसे अपनाते हैं

अंधाधुंध कर्ज देने से बचें सूक्ष्म वित्त संस्थान

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्तीय सेवाओं के सचिव एम नागराजू ने बुधवार को कहा कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआइ) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन उन्हें अंधाधुंध कर्ज देने से बचना चाहिए। एक कार्यक्रम में नागराजू ने कहा, 'हमें इस मामले में सावधान रहना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या संयुक्त रूप से कर्ज लेने वाले समूहों (जेएलजी) को बिना सोचे विचारे या जोखिम से निपटने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन किए बिना ऋण देने से इस क्षेत्र को नुकसान होगा।'

उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उनकी भुगतान करने की क्षमता को प्रभावित करेगा, वह वास्तव में एमएफआइ को नुकसान पहुंचाएगा। नागराजू ने कहा कि एसएचजी को बैंक से जोड़ने के कार्यक्रम के तहत 77 लाख से अधिक समूह हैं। उन पर 2.6 लाख करोड़ रुपये का ऋण बकाया है। इससे लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ मिल रहा है।

महंगाई के एक और दौर का जोखिम नहीं उठा सकता भारत

मुंबई, प्रेट्र: भारत महंगाई के एक और दौर का जोखिम नहीं उठा सकता है। वर्तमान में सबसे अच्छा तरीका लचीला बने रहना और महंगाई के संबंध में केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य का समर्थन करना होगा। यह बात आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी बैठक के दौरान रेपो रेट को बरकरार रखने के लिए मतदान करते समय कही।

इस महीने की शुरुआत में आयोजित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के विवरण के अनुसार, दास ने कहा कि मौद्रिक नीति केवल मूल्य स्थिरता बनाए रखकर ही सतत विकास का समर्थन कर सकती है। एमपीसी ने रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया था। पुनर्गठित एमपीसी की यह पहली बैठक थी। तीन नवनियुक्त बाहरी सदस्य राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार हैं।

शक्तिकांत दास ● फाइल फोटो

एमपीसी की बैठक में आरबीआइ गवर्नर ने रेपो रेट को बरकरार रखने के लिए मतदान करते समय की यह टिप्पणी

विवरण के अनुसार, दास ने कहा कि कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिरता और मजबूती की तस्वीर पेश करती है। मुद्रास्फीति में निकट अवधि में तेजी के बावजूद, वर्ष के उत्तरार्ध और अगले वर्ष की शुरुआत में सकल मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण चार प्रतिशत लक्ष्य के साथ रहने का इशारा करता है।

'विकसित भारत' बनाने के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित

वाशिंगटन, प्रेट्र: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार चार प्रमुख क्षेत्रों, बुनियादी ढांचा, निवेश, नवाचार तथा समावेशिता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल के छात्रों के साथ बातचीत के दौरान यह बात कही। वित्त मंत्री अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार दोपहर यहां पहुंचीं। वह न्यूयार्क से वाशिंगटन डीसी तक कार में आईं। इस बीच वह पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में रुकी थीं।

सीतारमण ने छात्रों से कहा, 'जिस वर्ष हम ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, उस समय तक हम एक विकसित देश बनने की आकांक्षा रखते हैं।'

राष्ट्रीय फलक

गुजरात में सीजेआइ और सीबीआइ अधिकारी बता 1.26 करोड़ की ठगी

- कंबोडिया के जालसाजों ने स्थानीय लोगों की मदद से दिया इस धोखाधड़ी को अंजाम
- इस मामले में अहमदाबाद के रहने वाले ठगों के चार सहयोगियों को किया गया गिरफ्तार

अहमदाबाद, प्रेट्र : कंबोडिया के जालसाजों ने स्वयं को सीबीआइ अधिकारी और भारत का मुख्य न्यायाधीश बताकर एक वरिष्ठ नागरिक से 1.26 करोड़ रुपये की ठगी कर ली। अहमदाबाद साइबर अपराध शाखा के एक अधिकारी ने कहा कि ठगों ने शिकायतकर्ता को धन हस्तांतरित करने के लिए डिजिटल अरेस्ट किया। इस मामले में चार स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इन्होंने धोखाधड़ी के लिए अपने बैंक खातों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी।

सहायक पुलिस आयुक्त हार्दिक मकाडिया ने बताया कि इस मामले में अहमदाबाद के रहने वाले मोहम्मद हुसैन जाविद, तरुण सिंह वाघेला, ब्रिजेश पारेख और शुभम ठाकर को गिरफ्तार किया गया है। इस महीने की शुरुआत में सीबीआइ अधिकारी होने का दावा करने वाले एक अज्ञात व्यक्ति ने वरिष्ठ नागरिक को वीडियो काल कर बताया कि उनके बैंक खाते का इस्तेमाल गलत ढंग से रुपये के हस्तांतरण के लिए किया गया है। पीड़ित को बताया गया कि यदि वह वीडियो काल के जरिये जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो पांच साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें गिरफ्तारी से बचाया जा सकता है। उसने बताया कि वीडियो काल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अनुरोध दायर किया गया है। फिर, गिरोह के एक सदस्य ने स्वयं को मुख्य न्यायाधीश बताकर पीड़ित को फोन किया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि फोन करने वाले ने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की तस्वीर को डीपी के रूप में इस्तेमाल किया।

सुप्रीम कोर्ट में बायजू को झटका, दिवालिया कार्यवाही बंद करने का आदेश पलटा

- बीसीसीआइ से समझौते पर भी असर, एलएलसी को दखल का अधिकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : आनलाइन शिक्षण कंपनी बायजू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने नेशनल कंपनी ला अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के फैसले को दरकिनार करते हुए बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही को बंद करने का आदेश अब रद कर दिया है जिससे उसे अब बीसीसीआइ को स्पांसरशिप की रकम चुकानी होगी। कोर्ट का कहना है कि अमेरिकी देनदार ग्लास ट्रस्ट कंपनी (एलएलसी) के पास इस मामले में दखल देने का आधार है। सर्वोच्च अदालत के फैसले से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) को भी झटका लगा है, चूंकि एनसीएलएटी ने जो 158.9 करोड़ के करार की रकम बीसीसीआइ को चुकाने को कही थी, वह अब लेनदारों की समिति को देनी होगी।

यह फैसला प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जस्टिस जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा वाली पीठ ने सुनाया है। उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को निर्देशित किया कि वह समझौते के तहत लेनदारों की समिति (सीओसी) को 158.9 करोड़ रुपये की समझौते की धनराशि प्रदान करे। जमा की गई इस रकम को अब लेनदारों की समिति द्वारा प्रबंधित एक एस्क्रो खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इस फैसले के चलते अब बायजू रवींद्रन और उनके भाई राजू रवींद्रन को नियंत्रण फिर उनकी कंपनी बायजू यानी 'थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड' पर नहीं रहेगा। साथ ही इसकी कारपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया फिर मुश्किल में पड़ जाएगी। शीर्ष अदालत ने पाया कि कारपोरेट दिवालिया समाधान को समय से पहले समाप्त कर दिया था। एनसीएलटी ने 2016 के नियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का आह्वान करके दिवालिया आवेदन वापस लेने की अनुमति देकर गलती की।

यह है मामला : वर्ष 2019 में बायजू भारतीय क्रिकेट टीम का स्पांसर बन गया। कंपनी ने आइसीसी टूर्नामेंट के अधिकार खरीद कर जर्सी पर प्राइमरी स्पांसर की दावेदारी पक्की कर ली। लेकिन 2023 में ओडीआइ वर्ल्ड कप तक के लिए स्पांसरशिप बढ़वा ली, लेकिन बायजू जून,2023 में 1.2 बिलियन डालर के टर्म लोन पर ब्याज भुगतान चूक गया।

कानूनी सहायता व्यवस्था के संचालन के लिए जागरूकता अहम : कोर्ट

- सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करें कानूनी सहायता कार्यालय का पता
- अपने वेबपेज पर कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दे सकते हैं हाई कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कानूनी सहायता व्यवस्था के कामकाज की सफलता के लिए जागरूकता महत्वपूर्ण है। थानों, पोस्ट आफिस, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर निकटतम कानूनी सहायता कार्यालय का पता और फोन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

यह कार्य स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में किया जाना चाहिए। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने जेल में बंद कैदियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता तक पहुंच के पहलू पर कई निर्देश पारित किए।

उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट इस आशय का निर्देश जारी करने पर विचार कर सकते हैं कि सभी अदालतें दोषसिद्धि या बरी किए जाने के फैसले को पलटने और जमानत याचिकाओं को खारिज करने के फैसले की प्रति प्रस्तुत करते समय एक कवर शीट संलग्न कर सकती हैं। इसमें दोषी को ऊंची अदालतों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में सूचित किया जाएगा। हाई कोर्ट अपने वेबपेज पर राज्य में उपलब्ध कानूनी सहायता सुविधाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) राज्यों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सहयोग से यह सुनिश्चित करेगा कि जेल में कैदियों को कानूनी सहायता सेवा तक पहुंच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का सही तरीके से पालन हो। कानूनी सहायता व्यवस्था की सफलता के लिए जागरूकता महत्वपूर्ण है। इसके लिए एजेंसियों को पहल करनी होगी।

एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों को दोबारा पैक कर नहीं बेच सकते : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : एक्सपायर्ड खाद्य उत्पादों की नई पैकिंग कर बिक्री किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी सामग्री बेचने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यह कोई व्यवसाय नहीं हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि आम नागरिकों को मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। पीठ ने न्याय मित्र नियुक्त की गई श्वेताश्री मजूमदार को इस मामले से निपटने के बारे में सुझाव देने को कहा।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता श्वेताश्री मजूमदार ने रिपोर्ट पेश करके अदालत को सुझाव दिया कि निर्माताओं द्वारा सभी पैक किए गए खाद्य पदार्थों के लिए एक क्यूआर कोड तैयार किया जा सकता है, जो उत्पादों की असल समाप्ति तारीख को ट्रैक करने में मदद करेगा।

गाजियाबाद में प्रापर्टी डीलर की हत्या कर शव फार्च्यूनर में जलाया

जागरण संवाददाता, दादरी

- हत्या करने के बाद 31 किमी तक कार में लिए घूमते रहे शव
- प्रापर्टी डीलिंग का साथ में ही काम करने वाले दो आरोपित गिरफ्तार

गाजियाबाद में प्रापर्टी डीलर को बीयर पिलाने के बाद कुत्ते के गले में डाले जाने वाले पट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को गौतमबुद्धनगर के दादरी थानाक्षेत्र में फार्च्यूनर कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हत्याकांड में पुलिस ने प्रापर्टी डीलर के साथ ही काम करने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से प्रापर्टी डीलर से लूटे गए चेन, कड़ा, दो अंगूठी के साथ 6250 रुपये, दो मोबाइल व कुत्ते का पट्टा बरामद किया गया। प्राथमिक पूछताछ के बाद पुलिस लूट के लिए हत्या किए जाने का दावा कर रही है। हालांकि, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। आशंका जताई जा रही है कि प्रापर्टी विवाद के रुपयों के लेनदेन में वारदात को अंजाम दिया गया है।

गौतमबुद्ध नगर के दादरी थाना क्षेत्र के गांव नंगला नैन सुख, आइआइटी कालेज के पास बंजर जमीन में मंगलवार रात करीब 11 बजे राहगीरों ने जलती हुई फार्च्यूनर कार देखी। सूचना पर स्थानीय पुलिस और अग्निशमनकर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। पुलिस ने कार के अंदर देखा तो चालक की सीट पर एक युवक का जला हुआ शव पड़ा था। पड़ताल करने पर शव की गाजियाबाद के नेहरूनगर निवासी प्रापर्टी डीलर संजय यादव के रूप में हुई। पुलिस ने अस्पतालों में जलने वाले किसी व्यक्ति के इलाज कराने के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि गाजियाबाद के अक्षय एन्क्लेव मधुबन बापू धाम निवासी जीत चौधरी ने घटनास्थल के काफी दूर स्थित एक अस्पताल में इलाज कराया है।

बिहार में पुलिस व ग्रामीणों में झड़प, दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल

जासं, अंधराठाढ़ी (मधुबनी) : बिहार में मुधबनी जिले में बुधवार की रात करीब साढ़े सात बजे पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें महिला एएसआइ व एक सिपाही का सिर फट गया। करीब 10 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। इलाके में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट को लेकर कचरा प्रबंधन यूनिट के भवन का निर्माण होना है। ग्राम पंचायत की ओर से भवन निर्माण कराया जा रहा है। करीब तीन माह पहले ग्रामीणों ने इसका विरोध कर निर्माण कार्य को रुकवा दिया था। वह चाहते हैं कि दूसरी जगह निर्माण हो।

बुधवार को स्थानीय प्रशासन बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ वहां पहुंचा। एक बार फिर ग्रामीणों को तकरीबन तीन घंटे तक समझाने का प्रयास किया गया। कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया।

मप्र में तेंदुए को छेड़ा तो कर दिया हमला, तीन घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के गोहपरू वन परिक्षेत्र में जंगल के अंदर पिकनिक मनाकर लौट रहे लोगों को तेंदुए को छेड़ना भारी पड़ गया। गुस्साए तेंदुए ने करीब 50 लोगों के समूह पर हमला कर दिया। घटना 20 अक्टूबर की है। वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद मामला सामने आया।

तेंदुए ने एक महिला के सिर पर पंजे से ऐसा वार किया कि उसके सिर पर गंभीर चोट आई। एक अन्य व्यक्ति की जांघों को तेंदुए ने दांत और पंजे से लहूलुहान कर दिया। इस समूह में कुछ पुलिसकर्मी भी सादे कपड़ों में पिकनिक मनाने आए थे। तेंदुए के हमले में एएसआइ नितिन समदड़िया को गंभीर चोटें आई हैं। वन प्राणी विशेषज्ञों का कहना है कि वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि वन क्षेत्र में लोगों की भीड़ शोर कर रही है और कई समूह उपद्रव भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहां से गुजर रहे तेंदुए को अपनी जान का खतरा लगा और उसने आत्मरक्षा के लिए लोगों पर हमला किया। उधर, तेंदुए की निगरानी में वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

शहडोल में पिकनिक के दौरान तेंदुए से संघर्ष करता पर्यटक। सौजन्य वीडियो ग्रैब।

गृह मंत्रालय ने साइबर कमांडो की शाखा बनाने के लिए जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली, एएनआइ : देश में बढ़ते साइबर खतरों के बीच गृह मंत्रालय ने मंगलवार को साइबर कमांडो की एक विशेष शाखा की स्थापना के लिए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार की यह एडवाइजरी भारतीय एयरलाइंस को 100 से अधिक फर्जी बम की धमकियां मिलने के बाद जारी हुई है।

बम धमकियों से यात्रियों को काफी असुविधा हुई और एयरलाइंस को आर्थिक नुकसान हुआ है। एयरलाइंस को ज्यादातर धमकियां एक्स पर मौजूद अकाउंट पर पोस्ट किए गए थे और अकाउंट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) या डार्क वेब ब्राउजर का उपयोग करके बनाए गए थे, जिनका जांच एजेंसियां पता लगाने में असमर्थ रही हैं। साइबर रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आइ4सी) द्वारा यह निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय पांच वर्षों में पांच हजार साइबर कमांडो को नियुक्त करने की योजना बना रहा है।

****

31 लोग मारे गए हैं सूडान के वाड मदनी में एक मस्जिद को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में। रविवार शाम युद्धक विमानों ने शेख अल जेली मस्जिद और उसके आसपास बमबारी की।

न्यूज गैलरी

कनाडा के वालमार्ट स्टोर में मृत मिली सिख युवती

ओटावा : कनाडा के हैलिफैक्स में वालमार्ट स्टोर के वाक इन ओवन में 19 वर्षीय सिख युवती मृत मिली। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। वह स्टोर में कार्यरत थी। पुलिस ने कहा कि उन्हें शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे इसकी सूचना मिली। उसका शव वाक इन ओवन में पड़ा था। वाक इन ओवन को बैच ओवन भी कहा जाता है। यह एक पहियेदार रैक होता है, जिसमें बड़ी संख्या में चीजों को सुखाया, पकाया जाता है। यह अक्सर सुपरमार्केट जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। मैरीटाइम सिख सोसाइटी के अनमोलप्रीत सिंह ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत दुखद है, क्योंकि वह बेहतर भविष्य के लिए आई थी और उसने अपनी जान गंवा दी। वह हाल ही में भारत से कनाडा आई थी। वालमार्ट कनाडा ने कहा कि कंपनी घटना से दुखी है और उनकी संवेदनाएं युवती के परिवार के साथ है। (प्रेट्र)

इजरायली ठिकानों पर इराकी मिलिशिया का ड्रोन से हमला

बगदाद : शिया मिलिशिया समूह इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक (आइआरआइ) ने बुधवार को इजरायली ठिकानों पर पांच ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, समूह के लड़ाकों ने दक्षिणी इजरायल के ईलात में दो ड्रोन हमले किए, उत्तरी इजरायल में कब्जे वाले गोलान हाइट्स में दो और इजरायल में एक स्थान पर हमला किया। ये हमले फलस्तीन और लेबनान में हमारे लोगों के साथ एकजुटता में किए गए। (आइएएनएस)

नेपाल की सरकार को गिराने की कोशिशें जारी : ओली

काठमांडू : नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बुधवार को कहा कि सांप्रदायिक विद्वेष, घृणा और संघर्ष को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने तथा नेपाल को गर्त की ओर ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो देश एवं देश के लोगों को अस्वीकार्य है। ओली ने सरकार गिरने के संबंध में विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों को खारिज किया है। (प्रेट्र)

पाकिस्तान में हिंदू व सिख परिवारों को नकद राशि

लाहौर : पाकिस्तान की पंजाब सरकार गुरु नानक जयंती व दीपावली के मौके पर प्रांत में प्रत्येक सिख और हिंदू परिवार को 10,000 पाकिस्तानी रुपये देगी। 2200 परिवारों को यह राशि दी जाएगी। पाकिस्तान की पंजाब सरकार प्रांत में प्रत्येक सिख और हिंदू परिवार को एक 'त्यौहार कार्ड' जारी करेगी। अधिकारियों ने बताया कि गुरु नानक देव की 555वीं जयंती मनाने के लिए अगले महीने आने वाले विदेशी तीर्थयात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। (प्रेट्र)

जर्मनी में रूसी पर यूक्रेनी सैनिकों की हत्या का आरोप

बर्लिन : जर्मनी में अपने देश के युद्ध का समर्थन करने वाले एक रूसी व्यक्ति पर दो यूक्रेनी सैनिकों की चाकू घोंपकर हत्या का आरोप लगाया गया है। जर्मन गोपनीयता नियमों के अनुसार, संदिग्ध व्यक्ति का नाम जारी नहीं किया गया है। आरोपित को 27 अप्रैल को छोटे बवेरियन शहर मुर्नाऊ में चाकू घोंपने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया था। म्यूनिख में अभियोजकों ने कहा कि संदिग्ध और मारे गए दोनों सैनिक एक-दूसरे को जानते थे। (एपी)

इस्लामिक फर्म से जुड़े 22 पर संगठित अपराध का आरोप

क्वालालंपुर : मलेशिया में सैकड़ों बच्चों से कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद एक इस्लामी फर्म के सीईओ सहित 22 सदस्यों पर बुधवार को संगठित अपराध समूह का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया है। दोषी पाए जाने पर प्रत्येक को 20 साल तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है। पिछले महीने समूह से जुड़े वेलफेयर हाउस से 500 बच्चों को बचाया गया था। (एपी)

तुर्किये की एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी तुसास पर आतंकी हमला

हमले में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 घायल हुए हैं

दो हमलावर मारे गए, हमले की किसी ने नहीं ली है जिम्मेदारी

अंकारा के बाहरी क्षेत्र में बुधवार को तुर्किये की सरकारी एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी तुसास पर आतंकी हमले के बाद उठता धुआं। (इनसेट-आतंकी हमले के बाद विलखती महिला) एपी

अंकारा, एपी : तुर्किये की राजधानी अंकारा में बुधवार को आतंकी हमला हुआ है। यह हमला एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी तुसास के परिसर में हुआ। हमले में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में दो हमलावार मारे गए। हमले की किसी ने अबतक जिम्मेदारी नहीं ली है। निजी टेलीविजन एनटीवी की ओर से कहा गया है कि सुरक्षाकर्मियों के बदलने के दौरान हमलावर टैक्सी से परिसर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। एक हमलावर ने बम विस्फोट कर दिया, जबकि अन्य परिसर में दाखिल हो गए।

एनटीवी ने आशंका जाहिर की है कि परिसर में कुछ कर्मियों को बंधक बना लिया गया है। परिसर के ऊपर हेलीकाप्टर मंडरा रहे थे। अन्य मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि परिसर में विस्फोट के बाद गोलीबारी की आवाज सुनी गई। एनटीवी टेलीविजन ने बताया कि सुरक्षा बलों, एंबुलेंस और अग्निशमन कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया है। फुटेज में क्षतिग्रस्त गेट और पार्किंग स्थल में गोलीबारी होती नजर आ रही है। हमलावरों को इमारत में प्रवेश करते समय असाल्ट राइफल और बैकपैक के साथ देखा गया। तुसास तुर्किये की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा और विमानन कंपनी में से एक है। इसमें 10,000 से अधिक कर्मचारी हैं।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्किये में हुए घातक हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। नाटो प्रमुख मार्क रूट ने बुधवार को कहा कि सैन्य गठबंधन अपने सहयोगी तुर्किये के साथ खड़ा है। वहीं तुर्किये के व्यापार मंत्री प्रो. डॉ. उमर बोलाट ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं जघन्य आतंकवादी हमले की निंदा करता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि, मुझे यह जानकर दुख हुआ कि आतंकवादी हमले में हमारे कई लोग शहीद और घायल हुए हैं।

उत्तर कोरिया के तीन हजार सैनिकों को भेजा गया रूस

सियोल, एपी : दक्षिण कोरिया के खुफिया प्रमुख ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया के लगभग तीन हजार सैनिकों को रूस भेजा गया है। यूक्रेन के विरुद्ध युद्धक्षेत्रों में तैनाती से पहले उन्हें ड्रोन और अन्य उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इधर, अमेरिका ने बुधवार को पहली बार कहा कि उसके पास उत्तर कोरियाई सैनिकों की रूस में मौजूदगी के साक्ष्य हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लायड आस्टिन ने कहा कि अगर वे यूक्रेन में रूस की तरफ से युद्ध में शामिल होते हैं तो यह बेहद गंभीर मामला होगा।

इससे पहले पिछले सप्ताह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया था कि उनके देश में रूस की तरफ से लड़ने के लिए उत्तर कोरिया के दस हजार सैनिक तैयारी कर रहे हैं। कुछ उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती भी हो चुकी है।

दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा (एनआइएस) निदेशक चो ताए-योंग ने बुधवार को एक संसदीय समिति को इस बारे में जानकारी दी। बैठक में शामिल सांसदों पार्क सुनवोन और ली सेओंग क्वेउन के अनुसार, चो ने बताया कि उनकी एजेंसी को यह पता चला है कि उत्तर कोरिया ने अतिरिक्त 1500 सैनिक रूस भेजे हैं, जो वहां पहले से मौजूद अपने देश के 1500 सैनिकों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उत्तर कोरिया की दिसंबर तक कुल दस हजार सैनिकों को रूस भेजने की योजना है।

पन्नू की हत्या की साजिश में जांच पर सार्थक जवाबदेही चाहता है अमेरिका

- अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा- हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक सार्थक कार्रवाई नहीं होती
- भारत सरकार अमेरिकी धरती पर खालिस्तान समर्थक पन्नू की हत्या की साजिश से कर चुकी है इन्कार
- अमेरिका के आरोपों के बाद भारत ने मामले की जांच के लिए किया था एक जांच समिति का गठन

वेदांत पटेल। फाइल

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका ने कहा कि वह अपनी सरजमीं पर सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश की भारत द्वारा की जा रही जांच के नतीजों पर सार्थक जवाबदेही चाहता है। वह तब तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगा जब तक सार्थक कार्रवाई नहीं हो जाती। हालांकि भारत सरकार ने अमेरिकी सरजमीं पर किसी अमेरिकी नागरिक की हत्या की ऐसी साजिश में अपनी संलिप्तता से साफ इन्कार किया है। अमेरिका के आरोपों के बाद नई दिल्ली ने मामले की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की थी। इस समिति ने पिछले दिनों अमेरिका का दौरा किया था।

विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने पत्रकारों से कहा- 'हम जांच के परिणामों के आधार पर जवाबदेही की उम्मीद करते हैं और निश्चित रूप से अमेरिका तब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि उस जांच के परिणामस्वरूप सार्थक जवाबदेही तय न हो जाए।' उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह भारत की जांच समिति के साथ अहम बातचीत हुई और दोनों सरकारों के बीच अपनी-अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया। हमें उम्मीद है कि भारतीय जांच समिति अपनी जांच जारी रखेगी और पिछले सप्ताह की बातचीत के आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे। पटेल ने कहा कि इसके अलावा वह इस पर और विस्तार से बात नहीं करना चाहते क्योंकि दोनों देश इस मामले की जांच कर रहे हैं। पिछले सप्ताह, अमेरिकी अधिकारियों ने भारत सरकार के एक पूर्व अधिकारी विकास यादव पर पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस मामले में सह-साजिशकर्ता निखिल गुप्ता को पिछले साल चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और वह प्रत्यर्पण के बाद से अमेरिका की जेल में बंद है। यहां बता दें कि पटेल की टिप्पणियों से कुछ दिन पहले विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था कि अमेरिका इस मामले में भारत के सहयोग से संतुष्ट है।

इजरायल के हमले में नसरुल्ला का उत्तराधिकारी भी मारा गया

- इस महीने की शुरुआत में बेरूत में हवाई हमले में सैफीद्दीन हुआ ढेर
- अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजरायल से समझौता करने का किया आग्रह

लेबनान के टायर में बुधवार को इजरायली हवाई हमले के बाद उठता धुआं। (इनसेट सैफीद्दीन) एपी

बेरूत, एपी : इजरायल ने हिजबुल्ला प्रमुख नसरुल्ला के संभावित उत्तराधिकारी हाशिम सैफीद्दीन को भी मार गिराया है। इजरायल ने दावा किया कि उसने इस महीने की शुरुआत में बेरूत में हवाई हमले में सैफीद्दीन को ढेर किया। उसे संगठन प्रमुख नसरुल्ला की जगह लेने की प्रबल संभावना थी। ईरान समर्थित इस संगठन ने भी हवाई हमले में सैफीद्दीन के मारे जाने की पुष्टि की है। बता दें कि 27 सितंबर को इजरायल ने बेरूत के उपनगर दाहिये स्थित हिजबुल्ला के मुख्यालय पर हमला किया था। इसमें नसरुल्ला की मौत हो गई थी।

इजरायल के अनुसार, अक्टूबर की शुरुआत में किए गए हमले में करीब 60 वर्षीय सैफीद्दीन के साथ हिजबुल्ला के 25 अन्य लोग मारे गए। वह संगठन के संस्थापकों में एक था। हाल के महीनों में इजरायल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के कई शीर्ष नेता मारे गए। इजरायल ने पिछले सप्ताह गाजा में हमास प्रमुख याह्या सिनवार को भी मार गिराया था। बेरूत के जिस उपनगर में सैफीद्दीन की मौत हुई थी, वहां मंगलवार को भी हवाई हमले किए गए। इजरायल ने इन हमलों में हिजबुल्ला के ठिकाने को निशाना बनाने की बात कही है। इधर, इजरायल के तेल अवीव में बुधवार को उस समय सायरन की आवाज सुनाई दी, जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यहां से रवाना होने वाले थे। वह जिस होटल में ठहरे थे, उसके ऊपर धुएं का गुबार दिखा। संभवतः यह धुआं उस मिसाइल से निकला, जिसे मार गिराया गया। पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम के प्रयास में ब्लिंकन मंगलवार को इजरायल पहुंचे थे। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। सऊदी अरब रवाना होने से पहले ब्लिंकन ने इजरायल से एक ऐसे समझौते पर विचार करने का आग्रह किया, जिससे गाजा में युद्ध समाप्त हो सके और हमास के हमले के दौरान बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई हो सके। उन्होंने कहा, 'गाजा के मामले में इजरायल ने ज्यादातर रणनीतिक लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। अब समय आ गया है कि इन सफलताओं को स्थायी रणनीतिक सफलता में बदला जाए। अब वास्तव में दो काम हैं, जिसमें बंधकों को घर वापस लाना और युद्ध को समाप्त करना।' जबकि नेतन्याहू ने कहा कि सिनवार के मारे जाने से इजरायली बंधकों की रिहाई पर सकारात्मक असर पड़ सकता है और युद्ध के लक्ष्य को पाने में मदद मिल सकती है।

लेबनानी शहर को बनाया निशाना : इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के ऐतिहासिक शहर टायर पर बुधवार को बमबारी की। कई इमारतों से धुएं का गुबार उठते देखा गया। यह शहर यूनेस्को की सूची में शामिल है। इजरायली हमलों में बीते 24 घंटों के दौरान लेबनान में 28 लोग मारे गए।

अमेरिका चुनावों पर ईरान के हैकर समूहों की निगाहें

- चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं हैकर : माइक्रोसाफ्ट

वाशिंगटन, रायटर

अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित इलेक्शन वेबसाइटों और अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स पर ईरान के हैकिंग ग्रुप की नजर को लेकर माइक्रोसाफ्ट ने अपने ब्लाग में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में शोधार्थियों ने सीधे चुनाव की तैयारियों को प्रभावित करने की कोशिशों की ओर इशारा किया है। मई में भी इन्होंने कई अमेरिकी न्यूज आउटलेट्स की जांच की थी ताकि उनकी कमियों को समझा जा सके।

हैकर्स जिन्हें माइक्रोसाफ्ट ने काटन सैंडस्टार्म नाम दिया है, वे ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े हैं। इन्होंने अमेरिका में चुनाव की नजर से अहम स्विंग रुझान वाले राज्यों में चुनाव से जुड़ी वेबसाइटों की टोह ली और सीमित जांच भी की।

हालांकि अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के आफिस ने इस पर कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। यह एजेंसी चुनावों को विदेशी प्रभाव से बचाने के लिए भी काम करती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने हाल की अपनी टिप्पणियों में 2024 के अमेरिकी चुनावों में किसी तरह की संलिप्तता या हैकिंग की कोशिशों से इंकार किया है।

पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी काटन सैंडस्टार्म ने साइबर आपरेशन को अंजाम दिया था। उस समय फ्लोरिडा राज्य के नागरिकों को दक्षिणपंथी प्राउड ब्वायज नाम से हजारों ईमेल भेज कर धमकियां दी गई थीं। इस समूह ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया था। हालांकि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया कभी प्रभावित नहीं हुई। ये सिर्फ संदेह और भ्रम फैलाने के उद्देश्यनय से किया गया था।

मैकडानल्ड्स का बर्गर खाने से अमेरिका में 49 बीमार, एक की मौत

- ई कोलाई संक्रमण के शिकार सभी लोगों ने मैकडानल्ड्स में खाया था बर्गर
- अधिकांश बीमार पड़ने वालों की संख्या कोलोरेडो और नेब्रास्का से

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका के 10 राज्यों में मैकडानल्ड्स क्वार्टर पाउंडर हैमबर्गर खाने से फैले ई कोलाई संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जनों बीमार हो गए। अमेरिकी रोग नियंत्रण केंद्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों का कहना है कि मैकडानल्ड्स के सबसे लोकप्रिय मेनू आइटमों में से एक से जुड़े ई कोलाई के प्रकोप ने 49 लोगों को बीमार कर दिया है और 10 को अस्पताल भेजना पड़ा। अधिकांश बीमार पड़ने वालों की संख्या कोलोरेडो और नेब्रास्का से है।

इसमें शामिल स्ट्रेन ई कोलाई ओ157:एच7 है, जो गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। यह 1993 के प्रकोप का कारण था, जिसमें जैक इन द बाक्स रेस्तरां में अधपके हैमबर्गर खाने वाले चार बच्चों की मौत हो गई थी। ई कोलाई बैक्टीरिया का एक समूह है जो पेट, मूत्र पथ और शरीर के अन्य भागों में संक्रमण पैदा कर सकता है।

ज्यादातर समय यह आपको नुकसान पहुंचाए बिना आंत में रह सकता है, लेकिन कुछ स्ट्रेन के कारण दस्त, उल्टी और बुखार हो सकता है।

अमेरिकी रोग नियंत्रण केंद्र के अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान बीमार लोगों से जब पूछताछ की गई, तो सभी ने बताया कि बीमार होने से पहले उन्होंने मैकडानल्ड्स में बर्गर खाया था। खासकर क्वार्टर पाउंडर हैमबर्गर का अधिकांश लोगों ने जिक्र किया। अमेरिकी रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार बीमार होने के पीछे के प्रमुख घटक की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जांचकर्ताओं का विशेष ध्यान कटे हुए प्याज और बीफ पैटीज पर है। मैकडानल्ड्स ने प्रभावित राज्यों से इन दोनों चीजों को हटा लिया है।

पाकिस्तान के पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान 30 छात्र घायल

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के पंजाब यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन के दौरान मंगलवार को सुरक्षा गार्डों से हुई झड़प में 30 छात्र घायल हो गए। वे एक छात्रा की आत्महत्या, उत्पीड़न और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। झड़प के दौरान दस सुरक्षा गार्ड और एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले छात्रों ने घटना की जांच की मांग की।

यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता खुर्रम शहजाद ने बुधवार को बताया कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने जब विश्वविद्यालय के गार्डों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर पथराव किया। विश्वविद्यालय के गार्डों पर हमला करने के आरोप में 50 से अधिक छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने देर रात छापेमारी के दौरान कुछ को गिरफ्तार किया है। कि विश्वविद्यालय प्रशासन उन छात्रों को निष्कासित कर सकता है, जिन्होंने अपने साथियों को हिंसा के लिए उकसाया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 2.1 करोड़ अमेरिकी पहले ही कर चुके मतदान

- पांच नवंबर को है चुनाव, भारतवंशी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच है कड़ा मुकाबला
- लगभग 78 लाख वोट प्रारंभिक व्यक्तिगत तरीकों से, शेष 1.33 करोड़ से अधिक वोट मेल से पड़े

अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में मतदान करती युवती। एपी

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पांच नवंबर को होने हैं। इसे देखते हुए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बीच लगभग 2.1 करोड़ अमेरिकी पहले ही अपना वोट डाल चुके हैं। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में इलेक्शन लैब के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 78 लाख वोट प्रारंभिक व्यक्तिगत तरीकों से आए हैं, जबकि शेष 1.33 करोड़ से अधिक वोट मेल के माध्यम से डाले गए हैं।

भारत में होने वाले आम चुनावों के विपरीत अमेरिका में प्रचार और मतदान लगभग चार सप्ताह तक एक-दूसरे के समानांतर चलता है। भारत में मतदान शुरू होने से 36 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाता है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि विजेता का फैसला सात प्रमुख माने जाने वाले राज्यों एरिजोना, नेवादा, विस्कान्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना और जार्जिया में चुनाव के नतीजों पर किया जाएगा।

अमेरिकी मतदाताओं के लिए प्रारंभिक मतदान एक अनूठा प्रविधान है, जिसमें मतदाता मेल-इन-बैलेट मांगकर वोट डालते हैं। यह कुछ मायनों में भारत के डाक मतपत्रों की तरह ही है। वहीं, दूसरी ओर वे मतदान केंद्रों पर भी जाकर वोट डालते हैं, जो वास्तविक मतदान दिवस से कुछ सप्ताह पहले खुल जाते हैं। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय की इलेक्शन लैब के अनुसार, एशियाई अमेरिकियों के बीच शुरुआती मतदान प्रतिशत केवल 1.7 प्रतिशत है। हालांकि, कई जगहों पर कई भारतीय अमेरिकियों को वोट डालने के लिए लाइनों में खड़े देखा गया। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि वैश्विक नेता ट्रंप से भयभीत हैं। उनका कहना है कि ट्रंप जीत नहीं सकता।

राष्ट्रीय फलक

चेहरों पर साफ नजर जा रहे आतंकी हमले के निशां

राज्य ब्यूरो, जागरण. श्रीनगर : आसपास ऊंचे पहाड़ और घने जंगल के साथ बहता सिंध नाला और उसके किनारे पर स्थित मकान और खेत। ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार ने कोई चित्र बनाया है। कुछ ऐसा ही है, लाल चौक से करीब 73 किलोमीटर दूर श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गगनगीर। यह वह जगह है जहां सोनमर्ग और लेह जाने वाले पर्यटक कुछ समय के लिए रुककर खूबसूरती को निहारते हैं। बुधवार को यहां ऐसा कुछ भी नहीं था।

गांव के भीतर और बाहर से गुजरने वाली सड़क पर पर्यटक नहीं, सुरक्षाबलों के वाहनों का जमावड़ा था। एक अजीब सी खामोशी, जो बता रही थी कि रविवार की रात को गूंजी गोलियों ने गांव की खुशियां छीन ली हैं। गांदरबल जिले के गगनगीर में आतंकियों ने जेड़ मोड़ सुरंग परियोजना के निर्माण में जुटी कंपनी के शिविर पर हमला किया था, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई।

आतंकियों ने जिस जगह मौत का नंगा नाच खेला, उससे कुछ ही दूरी पर अपने घर में बैठे मोहम्मद रमजान मीर ने कहा, मेरी उम्र साठ साल हो गई है, जो रविवार रात देखा, वैसा पहले कभी नहीं देखा था। करीब साढ़े सात बजे अचानक गोलियों की आवाज गूंजी।

सीमा सड़क संगठन में काम करने वाले रमजान मीर ने एक मकान की तरफ संकेत करते हुए कहा कि उस घर में शादी समारोह था। शुरू में हमने पटाखा समझा, लेकिन जब लगातार गोलियों की आवाज गूंजी तो समझ गए कि कोई हमला हुआ है। रुबीना ने कहा कि हमारे घर सोमवार को बरात आनी थी। काफी देर बाद पता चला कि सामने कैंप पर हमला हुआ है।

नक्सलियों के साथ मुठभेड़ से पहले घने जंगलों में 70 घंटे पैदल चले थे कमांडो

- गढ़चिरौली में दो मुठभेड़ों में मारे गए थे 38 लाख इनाम वाले पांच नक्सली

नागपुर, प्रेट्र : महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों से मुठभेड़ से पहले सोमवार को पुलिस की सी-60 विशेष लड़ाकू इकाई के कमांडो कुमोद आत्राम और उनके साथियों को 70 घंटे तक जंगलों में पैदल चलना पड़ा।

दो मुठभेड़ों में पांच नक्सली मारे गए थे, जिनके सिर पर कुल 38 लाख रुपये का इनाम था। इस दौरान आत्राम को दो गोलियां लगीं और अब सर्जरी के बाद एक निजी अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है।

सी-60 गढ़चिरौली पुलिस का एक विशेष नक्सल विरोधी बल है। आठ साल से गढ़चिरौली पुलिस में सेवारत आत्राम को करीब 10 मुठभेड़ों में 39 नक्सलियों को ढेर करने का श्रेय दिया जाता है। इस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। सी-60 कमांडो और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों ने भामरागढ़ तहसील के जंगलों में सोमवार को हुई मुठभेड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

आत्राम ने बताया कि जब हम अबूझमाड़ के दुर्गम इलाके में 70 घंटे से अधिक समय तक पैदल चले थे, तभी नक्सलियों ने हम पर हमला कर दिया। गोलीबारी सुबह करीब आठ बजे शुरू हुई और करीब 10 बजे भारी गोलीबारी के बीच मुझे गोली लग गई।

आगे बताया कि इसके बाद मुझे हेलीकाप्टर से नागपुर लाया गया। पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ में मारे गए लोगों में माओवादियों के डिविजनल कमेटी के दो सदस्य भी शामिल हैं।

महिला पायलट ने जान जोखिम में डालकर कमांडो को बचाया

गढ़चिरौली, प्रेट्र : सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ के दौरान एक बहादुर महिला हेलीकाप्टर पायलट ने अपनी जान जोखिम में डालकर घायल पुलिस कमांडो को सुरक्षित निकाला। कैप्टन रीना वर्गीज की बहादुरी ने कमांडो कुमोद आत्राम की जान बचाने में मदद की। पवन हंस हेलीकाप्टर की पायलट कैप्टन वर्गीज ने गढ़चिरौली से सीधे ग्राउंड जीरो पर उड़ान भरी, जहां मुठभेड़ चल रही थी। चट्टानी और जंगली इलाके में उतरने में असमर्थ होने पर कैप्टन वर्गीज ने अपने सह-पायलट को हेलिकाप्टर का नियंत्रण सौंप दिया और घायल कमांडो तक पहुंचने के लिए 11 फुट की ऊंचाई से छलांग लगा दी।

पकड़ा गया वाहन चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का बदमाश

- चोरी के लिए लग्जरी वाहनों की रेकी करने देहरादून पहुंचे थे बदमाश
- टी-एस्टेट के जंगल में पुलिस से हुई मुठभेड़, एक को लगी गोली

जागरण संवाददाता, देहरादून

दीवाली व धनतेरस पर नए वाहनों को चुराने के लिए उनकी रेकी करने देहरादून पहुंचे उत्तर प्रदेश के अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। मंगलवार रात टी-एस्टेट के जंगल में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस की फायरिंग में गिरोह के एक सदस्य के दाहिने पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसका साथी फरार हो गया। फरार बदमाश की पहचान हरदोई निवासी अभिषेक वाजपेयी के रूप में हुई है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान अनुभव त्रिपाठी निवासी सिनेमा रोड, हरदोई के रूप में हुई है। उसके विरुद्ध दिल्ली व उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे दर्ज हैं। वह पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस को उसके कब्जे से एक तमंचा भी बरामद हुआ है।

दिल्ली से चुराई कार से आए थे बदमाश : पकड़े गए बदमाश से होंडा अमेज कार भी बरामद हुई है। इंजन नंबर व चेसिस नंबर से मिलान के आधार पर कार में लगा नंबर प्लेट फर्जी पाया गया। कार का वास्तविक नंबर दिल्ली का था, जिसे उसने एक सप्ताह पूर्व दिल्ली से चुराया था। मामले में प्रशांत विहार थाने में मुकदमा दर्ज है। अनुभव ने बताया कि उनका गिरोह दिल्ली व एनसीआर में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। गिरोह में तीन अन्य साथी अभिषेक वाजपेयी, शिवांश त्रिपाठी और मोहम्मद सलीम भी हैं।

****

पंत करेंगे विकेटकीपिंग, राहुल को मौका संभव

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से, शुभमन गिल की वापसी से सरफराज का बाहर बैठना लगभग तय

पुणे, प्रेट्र: बेंगलुरु में अप्रत्याशित हार के बाद भारतीय टीम जब गुरुवार से पुणे में न्यूजीलैंड के विरुद्ध दूसरे टेस्ट मैच में उतरेगी तो उसकी नजरें जीत के अलावा बेहतर टीम संतुलन पर होंगी। तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड 1-0 से आगे है और बेहतर टीम संयोजन ही भारतीय टीम की सीरीज में वापसी कराएगा। अगले महीने आस्ट्रेलिया के विरुद्ध पांच टेस्ट मैच की सीरीज से पहले रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम की प्राथमिकता न्यूजीलैंड के विरुद्ध अगले दोनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

बेंगलुरु में घुटने में चोट लगने के बाद विकेटकीपिंग से दूर रहे पंत ने मंगलवार को अभ्यास सत्र में कुछ समय के लिए विकेटकीपिंग की थी। कोच गंभीर ने बुधवार को कहा कि पुणे में पंत ही विकेटकीपिंग करेंगे। शुभमन गिल वापसी करने के लिए तैयार है तथा केएल राहुल और सरफराज खान में से किसी एक को उनके लिए जगह खाली करनी होगी। मुख्य कोच गौतम गंभीर राहुल को अधिक मौके दिए जाने के पक्ष में हैं। भारतीय टीम प्रबंधन भले ही राहुल का पक्ष ले रहा हो लेकिन यह बल्लेबाज पिछले कुछ समय से रन बनाने के लिए जूझ रहा है। इसके बावजूद कोच गौतम गंभीर ने स्पष्ट कर दिया है कि इंटरनेट मीडिया पर केएल राहुल को लेकर क्या चल रहा है, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। गंभीर के रुख को देखकर माना जा रहा है कि पुणे में सरफराज का अंतिम एकादश से बाहर होना तय है। शुभमन के खेलने पर विराट फिर से नंबर चार, उनके बाद रिषभ पंत और छठे नंबर पर केएल राहुल बल्लेबाजी करने आएंगे।

भारत की समस्या बल्लेबाजी तक ही सीमित नहीं है। उसकी गेंदबाजी में भी कुछ समस्या हैं विशेषकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का लगातार खराब प्रदर्शन चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में टीम प्रबंधन आकाश दीप को मौका दे सकता है जिन्होंने मंगलवार को बल्लेबाजी का भी जमकर अभ्यास किया है। वाशिंगटन सुंदर को भी टीम में शामिल किया गया है। उन्हें अगर अंतिम एकादश में शामिल किया जाता है तो इससे भारत की बल्लेबाजी भी मजबूत होगी। महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम की पिच को भारत की स्थिति को देखकर तैयार किया गया है। काली मिट्टी से बनी इस पिच पर घास नहीं है, जिससे न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को बेंगलुरु जैसा उछाल नहीं मिलेगा।

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों विलियम ओरूर्के, मैट हेनरी और टिम साउदी ने पहले मैच में भारतीय बल्लेबाजों को खासा परेशान किया था। ऐसे में भारत टर्निंग विकेट तैयार कर सकता है, लेकिन उसका यह दांव अतीत में उल्टा पड़ चुका है। आस्ट्रेलिया ने आठ वर्ष पहले पुणे की टर्निंग विकेट पर भारत को 333 रन से हराया था। इसी टीम ने पिछले साल इंदौर में खेले गए मैच में भारतीय टीम नौ विकेट से पराजित किया था।

जहां तक न्यूजीलैंड की बात है तो उसकी तरफ से बेंगलुरु में खेले गए पहले टेस्ट मैच में रचिन रवींद्र ने शतक जमाकर अंतर पैदा किया था लेकिन उसकी टीम अन्य बल्लेबाजों से भी उपयोगी योगदान की उम्मीद कर रही होगी।

पुणे में दूसरे टेस्ट मैच से पहले बुधवार को पिच का निरीक्षण करते रोहित शर्मा, कोच गौतम गंभीर और जडेजा ● एएफपी

टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली से आगे निकले रिषभ पंत

रिषभ पंत बुधवार को आइसीसी की बल्लेबाजों के लिए टेस्ट रैंकिंग में अपने सुपरस्टार भारतीय साथी विराट कोहली को पीछे छोड़कर छठे स्थान पर पहुंच गए। पंत ने बेंगलुरु टेस्ट की दूसरी पारी में 99 रन बनाए थे, जिससे उन्हें रैंकिंग में तीन स्थान का लाभ हुआ। दूसरी तरफ कोहली 70 रन बनाने के बावजूद एक पायदान नीचे आठवें स्थान पर खिसक गए हैं। आरंभिक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल चौथे स्थान पर भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले बल्लेबाज बने हुए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दो पायदान नीचे गिरकर श्रीलंका के दिमुथ करुणारत्ने के साथ संयुक्त 15वें स्थान पर हैं।

टीमें

भारत : रोहित शर्मा (कप्तान), जसप्रीत बुमराह (उपकप्तान), यशस्वी, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, रिषभ पंत, ध्रुव जुरैल, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, वाशिंगटन सुंदर।

न्यूजीलैंड : टाम लाथम (कप्तान), डेवोन कान्वे, केन विलियमसन, मार्क चैपमैन, विल यंग, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर, रचिन रवींद्र, टाम ब्लंडेल, एजाज पटेल, मैट हेनरी, टिम साउथी, विलियम ओ राउरकी, जैकब डफी।

> 'केएल राहुल के मामले में इंटरनेट मीडिया बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि टीम प्रबंधन और नेतृत्व क्या सोचता है। वह अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है और कानपुर में अच्छी पारी खेली थी। मुझे यकीन है कि उसे पता है कि उसे बड़ी पारी खेलनी है और वह खेल सकता है। यही वजह है कि टीम उसके साथ है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सभी पर टीका टिप्पणी की जाती है।'
> – **गौतम गंभीर**, मुख्य कोच, भारत

अगर शमी उपलब्ध नहीं, मयंक को आस्ट्रेलिया ले जाएं : ब्रेट ली

क्रिकेट डायरी

सिडनी, प्रेट्र : आस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक रहे ब्रेट ली ने कहा है कि अगर मोहम्मद शमी चयन के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो मयंक यादव को आस्ट्रेलिया दौरे पर जाना चाहिए। ली को आस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिचों पर इस भारतीय तेज गेंदबाज से बहुत आशाएं हैं।

भारत की नजरें लगातार तीसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने पर टिकी हैं और टीम पांच टेस्ट मैच की बार्डर-गावस्कर ट्राफी में अपने खिताब की रक्षा के लिए अगले महीने आस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। इस बीच अनुभवी तेज गेंदबाज शमी की फिटनेस को लेकर संशय बना हुआ है। ली ने 'फाक्स क्रिकेट' से कहा, 'मैं आपको बता सकता हूं कि बल्लेबाजों को 135-140 किमी प्रति घंटा की रफ्तार की गेंदों का सामना करने में कोई परेशानी नहीं है लेकिन जब आप 150 किमी प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं तो कोई इसका सामना नहीं करना चाहता।' उन्होंने कहा, 'वह एक पूर्ण पैकेज की तरह नजर आते हैं। अगर मोहम्मद शमी फिट नहीं होते तो उन्हें कम से कम टीम में जगह तो मिलनी ही चाहिए। मुझे लगता है कि वह आस्ट्रेलिया के विकेटों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा।' शमी ने पिछले वर्ष नवंबर में विश्व कप के फाइनल के बाद से कोई मैच नहीं खेला है और भले ही उन्होंने हाल ही में नेट पर पूरी ताकत से गेंदबाजी की हो, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस तेज गेंदबाज को पूरी तैयारी और फिटनेस के बना आस्ट्रेलिया ले जाने के विरुद्ध हैं।

ली ने स्वीकार किया कि भारत के पास विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण है जो आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को उनके घरे में परेशान कर सकता है। इस पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, 'अश्विन 600 विकेट लेने के करीब हैं, वह शानदार स्पिन गेंदबाजी करते हैं। वह नई गेंद से भी गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारत को वहां जीतना है तो शमी निश्चित रूप से अहम भूमिका निभा सकते हैं।'

टेस्ट सीरीज जीतने उतरेंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान

रावलपिंडी, एपी : स्पिनरों के कमाल से दूसरा टेस्ट मैच जीतकर उत्साह से भरी पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के विरुद्ध गुरुवार से यहां शुरू होने वाले तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में धीमी गति के गेंदबाजों के लिए अनुकूल पिच पर जीत दर्ज करके तीन मैच की सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगी। मैदानकर्मी इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ दिनों से विकेट को सुखाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली और आफ स्पिनर साजिद खान ने मुल्तान में दूसरे टेस्ट में टर्न लेते विकेट पर इंग्लैंड के सभी 20 विकेट लिए, जिससे पाकिस्तान ने यह मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर की।

एक नजर में

सुल्तान जोहोर कप में भारत को आस्ट्रेलिया ने हराया

जोहोर बाहरु: आस्ट्रेलिया ने सुल्तान जोहोर कप में भारत की लगातार तीन मैचों की जीत के क्रम को तोड़ते हुए बुधवार को 4-0 से हरा दिया। भारतीय स्ट्राइकर आस्ट्रेलिया की मजबूत डिफेंस को नहीं भेद नहीं सके, वहीं आस्ट्रेलिया की ओर से डेकिन स्टेंजर (33वें, 39वें और 53वें) ने हैट ट्रिक जबकि पैट्रिक एंड्रयू (29वें) ने शुरुआती गोल दागा। हालांकि, इसके बावजूद भारत शीर्ष पर है। (प्रेट्र)

पहली निशानेबाजी लीग की तैयारी में एनआरएआइ

नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआइ) ने बुधवार को देश में खेल की पहली फ्रेंचाइजी आधारित लीग की घोषणा की जिसे 'भारतीय निशानेबाजी लीग' नाम दिया गया है। एनआरएआइ अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव के प्रस्ताव को राष्ट्रीय महासंघ की संचालन संस्था ने स्वीकृति दी। आइएसएसएफ से स्वीकृति मिलने के बाद इस लीग के लिए विंडो तय की जाएगी। लीग का पहला सत्र मार्च में होगा। (जासं)

त्रिपुरा के विरुद्ध रणजी मैच में नहीं खेलेंगे श्रेयस

मुंबई: मुंबई के सीनियर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर निजी कारणों से त्रिपुरा के विरुद्ध अगरतला में 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले रणजी ट्राफी के तीसरे दौर के मैच में नहीं खेलेंगे। मुंबई क्रिकेट संघ ने बुधवार को बताया कि अय्यर ने मुंबई की सीनियर चयन समिति से कुछ दिन का विश्राम देने की अपील की थी जिसे स्वीकार कर लिया गया है। (प्रेट्र)

अंडर-17 क्वालीफायर में भारत ने ब्रूनेई को रौंदा

वोनबुरी: भारतीय अंडर-17 फुटबाल टीम ने अंडर-17 एशियाई कप के क्वालीफायर के पहले मुकाबले में ब्रूनेई को 13-0 से रौंद दिया। इस दौरान भारत की ओर से विशाल यादव ने हैट ट्रिक दागा, शेष 10 गोल टीम के अन्य खिलाड़ियों ने दागा। (प्रेट्र)

आयुष बडोनी की पारी से भारत 'ए' ने लगाई जीत की हैटट्रिक

एमर्जिंग एशिया कप

भारत ने ओमान को छह विकेट से हराया, सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से होगा सामना

मस्कट, प्रेट्र: आयुष बडोनी की अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत ए टीम ने एमर्जिंग एशिया कप में बुधवार को ओमान को छह विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज की। ग्रुप में तीन जीत के साथ भारत शीर्ष स्थान पर रहा और अब सेमीफाइनल में उसका सामना अफगानिस्तान की टीम से होगा।

बुधवार को खेले गए मुकाबले में ओमान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ए के सामने 141 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने केवल 15.2 ओवर में चार विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। दिल्ली के युवा बल्लेबाज बडोनी ने ओमान के स्पिनरों के विरुद्ध अपने शानदार फुटवर्क का प्रदर्शन किया और उनके विरुद्ध जमकर रन कूटे। बडोनी ने केवल 27 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली। उनके अलावा ओपनर अभिषेक शर्मा ने केवल 15 गेंद पर 34 रन की पारी खेली और तिलक वर्मा ने भी 30 गेंदों में 36 रन की अविजित पारी खेली। इससे पहले तिलक ने ओमान के विरुद्ध आठ गेंदबाजों को आजमाया, जिनमें से पांच ने एक-एक विकेट लिया।

जिंबाब्वे ने बनाया टी-20 का सबसे बड़ा स्कोर, ठोक डाले 344 रन

नई दिल्ली, जेएनएन: कप्तान सिकंदर रजा की तूफानी पारी की बदौलत जिंबाब्वे ने बुधवार को टी-20 इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर डाला। टी-20 विश्व कप सब रीजनल अफ्रीका क्वालीफायर मुकाबले में जिंबाब्वे ने गांबिया के विरुद्ध चार विकेट पर 344 रन ठोक डाले। जिंबाब्वे ने नेपाल का रिकार्ड तोड़ा, जिसने पिछले वर्ष एशियाई खेलों में मंगोलिया के विरुद्ध 314 रन बनाए थे। जिंबाब्वे की ओर से 20 ओवर में 30 चौकों के अलावा 27 छक्के लगे और इनमें से 15 अकेले सिकंदर रजा ने जड़े।

रजा ने केवल 43 गेंदों में 133 रनों की पारी खेली। 344 रन के जवाब में गांबिया की टीम केवल 54 रन पर आलआउट हो गई। जिंबाब्वे ने 290 रन से यह मैच जीता, जो टी-20 इतिहास की रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत है। इसके साथ ही जिंबाब्वे टी-20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली टेस्ट दर्जा प्राप्त टीम भी बन गई है। उसने भारतीय टीम को पीछे छोड़ा, जिसने 18 अक्टूबर को हैदराबाद में बांग्लादेश के विरुद्ध छह विकेट पर 297 रन का स्कोर बनाया था।

सिकंदर रजा ● एपी

टी-20 में सर्वाधिक टीम स्कोर

स्कोर	टीम	बनाम	स्थान	वर्ष
344/4	जिंबाब्वे	गांबिया	नैरोबी	2024
314/3	नेपाल	मंगोलिया	हांगझू	2023
297/6	भारत	बांग्लादेश	हैदराबाद	2024
286/5	जिंबाब्वे	सेशेल्स	नैरोबी	2024
278/3	अफगानिस्तान	आयरलैंड	देहरादून	2019

टी-20 में बड़ी जीत (रन अंतर)

रन	टीम	बनाम	स्थान	वर्ष
290	जिंबाब्वे	गांबिया	नैरोबी	2024
273	नेपाल	मंगोलिया	हांगझू	2023
257	चेक गणराज्य	तुर्किये	इलोफ काउंटी	2019
208	कनाडा	पनामा	कूलिज	2021
205	जापान	मंगोलिया	सानो	2024

न्यूजीलैंड के बोवेस ने 'लिस्ट ए' में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा

वेलिंगटन, प्रेट्र: न्यूजीलैंड के प्रारंभिक बल्लेबाज चाड बोवेस ने बुधवार को केवल 103 गेंद पर दोहरा शतक जड़कर लिस्ट ए क्रिकेट में नया रिकार्ड बनाया। बोवेस ने खेल के इस प्रारूप में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकार्ड अपने नाम किया जो इससे पहले भारत के नारायण जगदीसन और आस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड के नाम दर्ज था। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे बोवेस ने फोर्ड ट्राफी में कैंटरबरी की ओर से ओटागो के विरुद्ध खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की। वह अंत में 110 गेंद पर 205 रन बनाकर आउट हुए जो लिस्ट ए क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर भी है। जगदीसन और हेड ने 114 गेंदों में अपने-अपने दोहरे शतक पूरे किए थे।

चाड बोवेस ● एपी

जर्मन 'दीवार' जोशुआ ने विफल किया भारत का हर वार

नितिन नागर, जागरण

नई दिल्ली : पेरिस ओलिंपिक के सेमीफाइनल में हार का हिसाब चुकाना तो दूर हमरनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय हाकी टीम बुधवार को युवा जर्मन टीम के सामने बेहद साधारण प्रदर्शन किया। 10 वर्ष बाद किसी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले की मेजबानी कर रहे दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले गए टेस्ट मैच में जर्मनी ने भारत को 2-0 से पराजित किया। पेरिस में कांस्य पदक जीतने वाले भारत को इस मुकाबले में आठ पेनाल्टी कार्नर और एक पेनाल्टी स्ट्रोक मिला, लेकिन जर्मन गोलकीपर जोशुआ नाजी ओंयेकवू दीवार बनकर खड़े हो गए, जिसे भारतीय आक्रमण भेद ही नहीं सका। यहां तक कि पेरिस ओलिंपिक में पेनाल्टी कार्नर से सर्वाधिक गोल दागने वाले हरमनप्रीत जब पेनाल्टी स्ट्रोक लेने आए तो ओंयेकवू ने सीधे शाट को रोकते हुए भारतीय टीम से गोल करने का सबसे अच्छा अवसर भी छीन लिया। भारत और जर्मनी के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच गुरुवार को खेला जाएगा।

जोशुआ ने ठंडा किया मेजबानों का जोश : पेरिस ओलिंपिक में भारतीय टीम ने पेनाल्टी कार्नर पर सर्वाधिक गोल दागे थे, लेकिन यहां यही उसकी बड़ी कमजोरी बनकर उभरा। आठ में से एक भी पेनाल्टी कार्नर का गोल में तब्दील नहीं होना हैरान करने वाला है। आठवें मिनट में भारत को पहला पेनाल्टी कार्नर मिला था, लेकिन यहां सुखजीत के प्रयास को जोशुआ ने विफल कर दिया। दूसरे क्वार्टर में भारत को चार पेनाल्टी कार्नर और एक पेनाल्टी स्ट्रोक मिला।

21वें मिनट में मनप्रीत सिंह ने संजय को अच्छा पास दिया जिसने दिलप्रीत सिंह को गेंद सौंपी लेकिन उनका शाट बाहर निकल गया। अगले मिनट संजय पेनाल्टी कार्नर पर गोल नहीं कर पाए। 25वें मिनट में अमित रोहिदास चूके तो 26वें मिनट में मिले दो पेनाल्टी कार्नर हरमनप्रीत ने गंवाए। अगले ही मिनट में पेनाल्टी कार्नर पर दिलप्रीत ने रिबाउंड पर गोल किया लेकिन जर्मनी ने रेफरल लिया जिसके बाद भारत को पेनाल्टी स्ट्रोक मिला। विश्व के सर्वश्रेष्ठ ड्रैग फ्लिकरों में से एक हरमनप्रीत ने यहां सीधा शाट खेला, लेकिन जोशुआ ने इसे भी रोक दिया।

मैच के तीसरे ही मिनट में हेनरिक मर्टजेंस के गोल से बढ़त बना ली। इसके बाद दूसरे क्वार्टर के अंतिम मिनट में मिले पेनाल्टी कार्नर पर लुकास ने जर्मनी के लिए गोल दागा।

जर्मनी के विरुद्ध मुकाबले में गोल दागने का प्रयास दिलप्रीत ● प्रेट्र

पहले हाकी टेस्ट में जर्मनी ने भारतीय टीम को 2-0 से हराया, आज खेला जाएगा दूसरा मैच

> 'हम हर मैच जीतना चाहते हैं लेकिन हमारे पास प्रयोग करने के लिये यही एक मौका है चूंकि हमारा मुख्य लक्ष्य प्रो लीग है। प्रो लीग में अच्छा खेलने से हम सीधे विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं। हमारी टीम में कुछ युवा खिलाड़ी हैं। यह उनके लिए अच्छा अवसर है क्योंकि मजबूत टीम के खिलाफ जितना खेलेंगे, उतना ही लय में आएंगे और सीखेंगे।
> – **हरमनप्रीत सिंह**, भारतीय कप्तान

मेहदी हसन ने बांग्लादेश को पारी की हार से बचाया

बांग्लादेशी आलराउंडर ने पदार्पण कर रहे जाकिर अली के साथ सातवें विकेट के साथ की 138 रनों की साझेदारी

मीरपुर, एपी: मेहदी हसन मिराज की अविजित 87 रन की पारी से बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध दो मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट में पारी की हार को टालते हुए तीसरे दिन बुधवार को 81 रन की बढ़त हासिल कर ली।

वर्षा और खराब रोशनी के कारण खेल रोके जाते समय बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में सात विकेट पर 283 रन बना लिए। मेहदी के साथ क्रीज पर नईम हसन (16*) उपस्थित हैं। मेहदी ने अपनी 171 गेंद की अविजित पारी में नौ चौके और एक छक्का लगाया है। बांग्लादेश ने दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 101 रन से की। उसे पारी की हार से बचने के लिए और 101 रन की जरूरत थी। टीम दिन की शुरुआत में 11 रन के रन अंदर तीन और विकेट गंवाकर मुश्किल में थी लेकिन मेहदी ने पदार्पण कर रहे जाकिर अली (58) के साथ सातवें विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला।

बांग्लादेश पहली पारी में 106 रन पर आउट हो गया, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने काइल वेरिने के 114 रन के दम पर 308 रन बनाए। तेज गेंदबाज कैगिसो रबादा (चार विकेट) और बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज (तीन विकेट) ने आपस में सात विकेट लिए।

मेहदी हसन ● एएफपी

साक्षी के आरोप पर बोलीं बबीता, किताब के चक्कर में ईमान बेच गईं

नई दिल्ली, एएनआइ : भाजपा नेता और पूर्व महिला पहलवान बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक को जवाब देते हुए कहा कि एक किताब बेचने के लिए उन्होंने अपना ईमान बेच गईं। पूर्व ओलिंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी ने दावा किया था कि बबीता ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध सभी पहलवानों को इकट्ठा किया ताकि वह डब्ल्यूएफआइ के अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा सके।

बबीता ने एक्स पर लिखा, खुद के किरदार से जगमगाओ, उधार की रोशनी कब तक चलेगी। किसी को विधानसभा मिली, किसी को मिला पद, तुम्हें कुछ नहीं मिला, इसका दर्द हम समझ सकते हैं। किताब बेचने के चक्कर में अपना ईमान बेच गईं। इससे पहले, बबीता की बहन गीता फोगाट ने भी साक्षी को करारा जवाब दिया था। गीता ने कहा था कि कई खिलाड़ी बबीता का नाम लेकर अपना एजेंडा चमकाने की कोशिश करते हैं। बबीता ने कुश्ती या राजनीति में जो भी हासिल किया है, वे अपनी मेहनत के दम पर किया। उनके लिए पद कोई मायने नहीं रखता।

साक्षी मलिक बबीता फोगाट

आइओए की एसजीएम अनिश्चितकाल के लिए किया गया स्थगित

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय ओलिंपिक संघ (आइओए) की 25 अक्टूबर को होने वाली विशेष आम बैठक (एसजीएम) को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। आइओए के निदेशक जार्ज मैथ्यू ने अध्यक्ष पीटी ऊषा के निर्देश के बाद बैठक को स्थगित करने के बारे में कार्यकारी परिषद और अन्य हितधारकों को सूचित किया।

मैथ्यू ने ईमेल में लिखा, 'आइओए अध्यक्ष के निर्देशानुसार मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आइओए अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई विशेष आम बैठक, जो मूल रूप से 25 अक्टूबर को नई दिल्ली के ओलिंपिक भवन में आयोजित होने वाली थी, को बाद की तिथि के लिए स्थगित कर दिया गया है।'

पिकलबाल टूर्नामेंट इंडिया मास्टर्स आज से, 750 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली, जेएनएन: पिकलबाल टूर्नामेंट इंडिया मास्टर्स का आयोजन नई दिल्ली के डीएलटीए परिसर में 24 अक्टूबर से किया जाएगा जिसमें लगभग 750 पेशेवर और एमेच्योर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इंडिया मास्टर्स पीडब्ल्यूआर700 प्रतियोगिता है और यह पूरी तरह से पिकलबाल विश्व रैंकिंग के अधीन भारत में होने वाला पहला टूर्नामेंट है।

भारत के अरमान भाटिया और आदित्य रुहेला सहित विश्वभर के कई शीर्ष खिलाड़ी इस 42.03 लाख रुपये (50 हजार डालर) इनामी टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट को लेकर विनीत जैन ने कहा, 'इंडिया मास्टर्स पहला पिकलबाल टूर्नामेंट है जिसमें विश्व स्तर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।'

यह होता है पिकलबाल

पिकलबाल एक रैकेट खेल है। इसमें दो (सिंगल्स) या चार खिलाड़ी (डबल्स) एक रैकेट का उपयोग करके एक खोखली प्लास्टिक की गेंद से खेलते हैं। पिकलबाल को बैडमिंटन के आकार के कोर्ट (20 इंच x 44 इंच) पर खेला जाता है। इसकी नेट ऊंचाई किनारे पर 36 और केंद्र में 34 इंच होती है। कोर्ट के प्रत्येक छोर पर सात इंच का क्षेत्र है जिसे नान-वाली जोन (या 'किचन') कहा जाता है, जहां खिलाड़ियों को वाली (हवा में मारा गया शाट) मारने की अनुमति नहीं होती। इसमें केवल सर्विस पर अंक लिए जा सकते हैं।

थिएम ने हार के साथ टेनिस को कहा अलविदा

टेनिस डायरी

वियना, एपी: डोमिनिक थिएम ने अर्स्टे बैंक ओपन के पहले दौर में लुसियानो डार्डेरी से 7-6 (6), 6-2 से हार के साथ अपने पेशेवर टेनिस करियर को अलविदा कहा। यूएस ओपन में 2020 के चैंपियन थिएम ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस टूर्नामेंट के बाद वह टेनिस से संन्यास ले लेंगे। वह कुछ समय से कलाई की चोट से जूझ रहे हैं।

आस्ट्रिया के इस खिलाड़ी ने अपने घरेलू दर्शकों के सामने अच्छी शुरुआत की और पहले सेट में एक समय वह 4-2 से आगे चल रहे थे लेकिन इसका लाभ नहीं उठा पाए। जब वह सेंटर कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो दर्शकों ने तालियों के साथ उनको विदाई दी। थिएम तीन ग्रैंडस्लैम, 2018 और 2019 फ्रेंच ओपन और 2020 आस्ट्रेलियन ओपन में उपविजेता भी रहे थे।

डोमिनिक थिएम ● एएफपी

नडाल को दिए सुनहरे रैकेट की कीमत 2.26 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, जेएनएन: रियाद में हुए सिक्स किंग्स स्लैम का समापन एक शानदार उपहार के साथ हुआ था। तीसरे स्थान के मैच में नोवाक जोकोविक से हारने के बावजूद, स्पेनिश चैंपियन राफेल नडाल को लगभग तीन किलोग्राम सोने का रैकेट दिया गया था, जिसकी कीमत लगभग 2.26 करोड़ रुपये (250,000 यूरो) है। यह असाधारण उपहार सऊदी अरब में टेनिस के राजदूत के रूप में नडाल के महत्व को दर्शाता है। टेनिस इतिहास में सबसे बड़ी पुरस्कार राशि का दावा करने वाले इस टूर्नामेंट में विजेता को 50.37 करोड़ रुपये (60 लाख डालर) का चेक दिया गया, जिससे इसने ग्रैंडस्लैम और एटीपी फाइनल के पुरस्कारों को पीछे छोड़ दिया। पहले दौर में बाहर होने वाले खिलाड़ियों को भी 12.61 करोड़ रुपये (15 लाख डालर) मिले।

सोने के रैकेट के साथ नडाल ● एक्स

****

दैनिक जागरण
सप्तरंग
तकनीक की दुनिया का
गुरुवार, 24 अक्टूबर, 2024

टेक टिप्स

कम रोशनी में भी ऐसे करें वीडियो कालिंग

वाट्सएप पर वीडियो कालिंग करते हुए अक्सर सामने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं दिखता है, तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, पहला पर्याप्त प्रकाश नहीं होने से चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता, दूसरा सामान्य तौर पर स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे की क्वालिटी रियर कैमरे के मुकाबले कम होती है, जिससे फोटो स्पष्ट नहीं होते। वाट्सएप के नए कालिंग फीचर के जरिए अब इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। वाट्सएप ने वीडियो कालिंग के लिए लो-लाइट मोड फीचर शुरू किया है, इससे स्पष्टता बढ़ेगी। साथ ही, जहां कम रोशनी है, वहां भी वीडियो कालिंग कर पाना संभव हो सकेगा। वाट्सएप के नवीनतम अपडेट से आप इस फीचर का लाभ उठा सकते हैं...

- स्मार्टफोन पर वाट्सएप को ओपन करें।
- किसी यूजर के साथ वाट्सएप वीडियो काल शुरू करें।
- वीडियो कालिंग के दौरान इंटरफेस के दाहिने कोने पर बल्ब का एक आइकन दिखेगा।
- लो-लाइट मोड एक्टिव करने के लिए बल्ब आइकन को क्लिक करना होगा।
- सामान्य प्रकाश होने की स्थिति में इसे टर्न-आफ कर सकते हैं।

इन दिनों

एआइ से बदल रही फैशन की दुनिया

अमिता गुप्ता
फैशन डिजाइनर एवं सदस्य, फैशन डिजाइन काउंसिल आफ इंडिया

एआइ के इस जमाने में फैशन इंडस्ट्री भी इसके प्रभाव से बची नहीं है। इसमें बहुआयामी परिवर्तन आ रहा है, प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक सब कुछ बदल रहा है। एआइ ने ग्राहकों के साथ ब्रैंड्स का जुड़ाव एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, जहां ग्राहक की पसंद और संतुष्टि बढ़ रही है। एआइ किस तरह और किस स्तर पर फैशन इंडस्ट्री में बदलाव ला रही है, आइए जानते हैं...

1. डिजाइन एवं क्रिएटिविटी

कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन : एआइ आधारित डिजाइन टूल्स कस्टम फैशन में सहायक हो रहे हैं। इससे ब्रैंड्स एआइ डिजाइन टूल से किसी ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार यानी उसकी शरीर के माप के हिसाब से कपड़ा तैयार कर सकते हैं।

जेनरेटिव डिजाइन : प्रयोग होने वाले फैब्रिक, सस्टेनेबिलिटी और रंग आदि मानकों पर एआइ अल्गोरिदम कई सारे डिजाइन का विकल्प जेनरेट करता है। इससे ब्रैंड्स के लिए अधिक आइडिया पर काम करने का मौका मिलता है।

एआइ एडेड डिजाइन : व्यापक डाटा सेट के माध्यम से ट्रेंड्स, रंग और पैटर्न आदि का एआइ टूल्स से विश्लेषण कर डिजाइनर नए तरह के डिजाइन तैयार कर रहे हैं। कुछ एआइ सिस्टम डिजाइन के लिए नए आइडिया भी दे रहे हैं, जिसमें मानव जैसी रचनात्मकता दिखती है। इससे डिजाइनर को नई प्रेरणा और विकल्प मिल रहे हैं।

2. सप्लाई चेन आप्टिमाइजेशन

प्रभावी उत्पादन : एआइ टूल्स मार्केट डिमांड के आधार पर प्रोडक्शन को बढ़ाने और कम करने के साथ-साथ वेस्ट को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पूर्वानुमान सटीकता से कंपनियां अनावश्यक भंडारण रोकने के साथ-साथ अपने संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल कर सकती हैं।

मैन्युफैक्चरिंग आटोमेशन : कपड़ों को तैयार करने के दौरान एआइ सक्षम रोबोट और मशीनें दोहराव वाले कार्यों को करने में सहायक होती हैं। इसमें फैब्रिक की कटिंग या सिलाई जैसे कार्य शामिल हैं। इससे मानवीय त्रुटियों की आशंका कम रहती है और उत्पादन वृद्धि अधिक रहती है।

3. नए ट्रेंड्स का अनुमान

ग्राहक की प्राथमिकता का पूर्वानुमान : एआइ इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध जानकारियों और खरीदारी के मौजूदा पैटर्न के आधार पर यह विश्लेषण कर सकता है कि आगे क्या होने वाला है। इससे ब्रैंड्स अपने लक्षित बाजार के लिए पहले से डिजाइन कलेक्शन तैयार कर लेते हैं।

मांग का पूर्वानुमान : एआइ स्टाइल, साइज और रंग के आधार पर यह अनुमान लगाने में सक्षम है कि किसकी बिक्री की संभावना अधिक है, इससे अनावश्यक (वेस्ट) प्रोडक्शन को नियंत्रित करने और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

4. सस्टेनेबिलिटी

कचरे में कमी : पर्यावरण अनुकूल पदार्थों या प्रक्रिया से सस्टेनेबल प्रोडक्ट को तैयार करने में सहायक एआइ टूल्स फैब्रिक से होने वाले वेस्टेज को कम करता है।

सर्कुलर फैशन : कपड़ों से तैयार उत्पाद कितने समय चलेंगे, इसका अनुमान लगाकर एआइ से कंपनियां रिसाइकिलिंग प्रोग्राम तैयार कर सकती हैं। एआइ आधारित प्लेटफार्म से इसे री-सेल कर कपड़ों का जीवन बढ़ा सकती है।

5. ग्राहक अनुभव और वैयक्तिकरण

वैयक्तिक सुझाव : ई-कामर्स साइट एआइ अल्गोरिदम का प्रयोग कर हर ग्राहक की पसंद, ब्राउजिंग हिस्ट्री या पुरानी खरीदारी के आधार पर उसे सुझाव आफर करती है। वैयक्तिकरण सेल्स और रिटेंशन दर में वृद्धि करता है।

चैटबाट और वर्चुअल असिस्टेंट : एआइ चैटबाट ग्राहकों को उनके प्रश्नों का जवाब देने के साथ-साथ स्टाइल सुझाने, ई-कामर्स वेबसाइट पर प्रोडक्ट खोजने और खरीदारी को आसान बनाने में मदद करते हैं।

वर्चुअल ट्राइ आन : एआइ वर्चुअल फिटिंग रूम ग्राहकों को डेस्कटाप/टेबलेट पर एआर (आग्युमेंटेड रियलिटी) के माध्यम से कपड़ों को ट्राइ करने की सुविधा देता है। इससे कपड़ों को वापस करने की दर कम होती है और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ती है।

6. थ्रीडी प्रिंटिंग और एआइ

आन-डिमांड मैनुफैक्चरिंग : थ्रीडी प्रिंटिंग के साथ एआइ का गठजोड़ मांग आधारित उत्पादन को बढ़ावा देता है। इससे डिजाइनर बड़ी इन्वेंटरी तैयार कर सकते हैं।

7. मार्केटिंग और इंटरनेट मीडिया

कंटेंट : एआइ आधारित टूल्स की फैशन कंटेंट तैयार करने में मदद ली जा सकती है, जैसे इंटरनेट मीडिया पोस्ट, ब्लाग आर्टिकल या प्रोडक्ट का विवरण लिखा जा सकता है। इससे ब्रैंड्स का समय बचता है और ग्राहकों के साथ और अधिक रचनात्मक जुड़ाव होता है।

ग्राहक सेंटीमेंट विश्लेषण : इंटरनेट मीडिया पर होने वाले रिव्यूज और कमेंट का विश्लेषण कर एआइ यह पता लगा सकता है कि किस उत्पाद के बारे में लोगों की राय क्या है। इससे प्रोडक्ट में अपेक्षित सुधार किया जा सकता है।

इन्फ्लुएंसर की पहचान : एआइ इंटरनेट मीडिया डाटा का विश्लेषण कर सभी संभावित इन्फ्लुएंसर और एंबेस्डर को चिह्नित करने में मदद करता है, जो ब्रैंड्स के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इससे मार्केटिंग अधिक सटीक और प्रभावी हो गई है।

8. सभी के लिए फैशन

अनुकूल फैशन : एआइ एडाप्टिव फैशन की सुविधा देता है, जिससे दिव्यांगों के लिए भी कपड़ों को तैयार किया जा सकता है।

शरीर और आकार की माप : एआइ बाडी स्कैनिंग और साइजिंग टेक्नोलाजी अलग-अलग शरीर के हिसाब से एक बड़ी रेंज तैयार करने में मदद करती है। वर्चुअल ट्राइ आन और एआइ सुझाव ग्राहक के लिए सही माप तैयार करता है।

कुछ चिंताएं और चुनौतियां भी

मानव रचनात्मकता बनाम एआइ : डिजाइन में एआइ मदद तो कर सकता है पर यह कैसे पर्सनल टच और कलात्मकता को उभार पाएगा, जिसके लिए फैशन जाना जाता है।

नौकरियों पर खतरा : आटोमेशन और एआइ की दखल से, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में, नौकरियों के जाने का खतरा बढ़ गया है।

नैतिकता का सवाल : वैयक्तिक सुझाव के लिए एआइ आधारित एप्लीकेशन में प्रयोग होने वाले निजी डाटा से निजता का सवाल गंभीर हो रहा है।

फोटो : प्रीपिक

साइबर सुरक्षा

त्योहारों की खरीदारी पर स्कैमर की भी नजर

आजकल त्योहारों के चलते लोग खूब आनलाइन शापिंग कर रहे हैं। आफर खत्म हो जाने या प्रोडक्ट के आउट आफ सेल हो जाने की जल्दबाजी में छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ जाती है। प्रोडक्ट के नाम पर धोखाधड़ी के अलावा जो सबसे गंभीर बात है, वह है आनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भुगतान में सतर्कता। आनलाइन पेमेंट के दौरान डेबिट कार्ड के बजाय क्रेडिट कार्ड का विकल्प बेहतर हो सकता है, इससे बैंक अकाउंट में सेंध के जोखिम से बचे रहेंगे।

कैसे हो रही है साइबर ठगी : यूपीआइ, क्यूआर कोड, ओटीपी स्कैम से लेकर डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं अब छोटे कस्बों और गांवों तक होने लगी हैं। बैंक के नाम से फर्जी मेल भेजकर स्कैमर नेट बैंकिंग फ्राड को अंजाम देते हैं। बूढ़े-वृद्धजनों के साथ बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने के मामले आए दिन चर्चा में रहते हैं।

नेट बैंकिंग फ्राड से बचाएंगी ये बातें

जागरूक बनें : डिजिटल धोखाधड़ी से बचने की पहली शर्त है जागरूकता। लोगों के अनुभव से भी सीख सकते हैं। इससे साइबर ठगी के जाल में खुद फंसने से बचेंगे, साथ ही दूसरों को बचाने में मददगार होंगे।

धोखाधड़ी को तुरंत रिपोर्ट करें: आनलाइन ठगी का शिकार होते हैं, तो घबराने की बजाय शांत होकर आगे फैसला करें। इसे साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ पर रिपोर्ट करें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन (1930) पर भी संपर्क कर सकते हैं।

वैध कस्टमर केयर से ही संपर्क करें: बैंक के वैध कम्युनिकेशन चैनल और आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर पर ही बात करें। ठगी होने की दशा में तुरंत कार्ड को ब्लाक या अकाउंट को फ्रीज कराएं।

जरूरी जानकारी एकत्र करें: खरीदारी और भुगतान से संबंधित जानकारियों और दस्तावेजों को एकत्र करें। संबंधित स्क्रीनशाट, ट्रांजैक्शन आइडी जैसी जानकारियां फ्राड के प्रभावी समाधान में कारगर साबित होंगी।

आनलाइन सेफ्टी का रहे ध्यान: कुछ आधारभूत बातों जैसे यूनिक और मजबूत पासवर्ड, पासवर्ड को अपडेट करने, टू-फैक्टर आथेंटिकेशन, सिक्योरिटी साफ्टवेयर का ध्यान रखना चाहिए। पेमेंट आप्शन को टोकनाइज करेंगे, तो पेमेंट सुरक्षित होने की प्रबल संभावना रहेगी।

ब्रह्मानंद मिश्र

कैसे पहचानें सही और वैध एप

टेक अपडेट

एप्स की मदद से बैंकिंग, शापिंग जैसे बहुत सारे कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दुनियाभर में हर साल करोड़ों एप्स डाउनलोड किए जाते हैं, लेकिन अगर आप गलती से फेक एप को डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपका पर्सनल डाटा खतरे में पड़ सकता है, फोन खराब हो सकता है या फिर आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। गूगल प्ले स्टोर पर फेक एप्स की कमी नहीं है, हालांकि कंपनी समय-समय पर इन एप्स को हटाती रहती है। यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन-सा एप सही और वैध है और कौन-सा नकली। यहां कुछ आसान तरीके दिए गए हैं, जिनसे आप सही एप की पहचान कर सकते हैं....

ध्यान से देखें गूगल प्ले स्टोर सर्च रिजल्ट: जब आप किसी एप को प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं, तो मिलते-जुलते बहुत सारे रिजल्ट दिखते हैं। अगर एक ही नाम और आइकन वाले कई एप्स दिखाई दें, तो इसमें कुछ फेक हो सकते हैं। नकली एप भी असली एप्स का नाम, आइकन और डिजाइन कापी कर लेते हैं ताकि लोग उसे इंस्टाल कर लें। इसलिए, सर्च रिजल्ट ध्यान से देखना चाहिए। असली एप का नाम यूनिक होता है और आइकन की क्वालिटी भी बेहतर होती है।

एप और डेवलपर का नाम करें चेक: एप को इंस्टाल करने से पहले डेवलपर का नाम जरूर चेक करें। वैध एप्स के डेवलपर्स का नाम जाना-पहचाना या प्रतिष्ठित कंपनियों का होता है, जैसे कि गूगल, मेटा या अन्य बड़ी टेक कंपनियां। अगर डेवलपर का नाम अजीब है या उसकी स्पेलिंग में कोई गलती है, तो यह एप नकली हो सकता है। गूगल प्ले स्टोर पर डेवलपर के नाम पर क्लिक करके यह भी देख सकते हैं कि उस डेवलपर के नाम और कौन-कौन से एप्स हैं। अगर वही डेवलपर बहुत सारे अच्छे एप्स बना चुका है, तो इसका मतलब है कि वह डेवलपर भरोसेमंद है।

डिस्क्रिप्शन और स्क्रीनशाट को देखें : प्ले स्टोर पर एप डिस्क्रिप्शन और स्क्रीनशाट को ध्यान से देखें और पढ़ें। असली एप की डिस्क्रिप्शन डि... की गलती नहीं... भी हाइ-क्वालि... इंटरफेस को दि... सारी गलतियां... लगते हैं, तो यह...

डाउनलोड, रि... है, तो डाउनलो... होगी। हालांकि... होते हैं, जिसे... है। आमतौर प... संख्या काफी... होते हैं। नकली...

देखने को मिलेंगे। रिलीज डेट भी चेक जरूरी है। असली एप्स को प्ले स्टोर पर लंबे से पब्लिश किया गया होता है, जबकि नकली ाल ही में लांच किए गए होते हैं।

द्वारा मांगी गई परमिशन चेक करें: असली एप्स वही परमिशन मांगते हैं जो उनके काम के नरूरी होती है। उदाहरण के लिए एक फोटो ा एप को फोन की गैलरी की परमिशन , लेकिन वह लोकेशन या माइक्रोफोन एक्सेस ा है, तो संदिग्ध हो सकता है। अगर कोई एप यक परमिशन मांगता है, तो एप नकली है ापका डाटा चोरी कर सकता है।

पर सर्च करें: अगर आप किसी एप को लेकर संदेह में हैं, तो उस एप की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि वह असली है या नहीं। अगर एप की वेबसाइट पर नहीं पहुंच पाते हैं या आपको उसका सही लिंक नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि वह एप नकली हो।

इंस्टाल करने से पहले स्कैन करें : अगर आप किसी एप की सुरक्षा को लेकर संदेह में हैं, तो बेहतर होगा कि उसे इंस्टाल करने से पहले स्कैन कर लें। आप इसके लिए गूगल प्ले प्रोटेक्ट या अन्य मोबाइल सिक्योरिटी एप्स जैसे मालवेयरबाइट्स, क्विकहील आदि का उपयोग कर सकते हैं। इससे जान सकेंगे कि एप सुरक्षित है या नहीं।

संतोष आनंद

एप नकली हो तो क्या करें?

अगर आपको पता चलता है कि कोई एप नकली है, तो उसे बिल्कुल भी इंस्टाल न करें। इसके अलावा, गूगल प्ले स्टोर पर उस एप को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए एप के पेज पर जाएं, फिर ऊपर दायीं ओर दिए गए तीन डाट्स पर क्लिक करें और 'फ्लैग एज इनएप्रोपिएट' का विकल्प चुनें। इसके बाद कारण बताएं, जैसे कि एप नकली है या यह किसी अन्य एप की नकल है। इस जानकारी के आधार पर गूगल उस एप को जांचेगा और जरूरी कदम उठाएगा। एप्स कार्य को आसान बनाते हैं, लेकिन अगर गलती से कोई नकली एप डाउनलोड कर लेते हैं, तो यह आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। नकली एप्स से बचने के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको संदेह हो, तो बेहतर होगा कि एप इंस्टाल करने से पहले पूरी तरह जांच कर लें।

आज का भविष्यफल - 24 अक्टूबर, 2024 गुरुवार

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति :
कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी
आज का राहुकाल :
दोपहर 01 बजकर के 30 मिनट से 03 बजे तक।
आज का दिशा शूल : दक्षिण
आज का पर्व एवं त्योहार :
अहोई अष्टमी

कल 25 अक्टूबर, 2024 का पंचांग

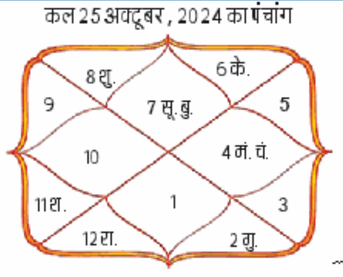

कल का दिशाशूल : पश्चिम
विक्रम संवत 2081 शके 1946 दक्षिणायण, दक्षिणगोल, शरद ऋतु कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की नवमी 27 घंटे 24 मिनट तक, तत्पश्चात दशमी पुष्य नक्षत्र 07 घंटे 40 मिनट तक, तत्पश्चात अश्लेषा नक्षत्र शुभ योग 29 घंटे 26 मिनट तक, तत्पश्चात शुक्ल योग कर्क में चंद्रमा।

मेष : पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। दांपत्य जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।

वृष : आर्थिक प्रयास फलीभूत होगा। रचनात्मक कार्यों में आशातीत सफलता मिलेगी।

मिथुन : उपहार, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। रिश्तों में निकटता आएगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।

कर्क : पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

सिंह : उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सुख बढ़ेगा।

कन्या : आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी।

तुला : व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।

वृश्चिक : शासनसत्ता का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी लेकिन उदर विकार हो सकता है।

धनु : यात्रा देशाटन में अपनी वस्तुओं की सुरक्षा की ध्यान रखें। किसी मूल्यवान वस्तु के खोने की आशंका है।

मकर : ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा। अधिकारी का सहयोग रहेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।

कुंभ : स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अधीनस्थ कर्मचारी या संबंधित अधिकारी से तनाव मिल सकता है।

मीन : व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। पारिवारिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शिक्षा में चल रहा प्रयास सार्थक होगा।

वर्ग पहेली - 2789

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं
1 सजावट, आभूषण (4)। 3 फिसलना, जल्दी-जल्दी चलना (4)। 5 गुरुमंत्र, शैक्षणिक उपाधि, शिक्षा- ... (2)। 6 नष्ट हो जाने वाला (4)। 8 बदला चुकाने वाला (5)। 9 जाना हुआ (3)। 11 नहीं मानना, उल्लंघन करना (3)। 14 हजारों छेद का एक पात्र, एक तीर्थ स्थल (5)। 16 एक प्राचीन ऋषि (4)। 18 छाया, परछाई (2)। 19 अंधकार हरने वाला (4)। 20 ऊपरी दिखावा, बनने या बनाने का भाव (4)।

ऊपर से नीचे
1 आशीर्वाद देना (4)। 2 रसायन शास्त्र का ज्ञाता (5)। 3 नगरवासियों की रक्षा करने वाला (4)। 4 देशवासी (4)। 7 संदेह, एक संघत (2)। 8 पाताल के सातवें भाग का नाम (3)। 10 भानुमति का ... (3)। 12 असफल, अनुत्तीर्ण (5)। 13 निर्णय, मत (2)। 14 समाप्त किया हुआ (4)। 15 लगातार वर्षा का होना, जल की सतत् वृष्टि (4)। 17 शरारती, चंचल (4)।

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

फ	ल	दा	य	क		स	र	ल	ता
ट				ल			ज		ली
क	प	टी		श	व		त		ब
ना					न				जा
		अ	न	प	च		पो	ल	ना
सं	म	ग्र		सं	र	स	री		
मा				र					औ
नु		श		ना	रा		वि	रा	म
पा		ह			जें				र
त	ह	री	र		दे	वी	क	र	ण

जागरण सुडोकू - 2789

7	1		9		4		8	5
9				3				6
				7	8			
		3	8			7		4
5	7			2	6	1		3
	2		3				6	
			7	4				2
2					3			9
8	4		5	1		6	3	

कल का हल

4	5	6	9	8	1	2	7	3
8	3	1	2	7	4	6	5	9
2	9	7	3	6	5	8	4	1
7	8	3	4	2	6	9	1	5
1	4	9	5	3	8	7	6	2
5	6	2	7	1	9	3	8	4
9	7	5	6	4	3	1	2	8
3	2	8	1	5	7	4	9	6
6	1	4	8	9	2	5	3	7

राष्ट्रीय फलक

छत्तीसगढ़ में मुर्गीखाना परिसर में बना श्रीप्रसाद अमानक निकला

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव

छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम राका में मजहर खान के मुर्गीखाना परिसर में फैक्ट्री खोलकर 'श्रीप्रसाद' नाम से बनाया जाने वाला इलायची दाना गुणवत्ता परीक्षण में अमानक निकला। यहीं से बने प्रसाद की मां बम्लेश्वरी मंदिर परिसर की दुकानों को आपूर्ति की जाती थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रसाद बनाने में उपयोग किए पदार्थ घुलनशील नहीं पाए गए हैं। पदार्थों की मात्रा भी तय मानक से अधिक निकली है। अब फैक्ट्री संचालक मजहर खान पर नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बता दें कि 26 सितंबर को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने फैक्ट्री में दबिश दी थी। वहां से श्रीप्रसाद नामक इलायची दाने को गुणवत्ता परीक्षण के लिए जब्त किया गया था। विभाग के पदेन उप संचालक सीएमएचओ डा. एनआर नवरतन ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान भी इलायची दाने के पैकेट पर पैकेजिंग लेबलिंग रेग्युलेशन का उल्लंघन पाया गया था।

फैक्ट्री में तैयार प्रसाद का पैकेट। नईदुनिया

लीक से हटकर कार्य करने वाले ही होते हैं विशिष्ट : योगी

जागरण संवाददाता, लखनऊ

मुख्यमंत्री ने युग तुलसी पं. रामकिंकर उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष पर भावांजलि की अर्पित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युग तुलसी के नाम से विख्यात मानस मर्मज्ञ पद्मभूषण पं. रामकिंकर उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष पर बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित भावांजलि कार्यक्रम में कहा कि यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि हम ऐसे महापुरुष के शताब्दी समारोह से जुड़े हैं, जिनका जीवन सनातन धर्म और प्रभु श्रीराम के आदर्शों पर आधारित था। युग तुलसी पं. रामकिंकर का जीवन श्रीराम और तुलसी साहित्य के प्रति समर्पित था। उनकी व्याख्याएं और चिंतन सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत बना रहेगा। उन्होंने कहा कि लीक से हटकर कार्य करने वाले विशिष्ट होते हैं।

पं. रामकिंकर उपाध्याय की श्रीराम कथा की विशिष्ट शैली का उल्लेख करते हुए योगी ने कहा कि उन्होंने रामकथा को नई दिशा दी। उनकी कथाएं न केवल आम जनमानस, बल्कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद जैसे गणमान्य लोगों को भी प्रभावित करती थीं। लगभग छह दशकों तक उन्होंने मानस के माध्यम से सनातन धर्म की सेवा की। रामजन्मभूमि आंदोलन के दौरान पं. रामकिंकर उपाध्याय की कथाओं ने ठीक उसी प्रकार जनजागरण किया, जैसे संत तुलसीदास ने विदेशी आक्रांताओं के समय किया था। उन्होंने तब के बादशाह का दरबारी बनने से इन्कार करते हुए प्रभु श्रीराम को भारत का एकमात्र राजा बताया था। उन्होंने गांव-गांव में रामलीलाओं का आयोजन शुरू करवाया और वह परंपरा आज भी बिना सरकारी सहायता के चल रही है, जिससे सनातन धर्म के मूल्य और अधिक सुदृढ़ हो रहे हैं। पं. रामकिंकर उपाध्याय का जन्म शताब्दी वर्ष एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह वही वर्ष है, जब 500 वर्षों के बाद श्रीरामलला अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। यह सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव का अद्वितीय उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने इस महान संयोग को रामकिंकर जी की श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक बताया। कहा कि उनकी स्मृतियों को स्मृति ग्रंथ के रूप में संजोकर लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि उनका जीवन व कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी बन सके।

मुख्यमंत्री ने आयोजक किशोर टंडन के बारे में कहा कि इनके नाना बिशन चंद्र सेठ गोरक्षपीठ के परम भक्त थे। वह प्रखर हिंदुनिष्ठ और अपने समय के अद्भुत व्याख्याकार थे, जो अपने तथ्यों के आगे कभी किसी के सामने नहीं झुके। इनका परिवार आज भी उसी निष्ठा के साथ धर्मपरायण होकर कार्य कर रहा है।

लखनऊ में बुधवार को मानस मर्मज्ञ पंडित रामकिंकर उपाध्याय के जन्मशताब्दी वर्ष पर आयोजित भावांजलि कार्यक्रम को संबोधित करते योगी आदित्यनाथ। सौ. सूचना विभाग

पर्यटन में अजरबैजान के बाकू से आगे निकला शिलांग

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय यात्रियों ने 2025 में मेघायल की राजधानी शिलांग को घूमने-फिरने के लिए अपने सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में चुना है। यह शहर पर्यटन के मामले में अजरबैजान की राजधानी बाकू से आगे निकल गया है। वैश्विक यात्रा एप स्काईस्कैनर की वार्षिक 'ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट' में यह बात सामने आई है। बुधवार को जारी रिपोर्ट में शिलांग एकमात्र भारतीय शहर है। भारतीय यात्रियों की अगले वर्ष की यात्रा को लेकर रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 2025 में 66 प्रतिशत भारतीयों की ज्यादा घूमने-फिरने की योजना है। रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व का स्काटलैंड कहे जाने वाला शिलांग उन पसंदीदा गंतव्यों की सूची में पहले स्थान पर है, जो अपने विविध अनुभवों और रोमांच का एहसास कराता है। अजरबैजान का बाकू और मलेशिया का लंगकावी सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

गुरुवार 24 अक्टूबर, 2024

14

www.jagran.com

अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हुआ संयुक्त राष्ट्र का गठन

1945 में आज ही के दिन स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अनुमोदन मिलने के बाद औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इस चार्टर पर 26 जून को 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना था।

UNITED NATIONS

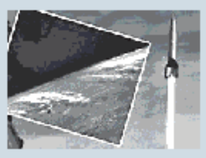

जर्मन वी-2 राकेट ने अंतरिक्ष से खींची पृथ्वी की पहली तस्वीर

1946 में आज ही अमेरिका द्वारा लांच जर्मन वी-2 राकेट ने अंतरिक्ष से पृथ्वी की पहली तस्वीर ली थी। राकेट अपने साथ 35 मिलीमीटर का मोशन पिक्चर कैमरा ले गया था। राकेट 105 किमी ऊपर कार्मन रेखा (पृथ्वी के वायुमंडल व अंतरिक्ष के बीच की सीमा) तक पहुंचा था।

आजाद हिंद सरकार की कैबिनेट में सदस्य थीं लक्ष्मी

स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सहगल का जन्म 1914 में आज ही के दिन चेन्नई में हुआ था। बतौर डाक्टर कुछ समय तक काम करने के बाद सिंगापुर चली गईं। वहां सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित होकर आजाद हिंद फौज (आइएनए) से जुड़ गईं। 1943 में आइएनए की 1200 महिलाओं वाली झांसी की रानी रेजिमेंट की कमांडिंग आफिसर नियुक्त हुईं और 1944 में बर्मा मोर्चे पर अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध लड़ा। बाद में वह अस्थाई आजाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली महिला मंत्री बनीं।

कृत्रिम गर्भाधान से दुर्लभ गोडावण हुआ पैदा

उपलब्धि ▶ पहला चूजा पैदा कर जैसलमेर के सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर ने रचा इतिहास

जलवायु परिवर्तन और अन्य बदलाव के प्रति संवेदनशील होता है गोडावण

जागरण संवाददाता, जयपुर

कृत्रिम गर्भाधान (आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन) के जरिए दुनिया के दुर्लभ पक्षियों में शामिल राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) का पहला चूजा पैदा कर जैसलमेर के सुदासरी गोडावण ब्रीडिंग सेंटर ने बड़ी सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि लुप्त हो रही इस दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण के लिए अहम कदम है। दुनिया का यह पहला मामला है, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान से गोडावण का चूजा पैदा हुआ है।

कृत्रिम गर्भाधान करने का सोच अबू धाबी से आया। पिछले वर्ष वहां इंटरनेशनल फंड फार हुबारा कंजर्वेशन फाउंडेशन में तलोर पक्षी पर इसी तरह का परीक्षण किया गया था। भारत के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया के विज्ञानी वहां गए थे। इसके बाद गोडावण पर परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। जैसलमेर के जिला वन अधिकारी आशीष व्यास ने दावा किया कि गोडावण को कृत्रिम गर्भाधान से प्रजनन का दुनिया में यह पहला मामला है। अब इसके स्पर्म को सुरक्षित रखकर बैंक बनाने और इनकी संख्या बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि नर गोडावण को कृत्रिम मेटिंग के लिए आठ महीने तक प्रशिक्षण दिया गया। 20 सितंबर को टोनी नामक मादा गोडावण को उसके स्पर्म से कृत्रिम गर्भाधान कराया गया। 24 सितंबर को टोनी ने अंडा दिया। 16 अक्टूबर को चूजा बाहर निकला। चूजा स्वस्थ है। बता दें कि जैसलमेर में अभी 173 गोडावण हैं, जिनमें 128 खुले में घूम रहे हैं, 45 ब्रीडिंग सेंटर में है। जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में इनके प्रजनन की अनुकूल स्थितियां हैं।

राजस्थान में दुर्लभ गोडावण हुआ पैदा। इंटरनेट मीडिया

गोडावण इसलिए है महत्वपूर्ण

गोडावण की इ, झींगुर और अन्य छोटे जीवों को खाता है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन में मदद मिलती है। फसलों की भी सुरक्षा होती है। यह प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होता है और इसे संकेतक समझा जाता है। उड़ने वाले पक्षियों में यह सबसे अधिक भारी पक्षियों में एक है। यह अत्यंत शर्मिला होता है और सघन घास में रहना इसका स्वभाव है। गोडावण को वर्ष 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। यह शांत पक्षी है, लेकिन डराया जाए तो हुक जैसी ध्वनि निकालता है। इसीलिए उत्तरी भारत के कुछ भागों में इसे हुकना भी कहा जाता है।

पेयजल में लंबे समय तक आर्सेनिक की मौजूदगी से हृदय रोग का खतरा

नई दिल्ली, आइएएनएस : पीने के पानी में लंबे समय तक आर्सेनिक की मौजूदगी से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। यह जानकारी बुधवार को जारी एक शोध रिपोर्ट में सामने आई है। इसमें कहा गया है कि तय सीमा से नीचे स्तर होने के बाद भी इसका खतरा बना रहता है।

यह अध्ययन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की ओर से किया गया। रिपोर्ट जर्नल एनवायर्नमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव में प्रकाशित किया गया है। यह वर्तमान नियामक सीमा (10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर) से कम सांद्रता पर एक्सपोजर-प्रतिक्रिया संबंधों का वर्णन करने वाला पहला शोध है। यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि पानी में आर्सेनिक का लंबे समय तक संपर्क इस्केमिक हृदय रोग के विकास में योगदान देता है। यह हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली कोरोनरी धमनियों के संकुचित होने के कारण होने वाली समस्या है।

डायनासोर की होगी नीलामी

फ्रांस की राजधानी पेरिस में डैपियर एन यवेलिन्स महल में एक व्यक्ति 69 फीट (21 मीटर) लंबे डायनासोर को देख रहा है, जो अगले 16 नवंबर को नीलाम किया जाएगा। इससे पहले पेरिस में 150 मिलियन वर्ष पुराने एक डायनासोर के कंकाल को नीलाम किया गया था। एपी

इधर-उधर की

रेगिस्तान में फंसी महिला ने उबर के जरिये बुलाया ऊंट

यूजर ने महिला को दी नंबर प्लेट जांचने की सलाह। इंटरनेट मीडिया

दुबई, एजेंसी: उबर से अब तक आप कार, बाइक या आटो ही बुक करते होंगे किंतु दुबई में एक महिला ने उबर के जरिये ऊंट बुला लिया। दुबई के रेगिस्तान में कार खराब होने से दो महिलाएं फंस गई थीं। तभी इनमें से एक ने उबर ऐप खोला। ऐप में बुक करने के बाद एक आदमी वहां ऊंट के साथ पहुंच गया। उसने खुद को उबर ऊंट चालक बताया। उसने कहा, रेगिस्तान में फंसे यात्रियों की सहायता करने में वह माहिर है। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

77% भारतीय बच्चों के आहार में विविधता का अभाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : बच्चों के स्वस्थ बनाने के लिए उनके आहार में विविधता का होना जरूरी है। आहार में विविधता होने से बच्चों का समुचित विकास होता है। देश के बच्चों के आहार को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने नई जानकारी दी है। इसके अनुसार देश में 6-23 महीने की आयु के लगभग 77 प्रतिशत बच्चों के आहार में डब्ल्यूएचओ द्वारा सुझाई गई विविधता का अभाव पाया गया है, जिसमें मध्य क्षेत्र में न्यूनतम आहार विफलता का प्रचलन सबसे अधिक पाया गया है।

अध्ययन के अनुसार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने बच्चों के आहार में अपर्याप्त विविधता के उच्चतम स्तर की सूचना दी। इन राज्यों में 80 प्रतिशत से ऊपर विविधता का अभाव पाया गया। वहीं सिक्किम और मेघालय केवल दो ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने 50 प्रतिशत से कम न्यूनतम आहार विफलता के प्रचलन की सूचना दी। डब्ल्यूएचओ ने एक बच्चे के आहार की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम आहार विविधता (एमडीडी) स्कोर का उपयोग करने का सुझाव दिया है, इसे विविधतापूर्ण माना जाता है। इसमें स्तनदूध, अंडे, फलियां, मेवे और फल और सब्जियां सहित पांच या अधिक खाद्य समूह शामिल हैं।

प्रतीकात्मक

- 6-23 महीने की आयु के लगभग 77 प्रतिशत बच्चों के आहार में नहीं मिलती विविधता : डब्ल्यूएचओ
- उप्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने बच्चों के आहार में अपर्याप्त विविधता की सूचना दी

राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 (एनएफएचएस-5) के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सहित अन्य शोधकर्ताओं ने पाया कि देश में न्यूनतम आहार विविधता विफलता की समग्र दर 87.4 प्रतिशत से कम हो गई है, जिसकी गणना 2005-06 (एनएफएचएस-3) के आंकड़ों का उपयोग कर की गई थी। लेखकों ने नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया में प्रकाशित अध्ययन में लिखा है कि हमारे अध्ययन से पता चलता है कि देश में न्यूनतम आहार विविधता विफलता का प्रचलन उच्च (75 प्रतिशत से ऊपर) बना हुआ है। टीम ने 2019-21 के आंकड़ों की तुलना 2005-06 के आंकड़ों से की और प्रोटीन और विटामिन जैसे विभिन्न खाद्य समूहों में बच्चों की आहार संबंधी आदतों को भी देखा। इसमें अंडों की खपत में ''प्रभावशाली'' वृद्धि दर्ज की गई, जो एनएफएचएस-3 में लगभग 5 प्रतिशत से बढ़कर एनएफएचएस-5 में 17 प्रतिशत से अधिक हो गई, जबकि फलियों और मेवों की खपत 2005-06 के दौरान लगभग 14 प्रतिशत से बढ़कर 2019-21 के दौरान 17 प्रतिशत से अधिक हो गई। शोध लेखकों ने लिखा कि विटामिन ए से भरपूर फलों और सब्जियों की खपत में 7.3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई, जबकि फलों और सब्जियों की खपत में इसी अवधि में 13 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। मांसाहारी खाद्य पदार्थों की खपत में 4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। हालांकि, स्तनपान का दूध और डेयरी उत्पादों की खपत एनएफएचएस-3 में 87 प्रतिशत से घटकर एनएफएचएस-5 में 85 प्रतिशत और 54 प्रतिशत से घटकर 52 प्रतिशत हो गई। लेखकों ने यह भी पाया कि अशिक्षित और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली माताओं के बच्चे, जिनका मास मीडिया से कोई संपर्क नहीं है, जो पहले पैदा हुए हैं और आंगनवाड़ी या एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) केंद्रों पर परामर्श और स्वास्थ्य जांच के संपर्क में नहीं हैं, उनके विविधता में कमी वाले आहार लेने की संभावना अधिक है। एनीमिया से पीड़ित बच्चे और कम वजन वाले बच्चे भी विविधता रहित आहार लेने की अधिक संभावना रखते हैं।

कैंसर कोशिकाओं में वसा की पहुंच रोकना होगा बेहतर इलाज

अनुसंधान

वैन एंडेल इंस्टीट्यूट के विज्ञानियों को एक अध्ययन में पता चला है कि कैंसर कोशिकाओं की फैट (वसा) तक पहुंच को प्रतिबंधित करने से कुछ कैंसर उपचारों की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। यह शोध सेल केमिकल बायोलाजी में प्रकाशित किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर आहार में कुछ परिवर्तन किया जाए तो कैंसर के उपचार को और प्रभावी बना सकते हैं।

वैन एंडेल इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता इवान लियन ने कहा कि हम कैंसर के उपचार को अधिक प्रभावी बनाने के तरीकों को ढूढने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह समझना था कि कैंसर कोशिकाएं कैसे व्यवहार करती हैं और उनकी सुरक्षा को तोड़ने के तरीकों की पहचान करनी थी। निष्कर्ष में सामने आया है कि आहार में बदलाव कर बेहतर लाभ लिया जा सकता है। कैंसर को लेकर शोध में रेडिएशन से लेकर खाने के तरीके में बदलाव पर पूरी दुनिया में अध्ययन हो रहा है। कोशिकाओं को बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए फैट महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। कैंसर कोशिकाएं सामान्य सेलुलर प्रक्रियाओं को हाईजैक कर लेती हैं और फैट जैसे संसाधनों को चुरा लेती हैं, जो फिर बीमार कोशिकाओं के बढ़ने और फैलने के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है। लियन ने कहा कि निष्कर्ष आशाजनक हैं। उनकी टीम यह भी जांच कर रही है कि क्या फेरोप्टोसिस इंड्यूसर्स को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आहार के माध्यम से फैट के प्रकार और मात्रा में हेरफेर किया जा सकता है। लियन ने कहा कि आहार एक ऐसी चीज है जिसमें बदलाव अपेक्षाकृत आसान है। (एएनआइ)

स्क्रीन शाट

चेहरे पर टिशू पेपर लगा राज कपूर से मिलीं जीनत

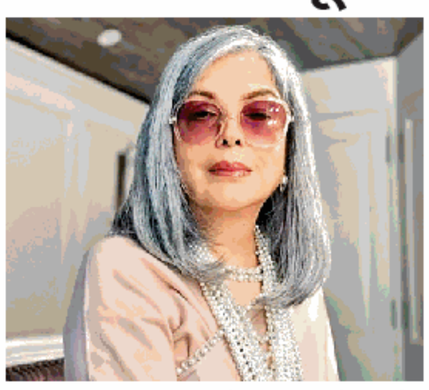

फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत ने निभाई थी रूपा की भूमिका। फाइल

साल 1978 में प्रदर्शित शशि कपूर अभिनीत फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में अभिनेत्री जीनत अमान ने ग्रामीण लड़की की भूमिका निभाई थी। जबकि तब उनकी छवि एक माडर्न और ग्लैमरस अभिनेत्री की हुआ करती थी। उन्होंने बुधवार को इंस्टाग्राम के माध्यम से साझा किया कि मार्डन छवि के बावजूद वह कैसे चेहरे पर टिशू पेपर लगाकर राज कपूर के पास यह फिल्म मांगने पहुंची थीं। उन्होंने बताया कि 1976 के आसपास फिल्म वकील बाबू की शूटिंग के दौरान राज कपूर अक्सर इस क्रांतिकारी फिल्म की कहानी पर चर्चा करते थे। हालांकि उनकी बातों से जीनत के कभी यह संकेत नहीं मिला कि राज कपूर उस फिल्म में उन्हें कास्ट करने पर विचार कर रहे हैं। जीनत ने स्वयं पहल करने का निर्णय लिया। एक शाम राज कपूर आरके स्टूडियो में बैठे थे। तब जीनत ने काम जल्दी खत्म किया। फिल्म की नायिका रूपा की वेशभूषा में तैयार होने के लिए उन्होंने 30 मिनट में घाघरा चोली पहनी, बालों को बांधा और फिर चेहरे पर टिशू पेपर को गोंद से चिपकाया, ताकि उनका चेहरा दागदार दिखे। इस वेशभूषा में राज कपूर के सामने पहुंची और उन्हें लुक दिखाया। यह देखकर वह बहुत हंसे और प्रभावित भी हुए। उन्होंने पत्नी कृष्णा कपूर से फोन करके मुट्ठी भर सोने की गिन्नियां मंगाई और उन्हें साइनिंग अमाउंट के तौर पर जीनत को दे दिया।

...तो इस कारण अन्नू कपूर ने नहीं लिया अमेरिकी पासपोर्ट

बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता अन्नू कपूर अपनी बेबाकी के लिए अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। ड्रीम गर्ल 2 अभिनेता अन्नू ने अमेरिकी निवासी अनुपमा पटेल से विवाह करने और अमेरिका में ही तीन बच्चों के जन्म के बावजूद कभी भी अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन नहीं करने को लेकर एक साक्षात्कार में बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें कभी भी ग्रीन कार्ड की जरूरत महसूस नहीं हुई। अन्नू ने कहा कि मैं किसी दूसरे देश का पासपोर्ट लेने से पहले मर जाऊंगा। मैं देश के प्रति वफादार हूं। अन्नू के लिए, भारत को सही मायने में समझने का मतलब है सुर्खियों और वायरल ट्रेंड से परे जाना। उन्होंने आगे बताया कि भारत के साथ उनका गहरा जुड़ाव इसके विविध लोगों से मिलने और उनकी भाषा, संस्कृति और मानसिकता से खुद को जोड़ने से आता है। उन्होंने कहा कि मैंने छप्पन घाट का पानी पिया है। उल्लेखनीय है कि अन्नू ने पहली शादी अमेरिका निवासी अनुपमा पटेल से हुई थी। फिर दोनों में तलाक हो गया था। उसके बाद अन्नू ने बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री अरुणिता मुखर्जी से दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी के होते हुए भी, उनका पूर्व पत्नी से अफेयर शुरू हुआ, जब यह बात अरुणिता को पता चली, तो उन्होंने भी अन्नू से तलाक ले लिया। दूसरी पत्नी से तलाक के बाद अन्नू ने फिर से अनुपमा से शादी कर ली।

देश को जानने के लिए ट्रैवल करना पसंद करते हैं अन्नू।

बुआजी की भूमिका में नजर आएंगी जयति। टीम जयति

कैमरे के सामने असली उम्र को जीकर ताजगी महसूस कर रही हैं जयति

वैसे तो कलाकारों के अक्सर कभी उम्र से ज्यादा, तो कभी उम्र से कम वाली भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। इस बीच सवाल वहां खड़ा होता है, जब किसी कलाकार को एक बार उम्रदराज भूमिका निभाने के बाद, आगे उसी तरह की भूमिकाओं में टाइपकास्ट कर दिया जाता है। कसौटी जिंदगी की और ससुराल सिमर का धारावाहिकों की अभिनेत्री जयति भाटिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले करीब दस वर्षों से अलग-अलग धारावाहिकों में वह उम्रदराज महिला की भूमिकाएं निभा रही हैं। हालांकि अब जी टीवी के आगामी धारावाहिक जाने अंजाने हम मिले से उनकी शिकायत दूर हो चुकी है। यह शो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी चल रही आटा साटा विवाह प्रथा पर आधारित है। वह इस शो में परिवार की सख्तमिजाज मुखिया शारदा सूर्यवंशी उर्फ बुआजी की खलनायक भूमिका में नजर आएंगी। इससे उत्साहित जयति का कहना है, 'इस शो में मेरी भूमिका अनोखी है। वो बाहर से सख्त नजर आती है, लेकिन अंदर उसमें बहुत सी कमजोरियां भी हैं। खास बात यह है कि मैं करीब 10 साल बाद वास्तविक उम्र के बराबर वाली महिला की भूमिका निभा रही हूं। इस भूमिका में कैमरे के सामने अपनी असली उम्र को जीना मेरे लिए एक ताजगी भरा अहसास है।

सिंघम अगेन में अवनी की भूमिका में होंगी करीना ● मिडे आर्काइव

पात्र मेरे लायक नहीं होगा, तो नहीं करूंगी

फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेताओं को अभिनेत्रियों से ज्यादा मेहनताना मिलने की बात पर काफी समय से बहस होती आ रही है। अभिनेत्री करीना कपूर भी इस पर अपनी आवाज उठा चुकी हैं। हाल ही में जब उनसे एक समारोह के दौरान पूछा गया कि फीस को लेकर समानता कैसे लायी जाए? इस पर करीना ने कहा, 'अब ऐसा समय है कि अगर मुझे लगता है कि यह पात्र मेरे लायक नहीं है, तो मैं उसे नहीं करूंगी। मैं इंतजार करूंगी। खुद को बेहतर बनाऊंगी, ताकि लोगों को अहसास हो कि मैं अपने साथ काम करने वाले अभिनेताओं की तरह ही अपने काम में अच्छी हूं। आज की युवा लड़कियां जब ना कहती हैं, तो उन्हें यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनमें आत्मविश्वास नहीं है। कोई भी ऐसा काम जिसे लेकर अगर लगता है कि वह आपके लिए कहीं से भी कमतर है, तो उसे नहीं करना चाहिए।'

वार 2 में कैमियो नहीं कर रहे हैं शाह रुख खान

हाल ही में आई खबरों में कहा गया था कि यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) की आगामी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म वार 2 में शाह रुख खान अतिथि भूमिका में होंगे। अब फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अयान मुखर्जी निर्देशित इस एक्शन फिल्म में शाह रुख अपने प्रिय जासूस किरदार पठान के रूप में कैमियो नहीं कर रहे हैं। हालांकि वाईआरएफ के प्रमुख आदित्य चोपड़ा अपनी किसी स्पाई यूनिवर्स में शाह रुख और रितिक को साथ लाने का इरादा रखते हैं, लेकिन यह वार 2 में नहीं होगा।

फिल्म किंग को लेकर व्यस्त हैं शाह रुख ● मिडे आर्काइव

रामायण फिल्म में यश ही बनेंगे रावण

निर्देशक नितेश तिवारी की रामायण फिल्म में रावण की भूमिका निभाने को लेकर पहले कन्नड़ अभिनेता यश का नाम सामने आया था। तब यश ने इससे इन्कार कर दिया था। अब आखिरकार यश ने मान लिया है कि फिल्म में वही रावण की भूमिका निभा रहे हैं। यश ने कहा, 'रावण के रोल लिए जब मुझसे पूछा गया तब मैंने कहा था कि अगर इस पात्र को पात्र की तरह ट्रीट किया जाएगा तब, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, तो आज के समय में यह फिल्म नहीं चलेगी। अगर मुझसे पूछा जाए कि रामायण में मैं कोई और पात्र निभाना चाहता हूं, तो मेरा जवाब ना होगा। मेरे लिए केवल रावण ही सबसे रोमांचक चरित्र है।'

नितेश तिवारी की रामायण फिल्म के सहनिर्माता भी हैं यश ● मिडे

कंगुवा जैसा विजुअल पहले नहीं देखा : सुर्या

कंगुवा के ट्रेलर लांच के दौरान दिशा पाटनी, बाबी देओल एवं सुर्या ● प्रेट्र

दो हिस्सों में बनी और रिकार्डतोड़ कमाई करने वाली बाहुबली तथा केजीएफ जैसी पैन इंडिया फिल्मों ने दूसरे फिल्मकारों को भी ऐसे दो हिस्सों में फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया है। तमिल अभिनेता सूर्या और हिंदी फिल्मों के अभिनेता बाबी देओल अभिनीत फिल्म कंगुवा भी कुछ उसी तरह बनाई गई है।

14 नवंबर को प्रदर्शित होने जा रही तमिल फिल्म कंगुवा के प्रदर्शित होने से पहले ही उसकी सीक्वल फिल्म की संकल्पना तैयार की जा चुकी है। यह रहस्योद्घाटन फिल्म के निर्माता ज्ञानवेल राजा ने बुधवार को मुंबई में फिल्म के हिंदी ट्रेलर लांच समारोह के दौरान किया। इस मौके पर सूर्या ने कहा, 'मुंबई मेरे लिए घर की तरह है। मेरे लिए यहां आना और कंगुवा को प्रमोट करना खास है। यह ऐसी फिल्म है, जैसा विजुअल आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं यह सिर्फ स्टंट और वीएफएक्स को लेकर नहीं कह रहा हूं। फिल्म में एक भावनात्मक पहलू भी होना जरूरी है। अगर आप फिल्म से सारे एक्शन और वीएफएक्स को निकाल भी दें, तो इमोशन आपके साथ जाना चाहिए।'

बाबी देओल की यह पहली तमिल फिल्म है, इसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई है। इस मौके पर सूर्या ने बाबी को गले लगाते हुए, उन्हें दूसरी मां से पैदा हुआ अपना एक और भाई बताया। मौके पर फिल्म की अभिनेत्री दिशा पाटनी भी उपस्थित थीं।

मराठी और हिंदी सिनेमा में अभिनय करती हैं सोनाली। इंस्टाग्राम (@sonalikul)

फोटो गिरी और सोनाली को मिल गई दिल चाहता है

कहते हैं, जो किस्मत में लिखा होता है, वो मिलकर ही रहता है। अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी के मामले में यह बात सही भी लगती है। सोनाली एक नए अंदाज में फिल्म दिल चाहता है में नजर आई थीं। हालांकि, इस रोल का आफर उन्हें तस्वीर देखकर मिल गया था। सोनाली एक किस्सा सुनाते हुए कहती हैं कि वह फोटो सेशन का दौर था। एक साड़ी में, दूसरा ग्लैमरस लुक में, तीसरा टाप और जीन्स में, चौथा ब्लैक एंड व्हाइट ऐसी चार फोटो उस दौरान खिंचवाया करते थे और उस पर अपना पेजर नंबर डाल देते थे। किसी प्रोडक्शन आफिस में मेरे फोटो जमीन पर गिर गए थे। वहां पर जोया अख्तर (दिल चाहता है कि कास्टिंग जोया ने की थी) बैठी थीं। उन्होंने फोटो देखकर कहा कि यह किसकी फोटो है। किसी ने कहा कि सोनाली की है। जोया ने कहा कि मैंने उनकी फिल्में देखी हैं, वह ऐसी नहीं दिखती हैं। फिर जोया ने मुझे फोन करके कहा कि एक बार मिलने के लिए आ जाओ। कैजुअल कपड़ों में आना। आफिस में हमने फिल्म के उस सीन की रिहर्सल की, जिसमें मैं फिल्म में सैफ अली खान अभिनीत पात्र के घर में जाती हूं। मैं कभी यह सोचकर नहीं जाती हूं कि मुझे फिल्म मिल जाएगी। कास्ट नहीं भी किया, तो कोई बात नहीं। सही तरीका था कि आडिशन लेंगे, काम पसंद आया तो कास्ट करेंगे। जोया ने मुझे कास्ट किया। वह मेरे काम से खुश थीं।

****